हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

पारंपरिक चिकित्सा

ऐसे वक्त में, जब वैश्विक आबादी का करीब आधा हिस्सा (4.6 अरब लोग) जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम हो, तब पारंपरिक चिकित्सा पर जोर देने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर इसका दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े तमाम पक्षों पर चर्चाएं की गईं। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने न सिर्फ ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, मेक्सिको, नेपाल, श्रीलंका जैसे 16 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, बल्कि आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक आयुष मार्क भी जारी किया गया, जो आयुष उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता के लिए वैश्विक बैंचमार्क का काम करेगा। यह आयोजन भारत सरकार के साथ साझेदारी में किया गया था, जो जन-केंद्रित पारंपरिक चिकित्सा एजेंडे को आकार देने में नई दिल्ली के बढ़ते कदम का संकेत है। आज दुनिया के लगभग 170 देश मानते हैं कि उनकी 40 से 90 फीसदी आबादी किसी-न-किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है। ऐसे में, विश्व मंच पर पारंपरिक चिकित्सा के नेतृत्व के रूप में भारत के स्थापित होने के गहरे निहितार्थ हैं।

भारत अपनी पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के लिए किस कदर प्रयासरत है, इसकी बानगी प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा में भी दिखी, जब मुक्त व्यापार समझौते में पारंपरिक दवाओं को शामिल किया गया। इससे खाड़ी के देशों में आयुष उत्पादों की पहुंच बढ़ सकेगी। गौरतलब है कि भारत का आयुष निर्यात लगातार ऊपर उठ रहा है। विगत फरवरी में राज्यसभा में दी गई जानकारी बताती है कि बीते वर्षों (2021-22 से 2023-24) में आयुष और हर्बल उत्पादों का निर्यात 61.1 करोड़ डॉलर से बढ़कर 65.1 डॉलर तक पहुंच चुका है। इन उत्पादों की अहमियत तब और बढ़ जाती है, जब दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी आर्थिक वजहों से स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर रहने को मजबूर दिखती है। माना यही जाता है कि स्वास्थ्य तंत्र में पारंपरिक चिकित्सा को शामिल करने से हर कोई बिना किसी आर्थिक परेशानी से अपनी स्वास्थ्य जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो सकता है। केंद्र सरकार ने साल 2022 में आयुष निर्यात संवर्द्धन परिषद बनाकर इस मामले में मजबूत कदम भी उठाए हैं। यह परिषद आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा जैसी पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े उत्पादों के निर्यात की देखरेख करती है।

भारत अपनी पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने को किस कदर प्रयासरत है, इसकी बानगी प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा में भी दिखी।

बेशक, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत ने 20 से अधिक देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसी सौगात भी दुनिया को दी है, फिर भी आयुष उत्पादों की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है। कई बार आयुर्वेदिक दवाएं वैज्ञानिक कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी हैं। कोरोना ठीक करने वाली दवाएं तो खास तौर से विवादों में रहीं। खराब गुणवत्ता किस कदर भरोसा तोड़ती है, इसकी झलक भारतीय कफ सिरप विवाद में देखी जा सकती है। भारत को अब भी 'ग्लोबल साउथ का दवाखाना' माना जाता है, पर इस विवाद ने उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। आयुष उत्पादों में मानकीकरण का अभाव, कच्चे माल की गुणवत्ता पर सवाल और प्रभावी नियामक ढांचे की कमी जैसी समस्याएं रही हैं। आयुष मार्क का अनावरण इन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश है। उम्मीद यही है कि इससे वैश्विक भरोसे में वृद्धि होगी और आयुष उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार हो सकेगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 21 दिसम्बर, 1950

पश्चिमी मोर्चा

पूर्व में कोरियाई मोर्चे पर जो कुछ हुआ उसके बाद पश्चिम में अटलांटिक राष्ट्रों द्वारा संयुक्त सैन्य-निर्माण के निर्णय ने तनाव का एक नया अवसर उपस्थित किया है। रूसी अखबार 'प्रवदा' ने इसे यूरोप के भाग्य के लिए एक अशुभ घटना बताया है, जबकि संयुक्त सैन्य का निश्चय करने वाले राष्ट्र विश्व-शांति के लिए इसे एक आवश्यक कदम समझते हैं और शायद ऐसा समझते हैं कि रूस से लोहा लेने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया है। भविष्य ही यह बतायेगा कि इनमें के कौन बात सत्य है और कौन गलत, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस कदम में संघर्ष के नये बीज मौजूद हैं और पूर्व की तरह पश्चिम में भी अकस्मात कोई घटना हो जाये, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।

पश्चिमी यूरोप में संयुक्त सैन्य के रूप में जो पश्चिमी मोर्चा संगठित किया जा रहा है, उसकी तह में रूस से यूरोप का भय मुख्य है। इसीलिए जिस जर्मनी को तानाशाह नाम देकर बुरा कहा जाता था और जिसकी शस्त्र शक्ति एवं उद्योग शक्ति को सहन न करने के लिए ही दो महायुद्ध हुए, उसे निःशस्त्रीकरण के बाद इतनी जल्दी सशस्त्र और उद्योगपूर्ण बनाने की बात सोची जा सकी है। कहते हैं कि पूर्व का- कोरिया का-युद्ध यूरोप के लिए उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि पश्चिम में उसे रूस से भय है और क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की युद्ध-शक्ति क्षीण पड़ चुकी है, इसलिए रूस से उन्हें बहुत भय है। अमरीका इस संकट में उनका सहायक बना है और धन-जन आदि से उनकी मदद कर उन्हें संघर्ष के लिए समर्थ बनाने को कटिबद्ध है। इसीलिए नेतृत्व स्वभावतः उसके हाथ में आ गया है और जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस की शंका-भावनाएं निर्णयों पर कोई असर नहीं डाल पाती।

ब्रूसेल्स में बारह अटलांटिक-राष्ट्रों के जिस सम्मेलन ने पश्चिमी यूरोप के संयुक्त सैन्य मोर्चे का निर्णय किया है, उसकी भूमिका अमरीकन राष्ट्रपति ट्रूमन ने एक वक्तव्य में इस प्रकार बांधी कि ... 'इससे ऐसी मैत्रीपूर्ण संयुक्त यूरोपीय प्रतिरक्षा का जन्म होगा, जो विश्व-शांति के लिए स्वतंत्र देशों को सुदृढ़ बनाने की हमारी व्यापक योजना की पूर्ति की दिशा में एक और कदम होगा।' सम्मेलन ने अमरीका के इस इरादे की पूर्ति ऐसी संयुक्त सेना के निर्माण की बात मानकर कर दी है।

चांदी कीमतों के आसमान में क्यों चढ़ी

एक किलोग्राम चांदी की कीमत एक साल से भी कम समय में एक लाख रुपये से दो लाख रुपये तक पहुंच गई है। चांदी में इतनी तेजी क्यों आई है और कब तक रहेगी ?

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

पिछले कुछ समय से सोना-चांदी लगातार सुर्खियों में हैं। उनमें भी चांदी ने सोने को काफी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, तुलना सीधी नहीं है। लंबी रवायत है कि एक किलो चांदी का दाम करीब-करीब उतना रहता था, जितने में 10 ग्राम सोना मिलता था। अब यह समीकरण काफी हद तक बदल चुका है। बीते शुक्रवार को 10 ग्राम सोने का दाम लगभग 1.36 लाख रुपये था, जबकि एक किलो चांदी का दाम दो लाख के आसपास।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी के दाम का अनुपात लगातार देखा जाता है। वहां यह हिसाब जोड़ा जाता है कि एक औंस सोने में कितने औंस चांदी खरीदी जा सकती है। प्राचीन रोम में यह अनुपात 12 होता था, जबकि आधुनिक विश्व में 80 के आसपास का स्तर संतुलित माना जाता है। मतलब यह कि अगर एक औंस सोने में 80 औंस चांदी आती है, तो तालमेल सही है। अगर इससे ज्यादा आती है, तो चांदी सस्ती है, यानी उसे खरीदना लाभदायक हो सकता है, और अगर 80 से कम है, तो वह महंगी मानी जाएगी। महंगी होने का अर्थ है, आगे चलकर दाम गिर सकते हैं।

कितनी आसान गणना है? कोई भी तय कर सकता है कि चांदी खरीदने का समय है या बेचने का? मगर इस वक्त के भाव देखिए। एक ग्राम सोने में करीब 68 ग्राम चांदी मिलेगी, यानी यह चांदी बेचने या सोना खरीदने का वक्त है। और, इसी गणित से अब चांदी में मंदी भी आ सकती है, पर बात क्या इतनी आसान है?

हुआ यह है कि लंबे समय से सोने-चांदी की जो कदमताल चलती थी, वह अब बिगड़ चुकी है। एक वजह तो यह है कि सोने और चांदी, दोनों में पिछले कुछ समय में जबर्दस्त तेजी आई है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले जो लोग सोने के नाम पर नाक-मुंह सिकोड़ते थे, उन्हें भी अब सोना भरोसेमंद निवेश दिखने लगा है। भारत और चीन जैसे देशों में तो सोना-चांदी खरीदकर जमा करने का शौक पुराना है, मगर अब पश्चिमी देशों के नागरिकों और सरकारों को भी सोने में सुरक्षा दिख रही है। नतीजतन, तमाम देशों के केंद्रीय बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं और साथ ही म्यूचुअल फंडों के पास सोने और चांदी के ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में खूब पैसा आ रहा है। ईटीएफ में पैसा आने का अर्थ है कि उस म्यूचुअल फंड को उतना सोना या चांदी खरीदकर रखना पड़ेगा।

यही दो बड़े स्रोत हैं, जिनके कारण पिछले कुछ समय से सोने-चांदी के दाम बढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बार चांदी की चमक के आगे सब कुछ फीका पड़ गया है। इस साल की शुरुआत से अब तक शेयर बाजार की 50 चुनिंदा कंपनियों के इंडेक्स निफ्टी ने करीब नौ प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसके सामने सोने से करीब 62 प्रतिशत कमाई हुई है। हालांकि, चांदी एकदम रॉकेट की तरह भागी और अभी तक वह 117 प्रतिशत रिटर्न दे चुकी है। यह चमत्कार क्यों और कैसे हुआ, समझना दिलचस्प है?

सोने और चांदी, दोनों को भारत में सजावट के लिए भी खूब इस्तेमाल किया जाता रहा है। गहने और बर्तन की शक्ल में, या फिर सिक्कों, बिस्किट और छड़ के रूप में। इससे अलग भी इन दोनों धातुओं के कुछ महत्वपूर्ण इस्तेमाल दुनिया भर में होते रहे हैं। पहले राजा-महाराजा सिक्के चलाते थे। फिर सोने को सरकार की आर्थिक हैसियत का प्रतीक माना जाता रहा। आज भी माना जाता है, हालांकि अब सरकारें नोट छापने के लिए सोने पर निर्भर नहीं हैं। काफी लंबे समय तक चांदी को सोने की सहायक धातु की तरह देखा जाता था, और शायद इसीलिए उनके दाम भी ताल मिलाकर ऊपर-नीचे होते थे।

सोने की सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत कम तत्वों के साथ इसकी कोई रासायनिक प्रक्रिया संभव है, इसीलिए इस पर मौसम, हवा, पानी का असर नहीं होता और यह बेहद कीमती धातु मानी जाती है। मुद्रा या हैसियत का प्रतीक होने के अलावा इसके दूसरे इस्तेमाल बहुत सीमित हैं। वहीं, चांदी सिर्फ सिक्कों, गहनों या बर्तनों में इस्तेमाल नहीं होती। उसके अनेक औद्योगिक इस्तेमाल हैं। सोने के बाद चांदी ही सबसे अच्छी सुचालक है। ताप ऊर्जा और विद्युत, दोनों के लिए। कीमत के कारण ये दोनों धातुएं आम इस्तेमाल में नहीं हैं। फिर भी चांदी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा और ऑटो उद्योग में इस्तेमाल होती है। इसमें एक और खासियत है कि यह एंटी बैक्टीरियल और गैर-विषाक्त धातु है। इस वजह से इसके औषधीय गुण भी हैं और चांदी के वर्क जैसा भोजन में सीधा इस्तेमाल भी होता है।

इसके इस्तेमाल की सूची लंबी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में यह स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर और टीवी में सर्किट बोर्ड, कनेक्टर व सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होती है। सोलर पैनल के फोटोवोल्टिक सेल में चांदी की अहम भूमिका है। दवाओं के अलावा चिकित्सा उपकरणों और बैटरियों में यह इस्तेमाल होती है। ऑटो उद्योग में यह इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और सेंसर बनाने में लगती है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल उद्योग में रासायनिक समीकरणों को तेज करने के लिए उत्प्रेरक के तौर पर भी चांदी का इस्तेमाल होता है।

जाहिर है, चांदी के उत्पादन या खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा औद्योगिक उत्पादन में जाता है, और सोने की तरह यह बची भी नहीं रहती, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में इसकी खपत हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और सौर ऊर्जा जैसे उद्योगों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि चांदी की औद्योगिक मांग अभी और बढ़ने वाली है। हालंकि, घरेलू खरीद या निवेश की नजर से देखें, तो यह भी साफ है कि चांदी के दाम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। इसलिए, आज चांदी भले ही पहुंच के बाहर लगने लगी हो, पर थोड़ा धीरज और थोड़ी योजना बनाकर अपने इस्तेमाल की चांदी भी धीरे-धीरे खरीदी जा सकती है और इसमें लंबी अवधि का निवेश भी छोटी-छोटी किस्तों में किया जा सकता है।

जिस तरह शेयर बाजार में किसी शेयर के तेजी से बढ़ने के बाद उसमें अपनी बड़ी रकम झोंक देना समझदारी नहीं मानी जाती, वही बात चांदी पर भी लागू होती है। हो सकता है कि अभी कुछ समय और ऐसी ही तेजी बनी रहे, लेकिन इसकी संभावना कम नहीं है कि चांदी की कीमतों में अचानक एक तेज गिरावट भी दिखाई पड़े। तो, अगर किसी को चांदी में निवेश करना है, तो उसे दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

परमाणु बिजली नहीं, अक्षय ऊर्जा में ही भविष्य सुरक्षित

यहां स्कैन करें

पुष्परंजन | वरिष्ठ पत्रकार

नाम लंबा है- 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऐंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।' संक्षेप में- शांति। गुरुवार को संसद में जो सांसद इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें 'शांत' रहने को कहा गया। सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने शांति मंत्र के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण परमाणु परीक्षण को याद किया, तो कुछ ने 18 जुलाई, 2005 को अमेरिका से परमाणु समझौते को रेखांकित किया, जिसकी वजह से परमाणु व्यापार पर तीन दशक से चली आ रही अमेरिकी रोक हटी। फिर भी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और मनमोहन सिंह के दौर में हुआ 123 करार पूर्णतः लागू नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्षतिपूर्ति के ढीले-ढाले प्रावधान थे। परमाणु दायित्व कानूनों में बंधना भारत को मंजूर नहीं था। भारत परमाणु संयत्रों में इस्तेमाल ईंधन पर पूरा हक चाहता था। अमेरिकी दबाव से हम मुक्त न थे। भारतीय संसद से पारित 'शांति' विधेयक अमेरिकी बाधा-बंधन से दूर है।

परमाणु ऊर्जा के पक्ष की बात करें, तो यह कम लागत वाला ऊर्जा स्रोत है। यह विश्वसनीय है और उद्योग के अवसर व रोजगार सृजित करता है। इससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है और इसका ऊर्जा घनत्व भी उच्च है, लेकिन इसकी कमियों पर भी गौर कीजिए। इसमें पानी की अत्यधिक खपत होती है और रेडियोधर्मिता जैसी परमाणु दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी चुनौती परमाणु कचरे का प्रबंधन है। साल 2023 में अपने आखिरी विद्युत केंद्र बंद करने के बावजूद जर्मनी अभी भी 27,000 क्यूबिक मीटर रेडियोएक्टिव कचरे को स्टोर करने के लिए स्थायी जगह ढूंढ़ रहा है। यह स्थिति किसी भी परमाणु ऊर्जा वाले देश की 'स्टोरेज' व 'ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी' के बारे में जरूरी सवाल उठाती है। जर्मनी में तो नाभिकीय कचरे के निष्पादन के लिए 23.6 बिलियन यूरो का एक कोष बना हुआ है। क्या भारत ऐसा कर पाएगा?

इसमें पानी की अत्यधिक खपत होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी चुनौती तो परमाणु कचरे का प्रबंधन है।

परमाणु संयंत्र में दुर्घटना और उसका विनाशकारी असर एक बड़ा सवाल है। हम ऐसा कुतर्क नहीं कर सकते कि सड़क दुर्घटना के डर से गाड़ी चलाना छोड़ दें क्या? हम भोपाल गैस कांड के साक्षी हैं। हम फुकुशिमा, चेर्नोबिल और पेंसिल्वेनिया की थ्री माइल आइलैंड जैसी भयावह घटनाओं से आंख मूंद नहीं सकते। 'शांति विधेयक' का कमजोर पक्ष यह है कि अगर किसी परमाणु बिजली ऑपरेटर की लापरवाही से विनाश होता है, तो प्रभावित समुदाय कोर्ट में शिकायत नहीं करवा सकता।

भारत में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा किया जाता है। इस समय भारत के सात राज्यों में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 6,780 मेगावाट है। भारत अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का मात्र 3.1 प्रतिशत परमाणु संयंत्रों से हासिल करता है। सरकार ने हाल में जानकारी दी है कि 2031-32 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। यहां सवाल है कि जर्मनी जैसा विकसित देश क्यों परमाणु ऊर्जा से दूर हो गया? मार्च 2025 में जर्मनी की पर्यावरण मंत्री स्टेफी लेम्के ने इसकी वजह दोहराई थी कि 'परमाणु ऊर्जा के खतरे आखिर में बेकाबू होते हैं, इसीलिए इसे हटाने से हमारा देश ज्यादा सुरक्षित व परमाणु कचरे से बचता है।'

परमाणु ऊर्जा संयंत्र 31 देशों में हैं। अमेरिका में 94 परमाणु बिजलीघर हैं। बावजूद इसके, वहां परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है, जबकि प्राकृतिक गैस का हिस्सा 40 फीसदी से अधिक है, इसके बाद अक्षय ऊर्जा (23 प्रतिशत) व कोयले (16 फीसदी) का स्थान रहा है। फ्रांस में 55 और चीन में 58 परमाणु बिजलीघर हैं। भारत, दुनिया का चौथा पवन ऊर्जा निर्माता व तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। हम अपने संसाधनों के दोहन में जुट जाएं, तो नंबर एक बन सकते हैं। 2047 तक भारत का लक्ष्य बिजली क्षमता को 2,100 गीगावाट करना है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल 100 गीगावाट है। यदि यह सही है, तो अन्य स्रोतों से उत्पादित 2,000 गीगावाट विद्युत के आगे कुछ भी नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, फिलहाल भारत की 50.07 प्रतिशत बिजली अक्षय ऊर्जा से आता है। इससे जान-माल, प्रदूषण और रेडिएशन का कोई जोखिम नहीं है। हमें इसी दिशा में बढ़ना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सतत बदलाव ही जीवन

सर्दियों की एक सुबह मैं लुधियाना में ओशो ध्यान शिविर करवा रही थी। ध्यान था जिंदगी में होने वाले सतत बदलाव को देखना और स्वीकार करना। बदलाव को महसूस करने के लिए मैंने एक खूबसूरत गुलाब का बगीचा चुना। अलग-अलग रंग और शेड्स के गुलाब- गुलाबी से बैंगनी और पीले से सफेद तक। बड़े और छोटे, सभी आकार के। वे जिंदगी के अलग-अलग पड़ाव पर थे, यानी कुछ कलियां थीं, कुछ आधे खिले हुए, कुछ पूरे खिले हुए और कुछ मुरझाए हुए। पत्तियां भी उम्र में अलग-अलग थीं, हरी कोंपलों से लेकर सूखी भूरी-पीली तक। ध्यान करने वाले लोग घूम रहे थे, गुलाब की झाड़ी के हर उस पड़ाव को ध्यान से देख रहे थे, जो जीवन की धारा में बह रहा था। प्रकृति में बदलाव को समझना बहुत आसान है, क्योंकि सभी पड़ाव एक साथ आपकी आंखों के सामने होते हैं।

गुलाबों के बदलाव को समझने के बाद लोग आस-पास टहल रहे लोगों को देखने लगे। क्या वे भी उन्हीं पड़ावों से नहीं गुजर रहे थे? सभी उम्र के लोग : जवान, अधेड़, बूढ़े, मौत की दहलीज पर... और एक दिन वे नहीं रहेंगे! हर इंसान के सामने रुककर, एक-दूसरे की आंखों में देखकर यह अटल सच जोर से उभरकर आया। क्या उनमें और गुलाबों में कोई फर्क था? सभी लोग गुलाब की झाड़ियों के बीच बैठ गए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जिंदगी की उन अलग-अलग स्थितियों को देखा, जिनसे वे गुजरे थे- बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा; अपने शरीर, विचारों, भावनाओं, सपनों में बदलाव, और अब जिंदगी के जिस पड़ाव पर वे थे, उन सबको फिर से देखने के लिए कहा। एक दिन वे भी अपने साथी यात्रियों, गुलाबों की तरह मुरझा जाएंगे। कुछ बंद पलकों से आंसू बहने लगे। भीतर से कुछ बोध हुआ। बोध के साथ एक गहरी स्वीकृति आती है कि अगर बदलाव ही जिंदगी का नियम है, तो इसे क्यों न स्वीकार करें?

ध्यान के बाद एक अधेड़ उम्र के सिख कारोबारी मुझसे मिलने आए। उनकी आंखों में अभी भी उस गहरे अनुभव की नमी थी। उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था। मैं बदलाव का विरोध करता था- अपनी फैक्टरी में, घर में। मुझे लगता था कि बदलाव मेरे फैसलों का अपमान है, जैसे यह मेरी हार हो और इसी वजह से मैंने अपने चारों ओर एक सख्त खोल बना लिया था। लोग मुझसे दूर रहते थे। आज पहली बार जब मैंने बाहर और अंदर बदलाव की धारा को देखा, तो मैं अंदर तक हिल गया। मुझे एहसास हुआ कि बदलाव से लड़कर मैं जिंदगी से लड़ रहा था।'

एक बार जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि जीने का मतलब ही बदलना है, तो हम बदलाव करने में बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और खुद को जिंदगी की धारा में बहने देंगे।

एक बार जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि जीने का मतलब ही बदलना है, तो हम बदलाव करने में रिलैक्स महसूस करेंगे और खुद को जिंदगी की धारा में बहने देंगे।

अमृत साधना

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल विजेता

आज भी दुनिया के लगभग 14 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं और 24 करोड़ शिक्षा से वंचित हैं। करोड़ों बच्चे युद्धों से पीड़ित व भुखमरी के शिकार हैं। उनके बचपन को बचाकर पहली पंक्ति में बैठाने का संघर्ष जारी रहेगा और हम इसे हासिल करके रहेंगे।

गणित के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा भारत

हमारे देश में हर दिन कुछ न कुछ विशेष होता है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी, तब से हर साल महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। यह वह महान दिन है, जो गणित के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभाओं को याद करने का हमें अवसर देता है।

इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य गणित के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और छात्रों को गणित में करियर बनाने के लिए उत्साहित करना है। वाकई, देश की युवा पीढ़ी में गणित सीखने के प्रति उत्साह, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ा है। उनमें यह भावना विकसित करने के लिए कई तरह की पहल भी की जा रही हैं। यहां तक कि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से शिक्षकों व छात्रों के क्षमता-निर्माण, गणित के लिए शिक्षण सामग्रियों के विकास, उत्पादन व वितरण और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा किया जाना जरूरी भी है, क्योंकि प्राचीन काल में हम गणित के सर्वोच्च रहे हैं। पांचवीं सदी के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट से लेकर ब्रह्मगुप्त, भास्कर से लेकर आधुनिक युग में श्रीनिवास रामानुजन, पीसी महालनोबिस, कल्यामपुडी राधाकृष्ण राव, डॉ. कारपेकर, सत्येंद्रनाथ बोस, शकुंतला देवी, नरेंद्र करमकर आदि अनेक गणितज्ञों ने देश और दुनिया में नाम कमाया है। आर्यभट्ट जहां खगोलीय मामलों के विशेषज्ञ थे, तो वहीं ब्रह्मगुप्त ने छठी शताब्दी में शून्य की खोज कर दुनिया को महान अवदान दिया। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रतिभा से वेदों में वर्णित नक्षत्रों की गति के आधार पर वेदकालीन सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया। शकुंतला देवी 'मानव कंप्यूटर' के रूप में ख्यात महिला गणितज्ञ थीं। अपनी असाधारण बुद्धि से उन्होंने गणित में कई विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए।

आज भी गणित को लेकर हमारा रुझान कम नहीं हुआ है। बच्चों और किशोरों में गणित को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है कि गणित में और रुचि बढ़ाने के लिए खास दिवस मानने की परंपरा शुरू हुई है। इसका भी असर पड़ेगा। आज गणित विषय पठन-पाठन में ही नहीं, करियर के लिहाज से भी बेहद अहम विषय माना लगा है। यहां तक कि एआई में भी, जिसकी चौतरफा चर्चा है, गणना का काफी इस्तेमाल होता है। ऐसे में, राष्ट्रीय गणित दिवस का महत्व हमारे लिए और बढ़ जाता है। इससे प्रेरणा लेकर हमारे युवा गणित की दुनिया के शिखर को प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करेंगे।

सुधांशु कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
राष्ट्रीय गणित दिवस

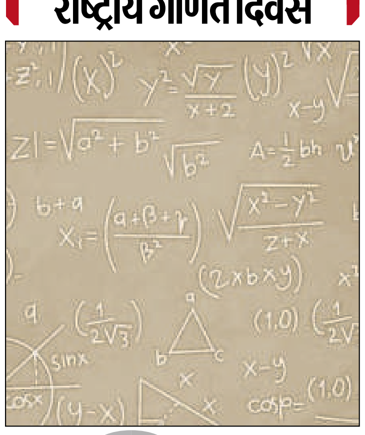

बच्चे अब इस विषय से कतराने लगे हैं

आज की युवा पीढ़ी के समक्ष उपस्थित अनेक समस्याओं में एक बड़ी समस्या उसके गणितीय दिमाग का विकास बाधित होना है। युवा पीढ़ी में अकादमिक-बौद्धिक पिछड़ेपन की यह समस्या वैश्विक चिंता का विषय है, जिसके मुख्य कारण शिक्षा-प्रणाली में बुनियादी अवधारणाओं- स्थानीय मान, जोड़-घटाव पर ध्यान न देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण और तरीकों में कमी, गणित के प्रति छात्रों में डर व अरुचि है, जिससे वे कैलकुलेटर पर निर्भर रहने लगे हैं। इस कारण बच्चों और युवाओं की बुनियादी समझ कम हो रही है। कई छात्रों को स्थानीय मान और बुनियादी गणितीय समस्या हल करने में कठिनाई होती है, जो उच्च कक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा है। गणित को अक्सर उबाऊ और मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों की रुचि कम होती है और वे रटने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि समझने पर।

छात्रों में गणित का डर अब आम समस्या है, जो उनके प्रदर्शन और विषय में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती है। छात्र अब मामूली गणनाओं के लिए भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका बुनियादी कौशल कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर कोरोना लॉकडाउन का पड़ा प्रभाव अब तक पूरी तरह से दूर नहीं हो सका है। इससे बच्चों व गणित, दोनों का नुकसान हुआ है। असल में, अपने देश में ग्रामीण-शहरी और लैंगिक असमानताएं गणितीय कौशल में अंतर पैदा करती हैं, नतीजतन कई राज्यों में छात्र खराब प्रदर्शन करने लगे हैं।

इस समस्या से तुरंत निपटने की जरूरत है। इसके लिए गणित को मजेदार और प्रासंगिक बनाकर छात्रों में रुचि पैदा करना जरूरी है, जैसे 'मैथ लैब' को शुरू करना। इसके अलावा, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी तरह, बचपन की शिक्षा और देखभाल कार्यक्रमों में निवेश कर गणितीय दक्षता बढ़ाने वाली बुनियादी शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है। सरकारों और समाज को मिलकर शिक्षा प्रणाली में जरूरी नीतिगत बदलाव के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए शिक्षाविदों, सरकारों और माता-पिता के सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता है, ताकि युवा पीढ़ी गणित के क्षेत्र में अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सके। गणित के क्षेत्र में शून्य, दशमलव प्रणाली और बीजगणित जैसे क्षेत्रों में हम स्कूल स्तर पर पिछड़ रहे हैं, जबकि इन मामले में हमारा वैश्विक योगदान किसी से छिपा नहीं है। इस समस्या को गंभीर मानते हुए तत्काल इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, अन्यथा गणित में समृद्ध इतिहास रखने वाले भारत के लिए यह संकट त्रासद हो सकता है।

अमन कुमार, छात्र

बेचैनी को दिखाएं बाहर का रास्ता

जब हालात पकड़ से बाहर होने लगते हैं, तो आगे-पीछे की कई बेचैनियां सिर उठा लेती हैं। दिमाग में बजने वाली डर की आवाजों को शांत करना मुश्किल हो जाता है और दवाएं स्थायी राहत नहीं देतीं। ध्यान रखें कि डर तनाव का एक रूप है, जिसे आप चाहें तो नियमित अभ्यास से दूर कर सकते हैं।

दीपक चोपड़ा
भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक व मोटिवेशनल गुरु। कई किताबें लिख चुके हैं।

अनिश्चितताएं जितनी अधिक होती हैं, उतनी ही हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। मसलन, जब कोई प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो भय केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने नहीं आता। ऐसे किसी भी समय में आगे-पीछे की कई बेचैनियां सक्रिय हो जाती हैं। बेचैन करने वाली स्थितियां जितनी अधिक भयावह होती हैं, उतना ही भीतर उठने वाली डर की आवाजों को शांत करना मुश्किल हो जाता है।

हमें खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है। रिलैक्स करने वाली दवाओं को छोड़ दें, तो आमतौर पर हम अपनी चिंताओं से कैसे निपटते हैं? मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसके दो तरीके होते हैं- समस्या से मुंह मोड़ना और ध्यान दूसरी जगह लगाना। हालांकि, अपनी बेचैनी को नजरंदाज करके या अपना ध्यान कहीं ओर लगाकर हमें कुछ देर के लिए ही राहत मिलती है। क्या फिर बेचैनी के पलों में भीतर से उठने वाली डर की आवाजों को शांत करने का कोई स्थायी और प्रभावी तरीका है? क्या इस अनचाहे मेहमान को विदा किया जा सकता है?

इसका जवाब है हमारी चेतना। ऐसे सचेत निर्णय लिए जाएं कि भय स्वयं ही सिमट जाए। जहां चेतना जाग्रत होती है, वहां भय नहीं होता। डर हमारी विकास यात्रा का हिस्सा है, जो 'लड़ो या भागो' की प्रतिक्रिया में निहित है। यह घात लगाए बैठा रहता है और मौका देखते ही हावी होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के समय होता था, लेकिन बीते दस हजार वर्षों में हमारे मस्तिष्क का बहुत विकास हुआ है। यह एक ऐसी शक्ति है, जो हमें यह अहसास दिलाती है कि हमारे पास सोचने, महसूस करने, रचनात्मक होने और चुनाव करने की असीमित क्षमता है। विकास यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमने खुद को कई पुराने डरों से आजाद किया है। हम इस तरह विकसित हुए हैं कि खुद को अपने डरों से मुक्त कर सकें। इसके लिए हमें बस जागरूकता का रास्ता चुनना होगा। हमें सचेत होना होगा। जैसे-जैसे हम जागरूक होते हैं, हर कदम पर हमारा डर कम होता जाता है।

बेचैनी के पलों में सही चुनाव कर सकें, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि डर हमें किस तरह प्रभावित कर रहा है? डर तनाव का एक रूप है और आप जब चाहें इस छोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको स्वयं की और एक आरामदायक जगह की जरूरत है- जहां आप लेट सकें जैसे कि फर्श या बाहर घास पर।

विश्राम का अभ्यास

पीठ के बल लेट जाएं। अपने पैरों के बीच लगभग डेढ़ फीट (18 इंच) की दूरी रखें और हाथों को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हों। अपनी आंखें बंद करें। इस स्थिति में सहज हो जाएं और सामान्य ढंग से सांस लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। महसूस करें कि सांस लेते समय पेट कैसे ऊपर-नीचे हो रहा है। गहरी राहत भरी लंबी सांस छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली होने दें। महसूस करें कि आप गहरे आराम में जा रहे हैं। इसे 5 से 10 मिनट तक जारी रखें और इस शांति में डूब जाएं।

इस अवस्था से बाहर आने में जल्दबाजी न करें और न ही तुरंत काम में लग जाएं। धीरे से हथेलियों को खोलें और बंद करें, फिर अपनी आंखें खोलें। बिना किसी जल्दबाजी के धीरे से उठें। भीतर की शांति और नियंत्रण को महसूस करें। इस अहसास को याद रखें। दिन में कभी भी घबराहट होने पर इसी शांति को दोबारा महसूस करने की कोशिश करें। 'शांत और सजग' रहने की यह अवस्था ही वह आधार है, जिससे आप बिना किसी मेहनत के अपने भीतर वहां तक पहुंच सकते हैं, जहां कोई डर नहीं है।

आंतरिक तृप्ति को दें अहमियत

अब चर्चा को थोड़ा और विस्तार देते हैं। आधुनिक जीवन बाहरी सुविधाओं और समृद्धि को तो महत्व देता है, पर आंतरिक संतुष्टि को कम। हालांकि, एक कड़वा सच यह है कि अधिक धन, शक्ति और पद-प्रतिष्ठा आंतरिक संतोष नहीं देते। आंतरिक तृप्ति एक अलग मार्ग पर मिलती है। प्राचीन भारत में जीवन के दो मार्ग बताए गए थे- सुख का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। पूर्व और पश्चिम की हर ज्ञान परंपरा 'जाग्रति' पर आधारित है, जिसका व्यावहारिक अर्थ है- अचेतनता से ऊपर उठकर सचेत व्यवहार अपनाना।

इस तरह आप अपने स्वयं के विकास में सहभागी बनते हैं, और इसी से ज्ञान जाग्रत होता है। समय के साथ, जब भीतर ज्ञान और विवेक बढ़ता है, तो भय की आवाजें शांत होने लगती हैं। पहले पहले कहा था कि आपको यह समझना है कि डर आप पर किस तरह असर करता है? यह समझने के बाद अब आप इसे छोड़ना भी सीख रहे हैं। यह जानते हैं कि इसे खुद पर हावी होने से रोका जा सकता है। आप भले इसे ज्ञान न समझें, पर यही ज्ञान है। आंतरिक ज्ञान का हर क्षण केवल अधिक सचेत और जागरूक होने का क्षण है। डर एक अचेतन शक्ति है, जो हमारी जागरूकता को हरा नहीं सकती।

मैं एक बार फिर शवासन के प्रभावी असर पर जोर देना चाहता हूं। तनाव से भरी दुनिया में 5 से 10 मिनट लेकर तनाव को बाहर छोड़ना और विश्राम को आत्मसात करना भले ही छोटा कदम लगे, लेकिन ऐसे छोटे कदम आपकी मौजूदा स्थिति पर आपका नियंत्रण बढ़ाते हैं, जिससे डर और अनिश्चितता की पकड़ ढीली पड़ जाती है।

www.deepakchopra.com

काम की बात

जीवन को सटीक दिशा देते पांच मूल्य

भले ही अपने फैसलों को हम नियति या परिस्थितियों का नतीजा मान लें, पर मनोविज्ञान कहता है कि इसके पीछे एक गहरी शक्ति काम करती है, वह हैं हमारे मूल्य। एक हालिया अध्ययन बताता है कि हम क्या चुनते हैं और क्यों चुनते हैं?

मानव जीवन केवल आदतों और परिस्थितियों से नहीं चलता। इनमें उन मूल्यों का योगदान होता है, जिन्हें हम महत्व देते हैं। हाल के वर्षों तक मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए थे कि मानव जीवन के मूल मूल्य कौन-कौन से हैं। अलग-अलग शोधकर्ताओं ने अलग मूल्यों को चुना था, ऐसे में कुछ खास मूल्यों पर सहमति बनाना कठिन हो जाता था।

साइकोलॉजी टुडे में मनोविज्ञानी जॉन. ए. जॉनसन के लेख में मूल मूल्यों के बारे में समझाते विल्कोवस्की डीमैरिआनो एंड पेक के नए अध्ययन का जिक्र किया गया है। इस अध्ययन में मूल मूल्यों को पांच व्यापक आयामों में बांटा है, जो इस प्रकार हैं-

1 व्यक्तिगत दक्षता

यह मूल्य व्यक्ति के आत्म विकास, निजी कौशल को निखारने और अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास करने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने से जुड़ा है।

2 समानता व न्याय

सबके लिए समानता और न्याय के समर्थक लोग बराबरी, निष्पक्षता और सबके कल्याण को महत्व देते हैं। ऐसे मूल्यों से जुड़े लोग सबकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं।

3 सामाजिक प्रतिष्ठा

इस मूल मूल्य का असर व्यक्ति की सामाजिक हैसियत, प्रभाव, शक्ति व आर्थिक सफलता, जीवनसाथी और दोस्तों के चुनाव पर पड़ता है। यह मूल्य व्यक्ति के बहिर्मुखी व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। ऐसे लोग नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत पहचान बढ़ाने वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं।

4 संस्कृति और परंपरा

यह मूल मूल्य परंपरा, स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर बल देता है। धर्म, संस्कृति और स्थापित नियमों के प्रति सम्मान इस मूल्य की पहचान है। ऐसे लोग आमतौर पर धर्म और राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं।

5 आपसी संबंध

इस मूल्य का केंद्र बिंदु गहरे और गर्मजोशी भरे संबंधों से जुड़ा है। अपने संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव, ईमानदारी, सहयोग और भरोसे को महत्व देते हैं।

जॉनसन के अनुसार, 'यह शोध इस बात पर भी महत्व देता है कि हर व्यक्ति एक जैसे मूल्यों को समान महत्व नहीं देता। यही विविधता समाज को आगे बढ़ाती है। कुछ लोग परंपराओं को सहेजते हैं, तो कुछ परिवर्तन लाते हैं; कुछ संबंधों में निवेश करते हैं, तो कुछ निजी विकास को महत्व देते हैं। जीवन में हम सभी मूल्यों को एक साथ पूरा नहीं कर सकते। समय और ऊर्जा सीमित हैं। हम जब अपने प्रमुख मूल्यों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तो हमारे लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है और जीवन अधिक संतोषजनक बनता है।'

एकदा

दड़बे की मुर्गी

एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, 'गुरुजी हमें खुश रहने के लिए क्या चाहिए?'

गुरुजी ने पूछा, 'तुम क्या सोचते हो?' शिष्य ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति की मूल जरूरतें पूरी हो रही हों, जैसे खाना, आवास, रोजगार और सुरक्षा, तो वो व्यक्ति खुश रहेगा।'

गुरुजी शिष्य को एक दरवाजे के पास लेकर गए। वहां मुर्गी का दड़बा था। सैकड़ों मुर्गियां और चूजे बड़े पिंजड़ों में कैद थे।

गुरुजी ने पूछा, 'क्या इन मुर्गियों को खाना मिलता है? क्या इनके पास घर है? क्या यहां ये कुत्ते-बिल्लियों से सुरक्षित हैं?

शिष्य ने कहा, 'हां।'

गुरुजी ने पूछा, 'क्या इनके पास कोई काम है?' शिष्य ने कहा, 'हां, ये यहां अंडे देती हैं।'

गुरुजी ने पूछा, 'क्या यहां ये खुश हैं?' शिष्य मुर्गियों को करीब से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि कैसे पता किया जाए कि कोई मुर्गी खुश है भी या नहीं? गुरुजी फिर उसे अपने साथ आगे ले गए। वहां पास ही एक मैदान में ढेर सारी8 मुर्गियां और चूजे थे। वे ढूंढ़-ढूंढ़ कर दाना चुग रहे थे और खेल-कूद रहे थे। 'क्या ये मुर्गियां खुश दिख रही हैं?', गुरुजी ने पूछा।

शिष्य ने देखा, यहां मुर्गियां प्राकृतिक तरीके से रह रही हैं। वह दबी आवाज में बोला, 'हां।'

गुरुजी बोले, 'तुम्हारी परिभाषा के अनुसार दड़बे वाली मुर्गियां ज्यादा खुश होनी चाहिए थी?'

गुरुजी बोले या तो हम दड़बे की मुर्गियों की तरह एक पिंजड़े में रहकर जी सकते हैं। एक ऐसा जीवन जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। या फिर मैदान की उन मुर्गियों की तरह जोखिम उठाकर एक आजाद जीवन जीते हुए अपनी संभावनाएं टटोल सकते हैं। तुमने खुश रहने के बारे में पूछा था न? तो यही मेरा जवाब है।

विविध

अच्छी सेहत के लिए सही दिनचर्या की खोज

हमें अपना दिन कैसे बिताना चाहिए या एक अच्छी दिनचर्या कैसी होती है, इस बारे में आए दिन हमें दूसरों से कई सलाह मिलती हैं। उनमें से कुछ सही होती हैं, तो कुछ वैज्ञानिक आधार से कोसो दूर। हाल में हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से जुड़ीं डॉ. तृषा पसरीचा ने विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एक अच्छी दिनचर्या के फायदे बताते हुए कुछ बातों पर जोर दिया है। आइए जानें...

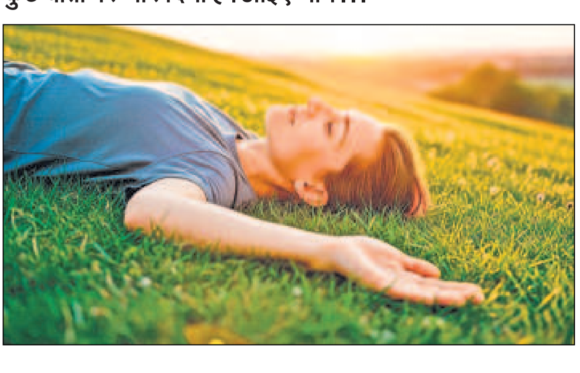

अच्छी सेहत एक दिन के प्रयास का नतीजा नहीं होती। एक नियमित और अनुशासित दिनचर्या ही हमें तन और मन से स्वस्थ रखती है। वॉशिंगटन पोस्ट के अपने कॉलम में डॉ. तृषा पसरीचा विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्वस्थ दिनचर्या की सलाह देती हैं। उनके अनुसार, 'हमारे अधिकतम प्रयास सुबह के समय किए जाने चाहिए। यह समय हमारी सेहत और कार्यक्षमता पर सबसे अधिक असर डालता है। साथ ही हमें रात में भी एक निश्चित रुटीन का पालन करना चाहिए।' डॉ. तृषा प्रमुख रूप से इन बातों पर जोर देती हैं-

सुबह सबसे पहले

सुबह के समय सूरज की धूप और कुदरती रोशनी में कुछ समय जरूर बिताएं। व्यायाम करें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। सुबह के समय प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें खाएं। हो सकता है कि सुबह के समय आपके ऊपर कई तरह के कामों की जिम्मेदारियां हों और आप हर सुबह यह रूटीन न अपना सकें। पर जितना अधिक संभव हो ऐसा करने की कोशिश करें।

दोपहर का वक्त

भोजन के बाद शरीर में आने वाले भारीपन को कुछ देर तेज गति से चलकर हल्का करें। कैफीन युक्त चीजें न लें और उसके बाद कम एकाग्रता वाले सामान्य काम करें।

जब दिन ढल जाए

शाम को जल्दी खाएं और अपनी रफ्तार कम करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि दिन में 8 से 10 घंटे के समय में आप खाएं-पिएं, इससे पाचन भी दुरुस्त रहता है और आप अगली सुबह की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाते हैं।

जब हो जाए रात

धूम्रपान, अल्कोहल और कड़े श्रम के व्यायाम करने से बचें। अपने दिन को समापन की ओर ले जाते हुए रात के समय अपने विचारों को आराम देने की ओर बढ़ें। अध्ययनों के अनुसार ऐसे में ध्यान व माइंडफुलनेस व्यायाम करना अच्छा रहता है। यहां तक कि केवल हर रोज सोने से पांच मिनट पहले ऐसा करना मन को शांत करता है। अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। शोधकर्ताओं के अनुसार आमतौर पर रात के समय रोशनी कम करना या बिस्तर की साफ-सफाई का ध्यान रखने वाली सलाहों की तुलना में रात में कुछ देर ध्यान करना अच्छी नींद लाने में मदद करता है।

जागने के कुछ समय बाद

यह समय काम की उत्पादकता और एकाग्रता के लिहाज से सबसे बेहतर है। इस समय ऐसे काम करें, जिसमें सबसे अधिक फोकस की जरूरत होती है। अगर आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं, तो पचास मिनट काम करें और दस मिनट का छोटा-सा ब्रेक लें। शोध के अनुसार दस मिनट या उससे कम का छोटा ब्रेक आपकी काम की क्षमता बढ़ा सकता है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार के लिए विदेश यात्रा लाभप्रद रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।

वृष : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। पिता का साथ मिलेगा। भागदौड़ अधिक रहेगी।

मिथुन : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी, परंतु कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

कर्क : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी, परंतु कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

सिंह : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं।

कन्या : कारोबार कार्यों में व्यस्तता रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। सुस्वादु खान-पान में रुचि बढ़ सकती है। कारोबार में लाभ बढ़ेगा।

तुला : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी, परंतु वाणी के प्रभाव से कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक : आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है।

धनु : आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। कारोबार के लिए परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध व वाद-विवाद से बचें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

मीन : मन शांत रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

22 दिसंबर, सोमवार, **शक संवत्**: 01 पौष (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग**: 08 पौष मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम**: 01 रज्जब, 1447, **विक्रमी संवत्** : पौष शुक्ल द्वितीया तिथि प्रातः 10.52 बजे तक पश्चात तृतीया तिथि, ध्रुव योग सायं 04.41 मिनट तक पश्चात व्याघात योग, कौलव करण, चंद्रमा धनु राशि प्रातः 10.07 मिनट तक उपरांत मकर राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। शक पौष प्रारंभ। रज्जब (मु.) मास प्रारंभ।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

वास्तु अनुसार घर में पोछा लगाने के क्या नियम होते हैं? -हेमा झा, बेगूसराय

- पोछा गुरुवार के दिन कभी नहीं लगानना चाहिए।
- एकादशी के दिन भी पोछा लगाना ठीक नहीं होता। पोछा सदैव सूर्योदय के बाद ही लगाना शुभ होता है। दोपहर 12 बजे के बाद एवं सूर्यास्त के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए।
- पोछा लगाने के लिए नया कपड़ा ही होना चाहिए। कभी भी इस्तेमाल किए हुए तौलिये या अन्य किसी वस्त्र से पोछा नहीं लगाना चाहिए।
- यदि टॉयलेट में पोछा लगाते हैं, तो घर का और टॉयलेट का पोछा एक नहीं होना चाहिए।

वर्ग पहेली : 8186

बाएं से दाएं
1. परिवार का; परिवार से संबंधित (5)
5. जल का प्रवाह; पानी की धारा (4)
6. खरोंचना; खुरचना (4)
7. नरम करना; पिघलाना (3)
8. थूक; एक प्रकार का वृक्ष और उसका निर्यास (2)
9. कोण; धार; पतला सिरा; पैना किनारा (2)
10. कुटैव; नशा; बुरी आदत; लत; विषयों के प्रति आसक्ति (3)
12. ऐसा काम करना जिससे कोई भटके; गलत रास्ता बताना; पथभ्रष्ट करना; भुलावा देना (4)
13. अच्छे लक्षणों वाला; सुयोग्य (4)
14. अचेत; बेहोश; संज्ञाहीन; सुधहीन (5)

ऊपर से नीचे
2. वामपंथियों का समूह; वाममार्गी; साम्यवादियों का दल (4)
3. अंतर मिटवाना; सटवाना; सम्मिलित करवाना; परिचय करवाना; मिलन करवाना; मिलावट करवाना (4)
4. पराभूत करना; परास्त करना; हराना (4,3)
6. कुठार का आघात होना; कुल्हाड़ी से आघात होना (5,2)
7. आकाश; नभ (3)
10. कार्य; आचरण; बरताव; लेन-देन; प्रथा; रिवाज; रीति (4)
11. उंगलियां फोड़ना; तोड़ना; भंजित करना; अलग करना; दूर करना (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8185

1 का	2 म	त	3 मा	म	क	4 र	ना	■
■	ह	■	ली	■	■	वा	■	5 अ
6 ठो	क	ना	■	7 अ	प	ना	प	न
■	दा	■	■	दा	■	हो	■	म
8 त	र	9 का	री	■	10 दा	ना	11 दे	ना
र	■	र्य	■	12 भा	■	■	र	■
13 ल	ट	क	जा	ना	■	14 क	स	ना
ता	■	ला	■	■	15 भ्र	■	वे	■
■	16 अ	प	ना	का	म	क	र	ना

सुडोकू : 8168

* मध्यम

			3	1		6		
				6	5		2	
	1						8	
5		9				3		
7			5		4			2
		8				7		6
	8						7	
	4		1	5				
		3		9	7			

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8167

9	1	8	6	4	5	2	7	3
2	4	5	7	9	3	1	6	8
7	3	6	8	2	1	9	5	4
6	2	7	4	1	9	8	3	5
8	9	3	5	7	6	4	2	1
4	5	1	3	8	2	6	9	7
3	6	4	2	5	8	7	1	9
5	8	9	1	6	7	3	4	2
1	7	2	9	3	4	5	8	6

कल्पमेधा

दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन खुद के कीर्तिमान को तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है।

- चंद्रशेखर आजाद

पारदर्शिता का तकाजा

बिहार की तर्ज पर अब अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के नाम इस सूची से हटाए जाने की आशंका है। चुनाव आयोग की ओर से हाल में जारी मसविदा सूची में तमिलनाडु में 97.40 लाख और गुजरात में 73.73 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें समय पर आवश्यक दस्तावेज दर्ज न कराना भी शामिल है। अंतिम सूची जारी होने से पहले ऐसे लोगों को अपनी आपत्तियां और दावे पेश करने का मौका दिया जाएगा और संभव है कि कई मतदाताओं के नाम फिर से जुड़ जाएंगे। मगर मसविदा सूची के आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो उससे यही लगता है कि नाम दर्ज कराने के आखिरी अवसर के बाद भी बड़ी संख्या में लोग इस सूची से बाहर रह जाएंगे। सवाल है कि अगर इन लोगों के पास मतदान की पात्रता नही है, तो पहले इनका नाम क्यों और कैसे मतदाता सूची में था?

बिहार में एसआइआर की प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले पहचान पत्र के मसले पर विवाद पैदा हुआ था। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को नागरिकता का पहचान पत्र मानने से इनकार दिया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आधार को पहचान पत्र के दस्तावेजों में शामिल किया गया। बिहार में भी मसविदा सूची में करीब पैंसठ लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। हालांकि बाद में उसमें कई नाम जोड़े गए, इसके बावजूद अंतिम सूची में करीब सैंतालीस लाख लोग मतदाता सूची से बाहर हो गए। शीर्ष अदालत ने इस पर सूची से हटाए गए लोगों का कारण सहित विस्तृत ब्योरा मांगा। यही स्थिति अब अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है। इस सबके बीच विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को भी कसौटी पर कसा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो मसविदा सूची से हटाए गए लोगों का सत्तारूढ़ दल ने अपने स्तर पर सत्यापन करने की मुहिम शुरू कर दी है। ऐसे में यह सवाल महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर चुनाव आयोग पर आम लोगों और राजनीतिक दलों का भरोसा क्यों डगमगाने लगा है?

इसमें दोराय नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में समय-समय पर संशोधन कर अपात्र लोगों या मृतकों के नाम हटाए जाने जरूरी है। मगर इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पैमाना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि न तो किसी के मन में कोई आशंका रहे और न ही कहीं से कोई सवाल उठने की गुंजाइश बचे। यह चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी को कोई आशंका हो, तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। ऐसा न होने पर आयोग की विश्वसनीयता पर अंगुली उठना स्वाभाविक है। एक अहम सवाल यह भी है कि जिन लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, उनका भविष्य क्या होगा? क्या वे देश के नागरिक बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है और जब उनका यही अधिकार खत्म हो जाएगा, तो उनकी नागरिकता पर भी देर-सवेर सवाल उठेगा ही। यह चिंता इसलिए गंभीर है, क्योंकि देश भर में गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से बाहर होने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में हो सकती है। चुनाव आयोग और सरकार को इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा।

जिम्मेदारी के बजाय

यह किसी भी सार्वजनिक जगह पर एक सामान्य अपेक्षा है कि लोग नागरिक बोध और संवेदनशीलता का परिचय दें और दूसरों का भी खयाल रखें। मगर हवाईअड्डे जैसी जगह पर कोई पायलट अगर खुद ही सुरक्षा जांच पंक्ति तोड़ने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर बेकाबू और हिंसक हो जाए, तो यह एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। गौरतलब है कि दिल्ली हवाईअड्डे पर छोटा बच्चा साथ होने की वजह से एक यात्री और उसके परिवार को कर्मचारियों के लिए निर्धारित सुरक्षा जांच गेट से जाने को कहा गया था। मगर वहां कुछ कर्मचारी आगे निकलने की होड़ में थे। खबर के मुताबिक, जब यात्री ने ऐसा करने पर टोका तो एक व्यक्ति ने उससे बदतमीजी की और उस पर हमला कर दिया। विडंबना यह है कि अपना आपा खोकर यात्री पर हमला करने वाला व्यक्ति पायलट है, जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। सवाल है कि सुरक्षा-व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील मानी जाने वाली हवाईअड्डे जैसी जगह पर ऐसा कैसे संभव हुआ।

यह सही है कि घटना के वक्त हमलावर हो जाने वाला पायलट उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन उससे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद की जाती है। अगर विमान में कभी बेहद विषम और उथल-पुथल से भरे हालात पैदा हो जाएं, तो ऐसे में भी ड्यूटी पर मौजूद पायलट को शांति और धीरज से काम लेना पड़ता है, परेशान यात्रियों की बातों को सुनना और उन्हें समझाना होता है। संभवतः यह पक्ष पायलट बनने के प्रशिक्षण में भी शामिल होगा। हैरानी की बात है कि एक मामूली बात पर ऐसा व्यक्ति नाहक ही हिंसक हो गया, जो खुद पायलट है और विमान उड़ाने जैसी बेहद संवेदनशील जिम्मेदारी भी निभाता है। घटना सामने आने के बाद संबंधित पायलट को ड्यूटी से हटा देने की खबर आई। मगर इस पहलू पर भी विचार करने की जरूरत है कि पायलट और विमानन कंपनियों से जुड़े कर्मचारी अव्यवस्था के बीच क्या किसी तरह के दबाव और तनाव से गुजर रहे हैं और ऐसे में कई बार आपा भी खो रहे हैं! हाल के दिनों में विमानों की उड़ान में जिस तरह की व्यापक अव्यवस्था देखी गई, उसमें यह वाकया एक और नकारात्मक संदेश देता है।

नई योजना और रोजगार की चुनौतियां

नए सर्वेक्षणों के मुताबिक, इस कृषि प्रधान देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या मनरेगा का बदला रूप 'वीबी-जी राम जी' इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगा।

सुरेश सेठ

भारत तरक्की कर रहा है, आंकड़ों से अर्शशास्त्री यही बताते हैं। निस्संदेह भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र होंगे। उस समय हर आदमी यथोचित रोजगार के साथ अच्छा भोजन करेगा, अच्छा पहनेगा और खुशहाली के शिखर पर होगा। यह है सपना। ऐसा अगर लोग स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के बाद भी सोचते हैं, तो कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। पिछले दिनों कहा गया कि हम देश से बेरोजगारी मिटा देंगे। बेरोजगारी की भूख अनुकंपा के सस्ते राशन से मिटा दी जाएगी। मगर युवा पीढ़ी जो इस देश की आधी आबादी है, वह काम चाहती है। यह कड़वी सच्चाई है कि बड़ी संख्या में युवा आज भी बेरोजगार हैं। नए सर्वेक्षणों ने बताया है कि इस कृषि प्रधान देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या मनरेगा का बदला रूप 'वीबी-जी राम जी' इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि गांवों में योजना का नया कलेवर नहीं, काम चाहिए।

अब जरूरत है कि देश में नागरिकों को काम के उचित अवसर मिलें। यूपीए सरकार के समय सबसे अच्छी योजना मनरेगा को ही बताया जाता था। यह फरवरी 2006 में लागू हुई थी। इसमें आवेदन करने पर पंद्रह दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य होता था। आंकड़े बताते हैं कि इस पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2014 से राजग सरकार के कार्यकाल में भी इस पर 7.8 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हालांकि इसमें केवल सौ दिन का काम दिया जाता है। कई बार तो मजदूरों को औसत पचास दिन ही काम मिला। फिर भी मनरेगा वर्ष 2014 से अब तक आठ करोड़ लोगों को ही रोजगार दे पाई।

अब केंद्र सरकार ने संसद में नया ग्रामीण रोजगार विधेयक पारित किया है। ग्रामीणों को रोजगार के लिए 20 साल के बाद योजना को एक नया कलेवर दिया गया है। इसकी शुरुआत नाम बदलने से हुई। इस योजना का नया नाम है- विकसित भारत-जी राम जी। जबकि इससे पहले इसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता था। कुल जमा ये कि नई योजना ने रूप बदला है। पहले सौ दिन काम मिलता था, लेकिन अब 125 दिन काम मिलेगा, लेकिन दिहाड़ी वही रहेगी। पहले इस योजना पर सौ फीसद पैसा केंद्र सरकार खर्च करती थी। अब इसमें 60 फीसद योगदान केंद्र देगा। जबकि 40 फीसद राज्य सरकारें देंगी। पहले इस योजना में आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर काम मिलता था। मगर अब काम न मिलने पर राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। मनरेगा ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए था। फिलहाल 'वीबी-जी राम जी' को विकसित भारत का हिस्सा बना कर देखा जा रहा है।

नई योजना की डिजिटल निगरानी होगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें बनेंगीं। संचालन समितियां बनेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाली योजनाओं को 'पीएम-विकास गतिशक्ति' से जोड़ देंगे। अब सवाल

है कि इस परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? संसद में विधेयक पारित भी हो गया है। इससे पहले इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष की जम कर बहस हुई। सत्तापक्ष का कहना था कि मनरेगा दिशाहीन था और इसमें ऐसा था कि पहले गड्ढे खोदो, फिर उन्हें भर दो। मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवार के

> विपक्ष के अपने तर्क हैं कि क्या ऐसे ही प्रावधान मनरेगा में नहीं किए जा सकते थे! क्या उसे निश्चित उद्देश्यों के साथ लक्ष्यबद्ध नहीं किया जा सकता था? फिर जरूरी तो यह था कि महंगाई की दर को देखते हुए कार्यबल के पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी जाती। वृद्धि तो की नहीं, केवल काम के 25 दिन बढ़ा दिए। राज्य सरकारें तो पहले ही अपने खाली खजाने का रोना रो रही हैं। उनका यह कहना है कि ग्रामीण विकास कोष से लेकर जीएसटी तक में से उन्हें उनका उचित भुगतान नहीं मिलता। अब उन पर इस योजना के योगदान का 40 फीसद भार भी डाल दिया गया है।

एक सदस्य को सौ दिन काम देकर मेहनताना देना। अब यह नई योजना दिशाहीन नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार का मत है कि गांवों में परिवर्तन आ गया है। भुखमरी कम हो गई है, ग्रामीण बेरोजगारी इतनी बड़ी चुनौती नहीं रही। मगर सच से कैसे इनकार किया जा सकता है? चुनौती तो अब भी है! सरकार का यह भी कहना है कि ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना बदल रही है। वहां डिजिटल भुगतान पहुंच गया है। बैंक पहुंच गए हैं। बेहतर संपर्क है, लेकिन मनरेगा में फर्जीवाड़ा हो रहा था। योजना की राशि का दुरुपयोग हो रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब जैसे राज्यों में इतनी कम दिहाड़ी पर मजदूर काम करने के लिए राजी नहीं। इसलिए वहां फर्जी आंकड़ों से भुगतान हो रहे हैं।

विशेषज्ञ कहते हैं कि वर्ष 2024-25 में इस योजना में 194 करोड़ रुपए का घपला हुआ और केवल 7.6 फीसद ग्रामीण परिवार ही सौ दिन का रोजगार पा सके, लेकिन अब माहौल बदल जाएगा। फर्जीवाड़ा रुकेगा। अब यह चुस्त-दुरुस्त और नए कलेवर वाली योजना बनेगी, जिस पर बाकायदा काम होगा। श्रम बल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाएगा। यह यथार्थवादी योजना होगी। जब गांवों में फसल बिजाई और फसल कटाई का भरपूर आंशिक योगदान मिलने की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो यह योजना समांतर रोजगार देना स्थगित कर देगी। बाद में लक्ष्यबद्ध तरीके से कार्यबल का इस्तेमाल किया जाएगा जो ग्रामीण जीवन का कायाकल्प कर देगा।

दूसरी ओर विपक्ष के अपने तर्क हैं कि क्या यही नया कलेवर मनरेगा को नहीं दिया जा सकता था? क्या उसे निश्चित उद्देश्यों के साथ लक्ष्यबद्ध नहीं किया जा सकता था। फिर जरूरी तो यह था कि महंगाई की दर देखते हुए कार्यबल के पारिश्रमिक में वृद्धि कर दी जाती। वृद्धि तो की नहीं, केवल काम के 25 दिन बढ़ा दिए। राज्य सरकारें तो पहले ही अपने खाली खजाने का रोना रो रही हैं। उनका यह कहना है कि ग्रामीण विकास कोष से लेकर जीएसटी तक में से उन्हें उनका उचित भुगतान नहीं मिलता। मुआवजा नहीं मिलता। अब उन पर इस योजना के योगदान का 40 फीसद भार भी डाल दिया गया है। राज्य सरकारें तो अधिक आर्थिक सहायता की उम्मीद केंद्र से कर रही थीं, लेकिन यहां एक और दायित्व उन पर आ गया कि अगर ग्रामीण विकास को तेजी देनी है, तो आगे बढ़ो और केंद्र सरकार के साथ योगदान करो। यह भी कहा गया कि पंजाब ही नहीं, बल्कि बंगाल में भी इस कोष का भारी दुरुपयोग हुआ। इसलिए नया विधेयक लाया गया।

यह योजना क्या काम करेगी, इसे स्पष्ट किया गया है। यह मूलभूत बुनियादी ढांचा बनाएगी। आजीविका के लिए पूंजी का निर्माण करेगी और प्रदूषण से निपटने का कार्य करेगी। यह निराशाजनक है कि इस पर गंभीर चर्चा नहीं हुई। इसका नाम बदलने पर ही बहस होती रही। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है! मगर अब तो लगता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। सच तो यही है कि साम, दाम, दंड, भेद के साथ अपना नाम रोशन करने की यह जिद है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। सत्ता की यह नई संस्कृति बनती जा रही है। ग्रामीण रोजगार संबंधी इस योजना को सार्थक बनाना है, तो उसके लिए आर्थिक आबंटन भी बढ़ना चाहिए। नई योजना में केंद्र सरकार ने आर्थिक आबंटन तो बढ़ाया नहीं, अलबत्ता राज्य सरकारों पर बोझ जरूर डाल दिया गया है। अब जिस प्रकार संवादहीनता गैर-भाजपा सरकारों और केंद्र के बीच चलती है, या जहां 'डबल इंजन' सरकारें नहीं हैं, वहां इस नई योजना का भविष्य क्या होगा, यह विचारणीय है। क्या योजना का नाम बदलने भर से सार्थकता साबित होगी?

आत्मसम्मान की रोशनी

महिमा सामंत

दुनिया मेरे आगे

जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभाता है- पुत्र, मित्र, शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक। इन सभी पहचानों के बीच एक पहचान ऐसी है जो सबसे स्थायी है- स्वयं की। आत्मसम्मान उसी पहचान का मूल है। यह वह मौन शक्ति है जो व्यक्ति को परिस्थितियों के आगे झुकने नहीं देती, बल्कि उन्हें आकार देने की प्रेरणा देती है। आत्मसम्मान वह अदृश्य दीपक है, जो भीतर जलता है और अंधकार के समय दिशा दिखाता है। इसक अर्थ है स्वयं को स्वीकारना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और जीवन के प्रति गरिमा का भाव बनाए रखना। यह अहंकार नहीं, बल्कि आत्म-स्वीकार की परिपक्वता है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करता है, जबकि आत्मसम्मान स्वयं को गरिमा से ऊंचा उठाता है। यह उस व्यक्ति की पहचान है जो कहता है कि 'मैं जैसा हूं, वैसा ही पर्याप्त हूं।'

कभी-कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं, जो बार-बार हमें चोट पहुंचाते हैं, अपमानित करते हैं, और फिर एक साधारण 'सारी' या 'माफी' कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। वे वही गलती दोहराते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा की तरह माफ करते रहेंगे। पर हर 'सारी' रिश्ते को नहीं जोड़ती। क्षमा तभी अर्थपूर्ण होती है, जब सामने वाला अपनी गलती की गहराई सच में समझे। आत्मसम्मान का अर्थ कठोर होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्षमा वहीं तक उचित है, जहां हमारी गरिमा सुरक्षित रहे। जब किसी की गलती इतनी गहरी हो कि उसे भूलना खुद के साथ अन्याय लगे, तब दूरी बनाना गुस्सा नहीं, अपनी मानसिक शांति और स्वाभिमान की रक्षा करना होता है। दूसरों को माफ करना अच्छा है, पर खुद को भूल जाना कभी नहीं। इसी तरह, जब कार्यस्थल पर हमारी मेहनत को बार-बार नजरअंदाज किया जाता है, हमारी योग्यता को महत्त्व नहीं दिया जाता या हमारा योगदान किसी और के नाम कर दिया जाता है, तो चुप रहकर सब लंबे समय तक सहना विनम्रता नहीं, बल्कि अपने मूल्य को कम आंकना है। वहां अपनी काबिलियत के लिए शांत, पर दृढ़ आवाज उठाना ही सच का पक्ष और स्वाभिमान की रक्षा बन जाता है।

रिश्तों में भी कई बार हम अनजाने में ऐसी आदत पाल लेते हैं कि हर बहस के बाद 'माफी' हम ही बोलते हैं, चाहे गलती सामने वाले की हो। हम सोचते हैं कि इससे रिश्ता बचेगा, पर धीरे-धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। इस चक्र को रोकना, अपनी बात, अपने दर्द और सम्मान को तवज्जो देना दरअसल अपनी कद्र करना है। कुछ स्थितियों में गलत व्यवहार इतना गहरा होता है कि शब्द बेअसर हो जाते हैं। वहां चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब बन जाती है।

जब कोई व्यक्ति हमें सिर्फ तब याद करे, जब उसे हमारी जरूरत हो, काम निकालना हो, सहानुभूति चाहिए हो, या अकेलापन बांटना हो, पर हमारी जरूरत के समय वह हमेशा गायब मिले, तो ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना भी स्वाभिमान का ही हिस्सा है। खुद को हर समय उपलब्ध न कराना, अपनी ऊर्जा और भावनाओं की रक्षा करना, और यह समझना कि हर कोई हमारे दिल तक पहुंचने का अधिकार नहीं रखता, यही आत्मसम्मान की असली शुरुआत है। सच तो यही है कि स्वाभिमान वहीं बचता है, जहां हम खुद को खोने से पहले रुकना और अपनी गरिमा को प्राथमिकता देना सीखते हैं।

आत्मसम्मान केवल दूसरों से व्यवहार का विषय नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति दृष्टिकोण का विषय है। जब कोई व्यक्ति गलती करता है और बिना बहाने के 'हां, मुझसे भूल हुई' कहने की हिम्मत रखता है, वह आत्मसम्मानित होता है। जब कोई अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, चाहे सामने लाभ ही क्यों न हो, वह आत्मसम्मान जी रहा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मसम्मान केवल बड़े निर्णयों में दिखता है, पर सच्चाई यह है कि यह हमारी रोजमर्रा की आदतों में बसता है। जब कोई विद्यार्थी नकल से इनकार करता है, कोई महिला अपने अधिकार के लिए बोलती है, या कोई व्यक्ति अपमानित होकर भी शांत और संयमित रहता है, तो ये सभी आत्मसम्मान के जीवंत उदाहरण हैं।

> हमारे जीवन का सबसे बड़ा संतोष यह नहीं कि दुनिया हमें कितना सम्मान देती है, बल्कि यह है कि हम स्वयं को कितना सम्मान देते हैं। आत्म-सम्मान कोई पदक नहीं है, जिसे कोई और दे। यह आत्म-निर्णय है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी गरिमा से समझौता नहीं करूंगा।

आज सोशल मीडिया और तुलना की दुनिया में लोग अपनी कीमत 'लाइक' और 'फालोअर्स' से मापने लगे हैं। पर आत्मसम्मान हमें सिखाता है कि पहचान भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है, वही दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। आत्मसम्मान हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। यह चिंता, असुरक्षा और आत्मसंदेह से बचाता है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं, तब हम दुनिया की अपेक्षाओं में उलझते नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। यह एक ऐसा मौन कवच है, जो हमें हर असमानता, उपेक्षा और अपमान से बचाता है।

जीवन का सबसे बड़ा संतोष यह नहीं कि दुनिया हमें कितना सम्मान देती है, बल्कि यह है कि हम स्वयं को कितना सम्मान देते हैं। आत्मसम्मान कोई पदक नहीं है, जिसे कोई और दे। यह आत्म-निर्णय है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपनी गरिमा से समझौता नहीं करूंगा। कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है, जहां चुप रहना आसान होता है, पर स्वयं का सम्मान बचाना कठिन। ऐसे क्षणों में याद रखना चाहिए कि दुनिया की नजरों में हार जाना भी स्वीकार्य है, अगर अपने भीतर हम विजेता हैं। आत्मसम्मान वही रोशनी है जो हमें हर अंधेरे से पार ले जाती है। जब हम खुद का सम्मान करना सीख लेते हैं, तब हमें किसी और से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो अपने भीतर की गरिमा को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है।

जानलेवा प्रदूषण

सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर तक पहुंच जाना अब वार्षिक त्रासदी बन चुका है। प्रदूषण नियंत्रण के मामले में प्रशासनिक सुस्ती पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी पूरी तरह जायज है, क्योंकि यह समस्या तात्कालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और गंभीर बन चुकी है। वायु प्रदूषण की चुनौती अब केवल दिल्ली और एनसीआर तक सीमित नहीं रही। पूरे उत्तर भारत में यह व्यापक संकट का रूप ले चुकी है। प्रदूषण के प्रमुख कारणों में धुआं और धूल सबसे आगे है। यातायात जाम के कारण वाहनों की धीमी गति से निकलने वाला जहरीला धुआं वातावरण को विषाक्त बना रहा है। वहीं लकड़ी, कोयला और उपलों के जलने से निकलने वाला धुआं भी हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। निर्माण कार्यों से उड़ती धूल इस संकट को और गहरा कर रही है। वायु प्रदूषण राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। इसके समाधान के लिए केवल प्रशासनिक कदम पर्याप्त नहीं होंगे। हर नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यवहार से ही इस संकट से निपटा जा सकता है।

- हिमांशु शेखर, गयाजी

साझेपन का संदेश

संयुक्त परिवार और माता-पिता के साथ रहने में जो आनंद है, वह अकेले या एकाकी जीवन बिताने में नहीं। 'प्यू रिसर्च' की रपट के अनुसार अमेरिका मे 1971 में जहां सिर्फ सात फीसद घरों में दो या दो से अधिक पीढ़ियां साथ रहती थीं, वहीं 2021 में यह आंकड़ा अठारह फीसद हो गया। अकेले ब्रिटेन में वर्ष 2011 से 2021 तक के बीच साथ रहने वाले परिवारों की संख्या सात लाख तक बढ़ी। संयुक्त परिवार में बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सदस्यों में आपसी प्रेम से हिम्मत बनी रहती है। वर्तमान दौर में एकल होते परिवार पर सवाल उठने लगे हैं। एक साथ रहने से परिवार में बच्चों का समुचित विकास तो होता ही है, साथ ही वे परंपरा और संस्कृति भी सीखते और जानते हैं। संवेदना और मानवता का पाठ भी बच्चे संयुक्त परिवार में पढ़ते हैं। इस बदलते दौर में 54 फीसद लोग संयुक्त परिवार को फायदेमंद मानते हैं। संयुक्त परिवार की एकजुटता सकारात्मक संदेश देती है।

- योगेश जोशी, बड़वाह

संकट में साख

हाल ही में दिल्ली की एक अदालत द्वारा नैशनल हेरल्ड मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करना इस संस्था की साख पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। यह वही एजंसी है जिसे देश की आर्थिक सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। अदालत की यह टिप्पणी कि ईडी का आरोपपत्र किसी 'मूल अपराध' की प्राथमिकी के बजाय एक व्यक्ति की निजी शिकायत पर आधारित है, यह संकेत देती है कि एजंसी शायद साक्ष्यों से अधिक 'निर्देशों' पर चल रही है। संवैधानिक संस्थाएं, जिनका स्वरूप निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए, अक्सर सत्ता के औजार के रूप में काम करती नजर आती हैं। इसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। ईडी और अन्य केंद्रीय एजंसियों की सक्रियता उन राज्यों या नेताओं के प्रति अचानक बढ़ जाती है जो सत्ता पक्ष के विरोधी होते हैं। यह स्थिति एक ऐसी धारणा पैदा करती है कि ये एजंसियां केवल विपक्ष को ही भ्रष्ट मानती हैं, जबकि सत्ता पक्ष के करीब जाते ही नेताओं के दाग धुल जाते हैं।

- प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

खतरे में अरावली

हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से भी पहले भूगर्भीय हलचलों से बनी विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। नया निर्देश है कि अरावली पर्वतमाला के 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को पहाड़ नहीं माना जाएगा। इससे अब अरावली की नब्बे फीसद पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में है। इस निर्देश के लागू होने के बाद 692 किलोमीटर लंबाई में गुजरात से लेकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैली यह विशाल श्रृंखला धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खो देगी। आने वाले समय में बेरोकटोक वनों की कटाई, अतिक्रमण और खनन पर्यावरण के लिए विनाशकारी साबित होगा। अरावली एक दीवार की तरह है जो थार के मरुस्थल को बढ़ने से रोकने का काम कर रही है। जब यह दीवार नष्ट होने लगेगी, तो रेगिस्तान धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ाने लगेगा। जल भंडार सूखने लगेंगे।

- संजय डागा, इंदौर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

खबर कोना

एशियाई फुटबाल परिसंघ एएफसी नेशंस लीग शुरू करेगा

कुआलालंपुर, 21 दिसंबर (भाषा)।

एशियाई फुटबाल परिसंघ (एएफसी) ने अपने सदस्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए रविवार को एएफसी नेशंस लीग शुरू करने की घोषणा की। यह कदम यूईएफए द्वारा 2018 में नेशंस लीग से प्रभावित होकर उठाया गया है, जिसमें यूरोप की राष्ट्रीय टीमों को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है और वे फीफा की निर्धारित विंडो में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हैं। यह घोषणा अफ्रीकी फुटबाल परिसंघ द्वारा 2029 में इसी तरह का टूर्नामेंट शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद आई है। एएफसी से जारी बयान के मुताबिक, 'राष्ट्रीय टीमों की सीमित उपलब्धता, बढ़ती परिचालन लागत और लाजिस्टिक संबंधी जटिलताओं के कारण फीफा अंतरराष्ट्रीय मैच विंडो का प्रभावी उपयोग करना लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय मैचों का महत्त्व कम होता जा रहा है।

इटली : अल्ता बदिया में अल्पाइन स्की पुरुष विश्व कप जीतने के बाद जश्न मनाते आस्ट्रिया के मार्को श्वार्ज।

एम्बापे ने रेकार्ड 59वां गोल करके रोनाल्डो की बराबरी की

बार्सिलोना, 21 दिसंबर (एपी)।

स्टार स्ट्राइकर काइलियन एम्बापे ने अपने 27वें जन्मदिन पर साल 2025 में रियाल मैड्रिड के लिए अपना 59वां गोल करके एक साल में सबसे अधिक गोल करने के क्लब रेकार्ड की बराबरी की, जो कि अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर दर्ज था। फ्रांस के स्ट्राइकर एम्बापे के लिए यह उपलब्धि हासिल करना लगभग असंभव रहा था, क्योंकि रियाल मैड्रिड का यह इस साल का आखिरी मैच था। एम्बापे ने मैच खत्म होने से चार मिनट पहले पेनल्टी किक को गोल में बदलकर रोनाल्डो की बराबरी की जिससे रियाल मैड्रिड ने सेविला को 2–0 से हराया। रोनाल्डो ने 2013 में यह रेकार्ड बनाया था।

न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज के सामने 462 रन का लक्ष्य रखा

माउंट माउंगानुई, 21 दिसंबर (एपी)।

कप्तान टाम लैथम और डेवोन कानवे ने लगातार दूसरी पारी में शतक जड़कर टेस्ट इतिहास में अपना नाम विशिष्ट सूची में शामिल किया, जिससे न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज के सामने तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में जीत के लिए 462 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। लैथम ने 101 रन बनाए जबकि कानवे ने 100 रन की पारी खेली। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की थी जिससे न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 306 रन पर समाप्त घोषित की। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 575 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने 420 रन बनाए थे। उसने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 43 रन बनाए हैं।

पुदुचेरी : 'फिट इंडिया संडे आन साइकिल' रैली का नेतृत्व करते केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया व पुदुचेरी के गृह मंत्री अरुमुगम नमस्सिवयम।

समारोह

फिट इंडिया : साइकिल से अभियान की वर्षगांठ पर 15 हजार प्रतिभागी शामिल

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

आयोजन

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को पुदुचेरी में 'फिट इंडिया संडे आन साइकिल' पहल की पहली वर्षगांठ के समारोह का नेतृत्व किया जिसमें 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और राक बीच पर साइकिल चलाई। भारत के पूर्व हाकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश और टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल भी इस साइकिल रैली का हिस्सा बने। इस रैली में स्कूली बच्चों, नमो साइक्लिंग क्लब के सदस्यों और पुदुचेरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया।

खेल मंत्रालय के अनुसार, 'फिट इंडिया संडेज आन साइकिल' पहल पिछले एक साल में देश भर के 700 से अधिक जिलों में दो लाख स्थानों पर आयोजित की गई जिसमें वर्ष भर में 20 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। मांडविया ने कहा, 'जब हमने एक साल पहले इस पहल की शुरुआत की थी, तब इसका आयोजन केवल पांच स्थानों पर लगभग 500 प्रतिभागियों के साथ किया जाता था। अब प्रत्येक रविवार को देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों पर इसका आयोजन होता है जिसमें 10 लाख से अधिक नागरिक भाग लेते हैं।'

इस कार्यक्रम में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी, विधानसभा अध्यक्ष आर सेल्वम और पुडुचेरी के गृह मंत्री ए नमसिवयम भी उपस्थित थे। कैलाशनाथन ने कहा, 'भावनगर में मांडविया के गांव में केवल 4000 लोग रहते हैं। वहां यातायात के लिए हर कोई साइकिल का उपयोग करता है, कोई अन्य वाहन का नहीं। हम यह महसूस नहीं करते कि जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव सामूहिक रूप से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के मामले में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।'

भारत को फाइनल में हराकर पाकिस्तान बना अंडर-19 एशिया कप चैंपियन

दुबई, 21 दिसंबर (भाषा)।

क्रिकेट

समीर मिन्हास की तूफानी बल्लेबाजी के बाद तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान ने रविवार को अंडर-19 एकदिवसीय एशिया कप के एकतरफा फाइनल में भारत को 191 रन के बड़े अंतर से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने इस तरह अपना दूसरा अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता। पिछले कुछ समय से चले आ रहे रिवाज को आगे बढ़ते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच के बाद एक-दूसरे का अभिवादन (हाथ मिलाने) करने से परहेज किया।

सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास की 113 गेंद में 17 चौके और नौ छक्के की मदद से 172 रन बनाए।

टास जीतकर भारत ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास की 113 गेंद में 17 चौके और नौ छक्के की मदद से बनाए 172 रन के बूते पाकिस्तान ने आठ विकेट पर 347 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद भारत को 26.2 ओवर में 156 रन पर आउट कर दिया। अली रजा (42 रन पर चार विकेट), मोहम्मद सय्याम (38 रन पर दो विकेट) और अब्दुल सुभान (29 रन पर दो विकेट) की पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों तिकड़ी ने आठ विकेट साझा कर भारत के बल्लेबाजों को क्रीज पर समय बिताने का मौका नहीं दिया। कप्तान आयुष म्हात्रे (दो) के जल्दी आउट होने के बावजूद भारत की पारी की शुरुआत धमाकेदार रही। वैभव सूर्यवंशी (16) ने रजा की गेंदों पर दो छक्के और एक चौका लगाकर पहले ओवर में 21 रन बनाए।

आरोन जार्ज (16) ने भी अच्छी शुरुआत की और चौथे ओवर में सय्याम की गेंदों पर लगातार तीन चौके लगाए, जिससे टीम चार ओवर के अंदर ही 49 रन तक पहुंच गई। मैच का रुख चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जार्ज के आउट होते ही बदल गया। सय्याम की शाट गेंद पर जार्ज ने पुल शाट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में लहराकर मोहम्मद शयान के हाथों में चली गई। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर सूर्यवंशी के आउट होने से भारत को बड़ा झटका लगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने रजा की गेंद पर जोरदार शाट खेलने की कोशिश की, लेकिन अतिरिक्त उछाल के कारण गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर जहूर हमजा के दस्तानों में जा गिरी। रजा और पाकिस्तान के क्षेत्ररक्षकों ने इस विकेट का जमकर जश्न मनाया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ियों और सूर्यवंशी के बीच कुछ कहा-सुनी भी हुई, लेकिन वह निराश मन से मैदान से बाहर चले गए।

वैभव सूर्यवंशी (16) ने रजा की गेंदों पर दो छक्के और एक चौका लगाकर पहले ओवर में 21 रन बनाए। सूर्यवंशी के आउट होने से भारत को बड़ा झटका लगा। उन्होंने रजा की गेंद पर जोरदार शाट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर जहूर हमजा के दस्तानों में जा गिरी।

आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में 82 रन से हराया

कंगारुओं ने दो टेस्ट शेष रहते हुए एशेज बरकरार रखी

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

टेस्ट शृंखला

तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें और अंतिम दिन रविवार को एडिलेड में आखिरी चार विकेटों में से तीन विकेट लेकर इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कंगारुओं ने 82 रन से जीत दर्ज करके दो टेस्ट शेष रहते हुए एशेज बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड की पूरी टीम लंच के बाद 352 रन पर आउट हो गई। पांचवें दिन की सुबह इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 207 रन से आगे बढ़ाई। आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का लक्ष्य दिया था। पांच मैचों की इस शृंखला में यह इंग्लैंड की लगातार तीसरी हार है और इसी के साथ उसकी अप्रत्याशित जीत दर्ज करके विश्व रेकार्ड बनाने और एशेज में बने रहने की उम्मीदों पर तुषारापात हो गया।

इंग्लैंड ने आखिरी बार आस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जनवरी 2011 में जीता था, जिसके बाद से 5,462 दिन बीत चुके हैं। आस्ट्रेलिया ने उसके बाद से अपनी धरती पर 5–0, 4–0, 4–0 से शृंखला जीती है और अब वह 3–0 से आगे है। आस्ट्रेलिया ने पर्थ और ब्रिस्बेन में पहले दो टेस्ट मैच आठ विकेट के समान अंतर से जीते थे। इन दोनों मैच में तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की थी और उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। हालांकि, तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंज की पहली पारी में उन्हें केवल एक ही विकेट मिला था, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने एकबार फिर आस्ट्रेलिया की जीत में अहम भूमिका निभाई।

स्टार्क ने सुबह के सत्र में एकमात्र विकेट लिया। उन्होंने जेमी स्मिथ को 60 रन पर आउट किया। इंग्लैंड ने पहले सत्र में 102 रन जोड़कर अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। इंग्लैंड की शानदार वापसी ने आखिरी दिन दोपहर के भोजन तक एशेज का रोमांच बनाए रखा। इंग्लैंड ने लंच तक सात विकेट पर 309 रन बनाए थे। तब आस्ट्रेलिया को एडिलेड में ही ट्राफी जीतने के लिए तीन विकेट और इंग्लैंड को पांच मैचों की शृंखला में बने रहने के लिए 126 रन की जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बताया कि उन्हें सुबह के सत्र में ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम एक और बड़ी जीत हासिल करने के लिए तैयार है और उन्हें रेकार्ड स्कोर बनाने का पूरा भरोसा था।

इंग्लैंड ने आखिरी बार आस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जनवरी 2011 में जीता था, जिसके बाद से 5,462 दिन बीत चुके हैं। आस्ट्रेलिया ने उसके बाद से अपनी धरती पर 5–0, 4–0, 4–0 से शृंखला जीती है और अब वह 3–0 से आगे है। आस्ट्रेलिया ने पर्थ और ब्रिस्बेन में पहले दो टेस्ट मैच आठ विकेट के समान अंतर से जीते थे।

आस्ट्रेलिया में कुछ हासिल करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते : कमिंस

एशेज शृंखला में 3–0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद आस्ट्रेलयि के कप्तान पैट कमिंस ने सभी खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कर दिखाया। आस्ट्रेलिया में आप कुछ भी चीज को हासिल करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है और मुझे खुशी है कि हमारे सभी खिलाड़ियों ने मेहनत की। मैंने नहीं सोचा था कि मैच इतना करीबी हो जाएगा, लेकिन मैं परिणाम से बहुत खुश हूं।'

भारत ने श्रीलंका को आठ विकेट से हराया

जेमिमा ने खेली अर्धशतकीय पारी, भारत ने शृंखला में बनाई 1-0 की बढ़त

विशाखापत्तनम, 21 दिसंबर (भाषा)।

पहला टी20 मैच

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जेमिमा रोड्रिग्स (नाबाद 69 रन) की आकर्षक अर्धशतकीय पारी से रविवार को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 32 गेंद रहते आठ विकेट से हराकर पांच मैच की शृंखला में 1–0 की बढ़त बना ली। भारतीय गेंदबाजों ने ओस के बावजूद श्रीलंका को छह विकेट पर 121 के स्कोर पर ही रोक दिया।

ओस के उम्मीद से पहले असर दिखाने के बावजूद मेहमान टीम की बल्लेबाज ढीली गेंदों का पूरा फायदा नहीं उठा सकीं। फिर भारतीय टीम ने यह लक्ष्य 14.4 ओवर में दो विकेट पर 122 रन बनाकर हासिल कर लिया जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स ने 44 गेंद की नाबाद पारी में 10 चौके लगाए। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 25 रन का योगदान दिया। जेमिमा ने मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर (16 गेंद में नाबाद 15 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी निभाई।

जेमिमा ने अपनी पारी के दौरान कई दर्शनीय शाट खेले लेकिन उनकी पारी का आकर्षण 12वें ओवर में बाएं हाथ की कलाई की स्पिनर शशिनी जिम्हानी पर जड़े चार चौके रहे और इसी दौरान उन्होंने 34 गेंद में अपना पचासा भी पूरा किया। शेफाली वर्मा ने भारतीय पारी की शुरुआत पहले ओवर में दो चौकों के साथ आक्रामक अंदाज में की, लेकिन वह इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकीं।

रोड्रिग्स ने 44 गेंद की नाबाद पारी में 10 चौके लगाए। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 25 रन का योगदान दिया। जेमिमा ने मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर (16 गेंद में नाबाद 15 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी निभाई।

सुखमन सिंह ने पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब जीता

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 21 दिसंबर।

जीत

युवा गोल्फर सुखमन सिंह ने रविवार को कोलकाता के टालीगंज क्लब में खेली गई प्रतिष्ठित आइजीयू 124वीं पेशेवर गोल्फ चैंपियनशिप आफ इंडिया का खिताब अपने नाम किया। 36 होल के फाइनल मुकाबले में सुखमन ने हरियाणा के हरमन सचदेवा को 29 होल के बाद बढ़त बनाई।

फाइनल मुकाबले की शुरुआत से ही सुखमन ने अपना शानदार खेल दिखाया। छठे होल तक मुकाबला बराबरी पर रहा, लेकिन 12 होल के बाद सुखमन ने बढ़त बना ली। पहले 18 होल के बाद वह आगे थे। सुखमन के पिता सिमरजीत सिंह खुद पूर्व भारत नंबर-एक एमेच्योर रह चुके हैं और श्रीलंका एमेच्योर के तीन बार विजेता तथा आइजीयू मिड-एमेच्योर विजेता भी रहे हैं।

सुखमन ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी इसके लिए मेहनत की और इसे हासिल करना एक खास अहसास है।

जीत के बाद सुखमन ने कहा, यह अब भी एक सपने जैसा लग रहा है, यकीन करना मुश्किल है कि मैंने यह खिताब जीत लिया है। मैंने पूरी जिंदगी इसके लिए मेहनत की और आखिरकार इसे हासिल करना खास अहसास है। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। मेरे पिता ने तब भी मुझ पर भरोसा रखा, जब मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था।

भारत 2027 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका | हताशा | बांग्लादेश, हांगकांग और सिंगापुर से मिली हार

भारतीय फुटबाल के लिए निराशा से भरा रहा वर्ष 2025

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय फुटबाल के लिए वर्ष 2025 निराशा से भरा रहा जिसमें उसे गंभीर प्रशासनिक संकट, अदालती सुनवाई, वित्तीय समस्याओं, घरेलू लीग के अभाव और सीनियर पुरुष टीम के खराब प्रदर्शन से जूझना पड़ा। जैसे-जैसे साल खत्म होने लगा लियोनेल मेस्सी के बहुचर्चित 'जीओएटी इंडिया टूर' ने कुछ दिलचस्पी पैदा की और इस खेल को लेकर कुछ चर्चा शुरू करने पर मजबूर किया। लेकिन इससे भारतीय फुटबाल को कुछ फायदा हुआ होगा ऐसा नहीं लगता है।

भारतीय फुटबाल की अपनी समस्याएं ही कम नहीं थी और ऐसे में मेस्सी के दौरे के पहले दिन साल्ट लेक स्टेडियम में फैली अराजकता और अव्यवस्था ने शर्मिंदगी को और बढ़ा दिया। भारतीय फुटबाल के गढ़ कहे जाने वाले कोलकाता में कानून-व्यवस्था का बिगड़ना भले ही अच्छी खबर न हो, लेकिन हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में मेस्सी के कार्यक्रम अच्छी तरह से आयोजित किए गए। इस साल भारत की सीनियर पुरुष टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उसे ढाका में नवंबर में खेले गए 2027 एएफसी एशियाई कप क्वालीफाइंग मैच में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। यह बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 22 वर्षों में उसकी पहली पराजय थी।

भारतीय टीम वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस साल वह कुछ जीत हासिल करने में कामयाब रही, जिसमें सितंबर में मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित सीएएफए नेशंस कप में कांस्य पदक जीतना भी शामिल है। सबसे अहम मैचों में भारत अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहा और 2011 के बाद पहली बार एशियाई कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका, जिससे टीम फीफा रैंकिंग में और नीचे खिसक गई। बांग्लादेश के अलावा भारतीय पुरुष टीम को हांगकांग और सिंगापुर जैसी कम रैंकिंग वाली टीमों से भी हार का सामना करना पड़ा। सिंगापुर से 1–2 से मिली हार ने एशियाई कप में प्रवेश करने की उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

इस साल भारत की सीनियर पुरुष टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उसे ढाका में नवंबर में खेले गए 2027 एएफसी एशियाई कप क्वालीफाइंग मैच में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा। यह बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 22 वर्षों में उसकी पहली पराजय थी। भारतीय टीम पिछले साल अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी।

केओए ने वार्षिक पुरस्कार समारोह में आयुष, प्रज्वल, प्रणवी को सम्मानित किया

बंगलुरु, 21 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक ओलंपिक संघ (केओए) ने उभरते हुए शटलर आयुष शेट्टी, अनुभवी टेनिस खिलाड़ी एसडी प्रज्वल देव सहित इस साल उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को रविवार को वार्षिक पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया। बीस साल के शेट्टी ने जून में यूएस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट जीतकर बीडब्ल्यूएफ (विश्व बैडमिंटन महासंघ) विश्व टूर में इस साल भारत के खिताब के सूखे को समाप्त किया था।

प्रज्वल 2024 में भारत की डेविस कप टीम के सदस्य थे। आइजीपीएल आमंत्रण मुंबई में मिश्रित वर्ग में जीत दर्ज कर इतिहास रचने वाली युवा गोल्फर प्रणवी उर्स को भी सम्मानित किया गया। वह पुरुषों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनीं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 43, अंक 35
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरपी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

संपादकीय जागरण
सोमवार, 22 दिसंबर, 2025 : पौष शुक्ल - 2 वि. 2082

आचरण व्यक्तित्व का परिचय होता है

संकट में बांग्लादेशी हिंदू

यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बर्बर तरीके से हत्या करने वालों को न्याय के कठघरे में खड़ा करने और वहां के सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। भारत को बांग्लादेश पर इसके लिए दबाव भी बनाना होगा कि वहां अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं के जान-माल की रक्षा सुनिश्चित हो सके। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि दीपू चंद्र दास को पीट-पीटकर मारने और उसके शव को भीड़ के सामने जलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि यह गिरफ्तारी तब हुई जब रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वहशी घटना का वीडियो वायरल हो गया। बांग्लादेश के हिंदू इसलिए कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, क्योंकि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है और इस बहाने कट्टरपंथी ताकतें भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। इस माहौल का सबसे बुरा असर वहां के हिंदुओं पर पड़ रहा है। बांग्लादेश के हिंदू एक लंबे समय से खतरे में हैं। जब बांग्लादेश बना तब वहां करीब 15-16 प्रतिशत हिंदू थे, लेकिन आज उनकी संख्या आठ प्रतिशत से भी कम रह गई है। यह एक तथ्य है कि पूर्वी पाकिस्तान में भी हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ और इस पाकिस्तानी क्षेत्र के बांग्लादेश बन जाने के बाद भी। चूंकि वहां उत्पीड़न का सिलसिला कायम है, इसलिए उनका पलायन भी थम नहीं रहा है। यदि यही हालत रही तो बांग्लादेश के हिंदुओं की वही दयनीय दशा हो सकती है जो पाकिस्तान में है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भले ही हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा का वादा करती रहती हो, लेकिन तथ्य यह है कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं पर अत्याचार का जो सिलसिला कायम हुआ, वह अंतरिम सरकार गठित होने और उसकी कमान मोहम्मद यूनुस की ओर से संभालने के बाद भी थमा नहीं। पिछले 16 महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने की तमाम घटनाएं घट चुकी हैं। उनकी जान-माल के साथ उनके मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि जो कट्टरपंथी ताकतें यह सब कर रही हैं, उन्हें अंतरिम सरकार का सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त है। ऐसी कुछ ताकतें तो इस सरकार को अपना समर्थन भी दे रही हैं। इनमें से वह जमाते इस्लामी भी है, जो भारत विरोध के लिए कुख्यात है। भारत को यह आभास होना चाहिए कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को लेकर उसकी ओर से व्यक्त की जा रही चिंता मात्र से बात बनने वाली नहीं है। इस मामले में भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सहयोग एवं समर्थन भी लेना होगा।

निराशाजनक स्थिति

दिल्ली में पुलिसकर्मियों की कमी निराशाजनक है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है, जब यह सामने आता है कि राजधानी की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही पुलिसकर्मियों के स्वीकृत पदों की संख्या उसके अनुरूप नहीं बढ़ी है, वहीं वर्तमान में स्वीकृत पदों के मुकाबले भी वहां करीब दस प्रतिशत पुलिसकर्मियों की कमी है। इससे कानून-व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है और अपराध का ग्राफ साल दर साल बढ़ रहा है। वहीं, पुलिसकर्मियों को भी 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। स्थिति यह है कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने भी बीते दिनों राज्य सभा में दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की कमी पर चिंता जताई थी।

> राजधानी में बढ़ते अपराध और वीआइपी सुरक्षा की चुनौती को देखते हुए दिल्ली पुलिस में रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती की जानी चाहिए

दिल्ली पुलिस के जवानों की एक बड़ी संख्या वीआइपी सुरक्षा में भी लगी हुई है। ऐसे में कानून-व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों की कमी हो जाती है। दिल्ली पुलिस के लिए अपराध नियंत्रण के साथ ही राजधानी को आतंकी हमलों से बचाना भी बड़ी चुनौती है। वहीं, संगठित अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही साइबर अपराधियों से निपटना भी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा काम है। इसलिए वहां पुलिसकर्मियों की पर्याप्त संख्या होनी ही चाहिए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि राजधानी को बड़ी चुनौतियों से बचाते हुए बेहतर कानून-व्यवस्था बनाई जा सके। सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की रिक्तियां तेजी से भरी जानी चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या टी-20 विश्व कप टीम से शुभमन गिल को बाहर करने का फैसला सही है?

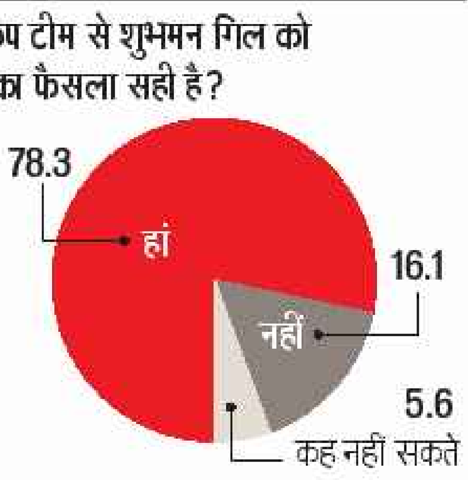

आज का सवाल

क्या इंटरनेट मीडिया पर ज्यादा समय देने से बच्चे अधीर और उग्र हो रहे हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विश्व की दिशा परिवर्तन का वर्ष

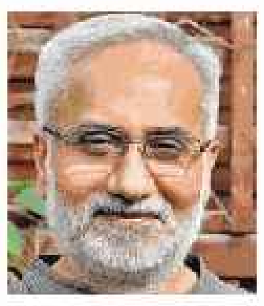

शिवकांत शर्मा

ट्रंप की नाटकीय नीतियों से वैश्विक स्तर पर ऐसी उथल-पुथल मची जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही विश्व व्यवस्था में पहले कभी नहीं देखी गई

विश्व आर्थिक मंच, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, राजनयिक और विश्लेषक वर्ष 2025 को दुनिया की दिशा बदलने वाले वर्ष के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाटकीय टैरिफ नीति, वैश्विक समीकरणों और व्यवस्थागत नियमों में हुई ऐसी उथल-पुथल है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही विश्व व्यवस्था में पहले कभी नहीं देखी गई। वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार बढ़कर 40 गुना से अधिक हो गया था जिसके कारण दुनिया के एक अरब से अधिक लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकल सके, लेकिन इस दौर में उद्योग-धंधे अमेरिका और यूरोप छोड़कर एशियाई देशों में चले गए, जहां कच्चा माल और मजदूरी सस्ती थी। इससे अमेरिका और यूरोप में कामगार बेरोजगार हुए और व्यापार घाटे भी बढ़े। ट्रंप इसी प्रक्रिया को पलटने के वादे पर चुनाव जीते थे। इसलिए, उन्होंने सत्ता संभालते ही कुछ देशों पर भारी टैरिफ लगाने के साथ-साथ छोटे-बड़े सभी देशों पर टैरिफ लगा दिए। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाया गया, ताकि विश्व व्यापार संगठन में चुनौती न दी जा सके। पिछले 70 वर्षों से मुक्त व्यापार की वकालत करते आ रहे देश ने 30 वर्ष लंबी गैट वार्ताओं के बाद बनी विश्व व्यापार की व्यवस्था को एक एलान से ध्वस्त कर दिया।

ट्रंप के टैरिफ युद्ध का प्रमुख निशाना चीन था, परंतु उसने अपने दुर्लभ खनिजों और औद्योगिक चुंबकों के ब्रह्मास्त्र से अपना बचाव कर लिया। भारत और ब्राजील इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों पर सर्वाधिक ऊंचे 50 प्रतिशत टैरिफ लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस पर युद्धविराम का दबाव डालने के लिए ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदना बंद करने का दबाव डाल रहे हैं, जिसे वे दोस्त कहते हैं। जबकि रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार और प्रतिद्वंद्वी चीन से कुछ नहीं कहते। नाटो में अपने सहयोगी तुर्किये से कुछ नहीं कहते। अपने दोस्त हंगरी के नेता ओर्बान को खरीदने की छूट दे रहे हैं और खुद रूस से परमाणु ईंधन की खरीदारी जारी है। ट्रंप की अबूझ नीतियों के कारण यह साल 25 वर्षों से घनिष्ठ होते आ रहे भारत-अमेरिका रिश्तों पर संदेह और अनिश्चितता के साए का साल रहा।

इस नियमहीन धौंस की कूटनीति ने चीन, रूस और ब्राजील जैसी ब्रिक्स शक्तियों को डालर के बिना व्यापार करने के उपाय खोजने पर विवश किया। ये देश अब अपना अधिकांश व्यापार अपनी मुद्राओं में करने लगे हैं। रूस और चीन करीब 250 अरब डालर के व्यापार का 99.1 प्रतिशत अपनी मुद्राओं में करते हैं। भारत-रूस भी अपने व्यापार का 96 प्रतिशत अपनी मुद्राओं में करते हैं। चीन और ब्राजील भी आपसी व्यापार अपनी मुद्राओं में करने लगे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए डालर मुक्त व्यापार नया नहीं है, पर ट्रंप की मनमानी और धौंस ने इसे नई गति दी है।

ट्रंप की नीतियों की अस्थिरता और अप्रत्याशितता ने सामरिक समीकरणों को भी उलटा-पलटा है। यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों की बुनियाद सदियों पुरानी है। दूसरे महायुद्ध में यूरोप के जर्जर और कंगाल हो जाने के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्ति बनकर उभरा था। इसलिए उसने अपने नेतृत्व में विश्व के लिए एक नई नियमबद्ध व्यवस्था बनाई जो उसके उदार लोकतंत्र, खुली स्पर्धा वाली आर्थिकी और कानून व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित थी। यूरोप उसका सामरिक साथी और वैचारिक प्रयोगशाला बना। यूरोप ने शीतयुद्ध के दौरान साम्यवादी एकदलीय तानाशाही के फैलाव को रोके रखा। सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए पूर्वी यूरोप के देशों ने अमेरिका और यूरोप की व्यवस्था को केवल तेज आर्थिक विकास के लिए ही नहीं अपनाया था। उन्हें साम्यवादी तानाशाही से अपना अस्तित्व भी बचाना था और उम्मीद थी कि यूरोप और अमेरिका उनकी रक्षा करेंगे। ट्रंप यूक्रेन के बचाव की जगह पुतिन को खुश रखने के लिए जिस तरह उसकी जमीन और सुरक्षा का सौदा करने में लगे हैं, उसने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है।

यूरोप को सबसे बड़ा धक्का ट्रंप की नई सुरक्षा नीति में पुतिन के हमले और तानाशाही की आलोचना की जगह अपनी आलोचना को पढ़कर लगा है। अमेरिकी सुरक्षा नीति कहती है कि लचर नीतियों के कारण यूरोप के कुछ देशों में कुछ ही दशकों के भीतर यूरोपीय सभ्यता लुप्त हो जाएगी, क्योंकि गैर-यूरोपीय बहुसंख्यक बन जाएंगे। इसलिए वह यूरोप में राष्ट्रवादी पार्टियों को सत्ता में देखना चाहती है। स्पष्ट है कि ट्रंप यूरोप को अब एक बोझ के सिवा कुछ नहीं मानते। दूसरी तरफ पुतिन का स्वागत वे महाशक्ति की तरह तालियां बजाकर करते हैं। चीनी राष्ट्रपति के साथ होने वाली शिखर बैठक को जी-2 की संज्ञा देकर वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि चीन अब बराबर की महाशक्ति है।

अवधेश राजपूत

स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट ने ट्रंप के इस रवैये को अमेरिका की 'सभ्यतागत आत्महत्या' की संज्ञा दी है। उदार लोकतंत्र, खुली स्पर्धा और नियमबद्ध व्यवस्था जैसे आदर्शों को ताक पर रखकर ट्रंप तीन महाशक्तियों के दबदबे वाली दुनिया बनाने की राह पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के किसी मंच पर अब जुबानी जमाखर्च के सिवा इन तीनों की आमराय के बिना कुछ हो पाने की संभावना कम ही दिखती है। ऐसे में असली चुनौती यूरोप और भारत के सामने है कि कैसे अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर होकर अपना दबदबा बढ़ाएं और कारोबार फैलाएं। इसमें कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि दुनिया तिकोना रूप लेती है तो समर्थन-शक्ति के लिए कई छोटे देश साथ आना चाहेंगे। तीन या अधिक धुरियों में बंटी दुनिया में जलवायु परिवर्तन और जिहादी आतंक की रोकथाम जैसी वैश्विक चुनौतियों पर अब क्षेत्रीय सहयोग जुटाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष का सबसे बड़ा दिशा परिवर्तन एआइ या यंत्रमेधा का आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र में सक्रिय हो जाना है। 30 वर्ष पुरानी सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद यह उससे भी बड़ी क्रांति है, जो खोज से लेकर निर्माण और उपभोग तक उत्पादन के हर पहलू को और कामकाज को प्रभावित करेगी।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

मुक्त व्यापार से खुलेगी प्रगति की राह

डा. जयंतीलाल भंडारी

अगले वर्ष होने वाले नए एफटीए भारत में निवेश-निर्यात बढ़ा कर उसे आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे

ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर अनिश्चितताओं के बीच भारत के निर्यात में बढ़ोतरी का रुझान दिखा है। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 64.05 अरब डालर से बढ़कर 73.99 अरब डालर हो गया। निर्यात में 15.52 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है। इसके पीछे मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए की अहम भूमिका मानी जा रही है। नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ एफटीए के आकार लेने से भारत का निर्यात नई ऊंचाई पर होगा तथा भारत की व्यापार घाटे की चिंताएं कम होंगी। इसी पृष्ठभूमि में 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए को मंजूरी दी है। दोनों देशों ने 14 साल पहले एफटीए पर बातचीत शुरू की थी। इस एफटीए से जहां वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के साथ-साथ निवेश प्रवाह को बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मा, शिक्षा और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बनने की भी उम्मीद है।

इससे पहले ही 18 दिसंबर को ओमान के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस एफटीए को आधिकारिक तौर पर समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (सीपा) कहा गया है। इस एफटीए के तहत भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को ओमान में शून्य दर पर पहुंच मिलेगी। इसमें ओमान को होने वाले 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात शामिल हैं। इससे भारत के कपड़ा, रत्न-आभूषण, दवाई, वाहन, कृषि उत्पाद और चमड़ा उद्योग को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। खासतौर से भारत से करीब 3.64 अरब डालर के निर्यात पर ओमान में फिलहाल लगने वाला पांच प्रतिशत शुल्क शून्य हो जाएगा। इसके बदले में भारत ने ओमान से आने वाले विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी सुनिश्चित की है। भारत ने अपनी करीब 78 प्रतिशत टैरिफ लाइन पर शुल्क में उदारता की पेशकश की है। ऐसे में मूल्य के लिहाज से ओमान से भारत में 95 प्रतिशत उत्पादों के शुल्क कम होंगे। इनमें खजूर, मार्बल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद शामिल हैं। निश्चित रूप से इस एफटीए के तहत भारत के हित में कई अहम बातें हैं। भारत ने घरेलू हितों की रक्षा के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। पेशेवर आवाजाही पर भी एफटीए में भारत के हित हैं। पहली बार ओमान ने भारतीय पेशेवरों की आवाजाही पर व्यापक रियायतें दी हैं। 'इंट्रा-कारपोरेट ट्रांसफरीज' का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। टेंडर के आधार पर सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए समय की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है। आइटी, बिजनेस सर्विसेज, आडियो-विजुअल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भारतीय कंपनियां अब ओमान में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकेंगी। एफटीए लागू होने के बाद भारत के उत्पाद और सेवा निर्यात ओमान में बढ़ सकेंगे और भारत का प्रतिकूल व्यापार असंतुलन कम होगा। ओमान के आधुनिक बंदरगाहों के उपयोग से पूर्वी यूरोप तक माल पहुंचाने में लगने वाले समय और खर्च में भारी कमी आएगी, जिससे भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी।

अनुकूल नीतियों से निर्यात में आ रही तेजी ● फाइल

मोदी सरकार के दौरान मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर प्रगति हुई है। एक अक्टूबर से भारत और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिंचेस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के बीच भी एफटीए लागू हो गया है और एफ्टा देशों को निर्यात बढ़ने लगे हैं। इसी क्रम में भारत और ब्रिटेन का एफटीए भी महत्वपूर्ण है। अब नए वर्ष 2026 में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, भारत-गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों-पक्षों के साथ भी एफटीए आकार लेते हुए दिखाई देंगे। इन देशों के साथ एफटीए में सिर्फ उत्पाद निर्यात ही शामिल नहीं होंगे, वरन सेवा सेक्टर परिदृश्य से संबंधित निर्यात भी शामिल होंगे। चूंकि सेवा निर्यात में भारत की विशेषज्ञता बढ़ती जा रही है, इसलिए जहां भारत के प्रशिक्षित श्रमिकों एवं पेशेवरों के लिए एफटीए वाले देशों में काम के मौके बढ़ेंगे, वहीं भारत की सेवा निर्यात से कमाई की ऊंची संभावनाएं बढ़ेंगी।

भारत के लिए एफटीए के लाभों के मद्देनजर एक अप्रैल से लागू होने वाले नए श्रम कानून मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जिन बहुप्रतीक्षित चार नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, उनसे श्रमिकों के साथ उद्योग-कारोबारों को भी राहत मिलेगी। ये श्रम कानून स्वतंत्रता के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधार हैं। नए श्रम कानून भविष्य के लिए एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और इससे उद्योग-कारोबार को एफटीए के अधिकतम लाभ हासिल होने की उम्मीद बनी है।

नए वर्ष 2026 में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के साथ एफटीए को तेजी से आकार देने की डगर पर आगे बढ़ेगा। उम्मीद करें कि नए साल में होने वाले एफटीए भारत को निर्यात, सेवा, निवेश, तकनीकी सहयोग और पेशेवरों की आवाजाही की नई आर्थिक शक्ति बनाते हुए देश को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की डगर पर आगे बढ़ाएंगे।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

व्यवस्थित जीवन

आज का मनुष्य स्वयं को अत्यंत व्यस्त मानता है, किंतु भीतर से वह उतना ही अस्त-व्यस्त भी है। व्यस्तता जीवन की सक्रियता और ऊर्जा का संकेत हो सकती है, किंतु जब यह अनुशासन, संतुलन और उद्देश्य से विहीन हो जाती है, तब यही व्यस्तता जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि साधन बढ़े हैं, गति तेज हुई है, परंतु जीवन की दिशा धुंधली होती जा रही है। स्मरण रहे कि सुखी, सफल और स्वस्थ जीवन के लिए नियमितता और समयबद्धता कोई वैकल्पिक गुण नहीं, बल्कि अनिवार्य शर्तें हैं। इनके अभाव में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो दूर, स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर पाता।

आज आर्थिक प्रगति की अंधी दौड़ में जीवन एकांगी होता जा रहा है। भौतिक उपलब्धियों के आकर्षण ने पारिवारिक संवाद, आत्मचिंतन और स्वास्थ्य जैसे मूल्यों को हाशिए पर धकेल दिया है। परिणामस्वरूप जीवन सुविधाजनक होते हुए भी समस्याग्रस्त और तनावग्रस्त बन गया है। जीवन की अधिकांश असफलताओं की जड़ अनियमित एवं अव्यवस्थित जीवनशैली में छिपी होती है। जीवनशैली ऐसी बन गई है कि मनुष्य जीने के लिए सब कुछ करने लगा, परंतु स्वयं जीने का अर्थ ही भूल गया है। हम दिन को भी रात की तरह जीने लग गए हैं। इसी से अशांति है, असंतुलन है, तनाव है और बेचैनी है। जबकि शांत और स्थिर दिमाग बेहतर काम करता है। हर समय की बेचैनी किसी काम नहीं आती। इससे न तो हम वह कर पाते हैं, जो करना चाहते हैं और न ही वह, जो दूसरे हमसे अपेक्षा कर रहे होते हैं। समस्याएं कैसी भी हों, हमारा व्यवस्थित न होना समस्याओं को और विकराल बना देता है।

इस संदर्भ में लेखक एकहार्ट टोल का सुझाव बहुत उपयोगी है कि 'हमारी भीतरी दुनिया जितनी सुलझी हुई होती है, बाहरी दुनिया उतनी व्यवस्थित होती चली जाती है।'

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

अपनी जड़ों से कटता बांग्लादेश

'बांग्लादेश में भारत के लिए खतरा बढ़ा' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में दिव्य कुमार सोती ने पड़ोस में कट्टरपंथी ताकतों के उभार का वर्णन किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद यह पड़ोसी देश अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अंतरिम सरकार के संरक्षण में कट्टरपंथी ताकतों का उभार और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा चुनावों को टालने की मंशा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। सत्ता में बने रहने के लिए कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट देना और 'ग्रेटर बांग्लादेश' जैसे सब्जबाग दिखाना क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर चुनौती है। बंगाल, ओडिशा और बिहार के हिस्सों को शामिल करने की कल्पना भारत की संप्रभुता पर हमला है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की जयंती पर प्रतिबंध और उनकी मजार पर जाने वालों के साथ मारपीट यह दर्शाती है कि यह देश अपनी ऐतिहासिक जड़ों और मूल्यों से कटता जा रहा है। भारतीय उच्चायोग पर कट्टरपंथियों का हमला कूटनीतिक मर्यादाओं का घोर उल्लंघन है। यह वही भारत है, जिसकी सेना के बलिदान से बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन सका। आज बांग्लादेश जिस राह पर चल पड़ा है, वह पाकिस्तान के कट्टरपंथी माडल की याद दिलाता है, जो भारत के लिए खतरा बन चुका है। बांग्लादेश अपनी जड़ों से जिस तरह कट रहा है, उससे वह शीघ्र ही उखड़ भी सकता है।

himanshushekhar.mca@gmail.com

बांग्लादेश में चरमपंथ

बांग्लादेश एक अत्यंत गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से शुरू हुई अस्थिरता अब और अधिक हिंसक रूप ले चुकी है। बांग्लादेश वर्तमान में चरमपंथ के उदय, आर्थिक मंदी और आंतरिक असुरक्षा के ऐसे चक्र में फंसा है, जिससे निकलने का फिलहाल कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा है। फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संभावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में विफल दिख रही है। या फिर जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की गई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। 2025 में महंगाई दर 10 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, जिससे आम जनता के लिए जीवन-यापन मुश्किल हो गया है। देश की रीढ़ माने जाने वाले गारमेंट सेक्टर में बड़े पैमाने पर हड़तालें और अशांति देखी जा रही है, जिसके कारण कई फैक्ट्रियां अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों, उनके घरों और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा की है। शेख हसीना चाहे जैसी भी हों, उन्होंने जमात और अन्य भारत विरोधी ताकतों को काबू में रखा था।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

प्रदूषण का कलंक

दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। इसका स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है। समय-समय पर वायु प्रदूषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं खोजा जाता है। यहां तक कि संसद में इस पर विचार-विमर्श होने के स्थान पर केवल शोरगुल और हंगामा ही होता रहता है। सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुमान के अनुसार 2023 में दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से 17,200 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आए दिन दिल्ली में प्राथमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ता है। समय-समय पर सरकार द्वारा वायु प्रदूषण बढ़ जाने से आनलाइन शिक्षा प्रदान की जाती है। मौजूदा दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में 38,000 कक्षाएं हैं। इनमें पहले चरण में 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाने का निर्णय लिया है। धूल से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नगर निगम के वित्तीय रूप से 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रित करने को लेकर विभिन्न उपायों को विभिन्न तरह के सवाल उठना भी स्वाभाविक है। यहां तक कि वर्ष भर वायु प्रदूषण नियंत्रित रहे और बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका असर न पड़े।

मीना धानिया, सिरसपुर दिल्ली

पोस्ट

गोपीनाथ बारदोलोई जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से ही थे, लेकिन भाजपा सरकार ने गुवाहाटी हवाई अड्डे का नामकरण उनके नाम पर ही किया है। हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

'धुरंधर' में भारतीय मुसलमानों, इस्लाम, कुरान या पैगंबर के खिलाफ एक भी सीन या संवाद नहीं। फिर भी, कुछ लोग व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं। वे पाकिस्तान को इस्लाम का सिंबल मान रहे हैं। शायद इसीलिए तकलीफ हो रही है। दिलीप मंडल@Profdilipmandal

हिंदू पुजारी यदि भाजपा के लिए वोट की अपील करें तो वह सांप्रदायिक है, लेकिन ईसाई पादरी ईसाइयों और मुसलमानों से द्रमुक के पक्ष में मतदान की अपील करें तो यह सेक्युलर है। सुमंत रमण@sumanthraman

पूरे बांग्लादेश में जिहादी हादी के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस निर्दोष गरीब हिंदू युवा की सुध नहीं ले रहा, जिसकी जिहादी गिरोह ने पीट-पीटकर हत्या कर चौराहे पर जला दिया। दीपू चंद्र दास के परिवार की व्यथा क्या किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही। तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

जनपथ

बंग्लादेशी खा रहे लोकतंत्र का नाम,
चेला बने मुनीर के गुंडागर्दी काम।
गुंडागर्दी काम और नारा इस्लामी,
किंतु न इसपर बोल रहा है कोई 'वामी',
रहे जहां इस्लाम न टिकती डेमोक्रेसी,
यही आज चरितार्थ कर रहे बंग्लादेशी।

\- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नईदिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय :0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 157

****

कोयला एक नीति दो !

कोयले का उपयोग हवाओं को जहरीला बनाने के साथ जलवायु परिवर्तन की गति को भी तेज करता है। यह सर्वमान्य तथ्य है। यही वजह है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच कोयला,लकड़ी और जैविक कचरे को जलाने पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब है कि सरकार कोयले के हानिकारक प्रभाव को समझती है। यहीं, पर सरकार की नीतियों के स्तर पर विरोधाभास दिखता है। दिल्ली में कोयला, लकड़ी और जैविक कचरा जलाने पर रोक लगती है,वहीं देश के बाकी हिस्सों में ऐसी कोई रोक नहीं है। विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि देश में वायु प्रदूषण की समस्या को एक शहर या राज्य विशेष की समस्या मान कर नहीं निपटा जा सकता है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्शन प्लान बना कर उसे कड़ाई से लागू करना होगा। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए हैं। खाना बनाने के लिए लकड़ी के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना लेकर आई लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए सिलिंडर रीफिल कराना आसान नहीं है। ग्रामीण इलाकों में खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग अब भी हो रहा है। वायु प्रदूषण से निपटने में सरकार की नीतियों में विरोधाभास की पड़ताल ही आज का अहम मुद्दा है...

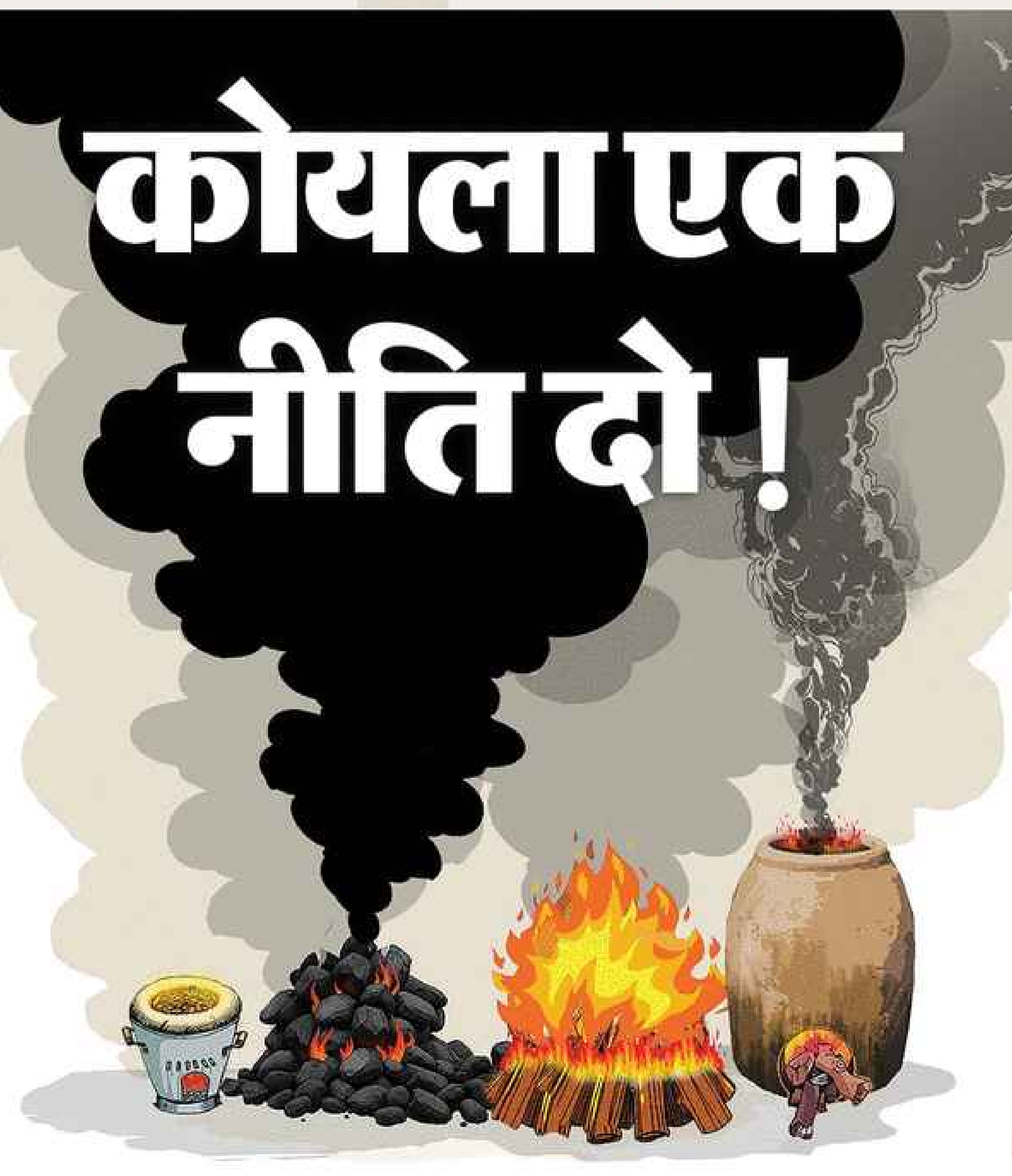

खाना बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल

41% भारतीय परिवार अब भी खाना बनाने के लिए जलाते हैं लकड़ी, उपले या दूसरे बायोमास

34 करोड़ टन कार्बन डाईआक्साइड का सालाना उत्सर्जन होता है लकड़ी और उपले जलाने से

13% हिस्सा है यह उत्सर्जन भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का

50 करोड़ भारतीय अब भी वंचित है स्वच्छ ऊर्जा समाधान से

6 लाख मौतें होती हैं सालाना घर के अंदर के प्रदूषण से

भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत

भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत काफी ज्यादा है। यह कुल ऊर्जा की जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत है। इसमें कोयला सबसे प्रमुख है, जो बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ रही है। 2023 में स्वच्छ ऊर्जा की खपत 8 प्रतिशत बढ़ी, और सरकार जैव-ईंधन को बढ़ावा दे रही है।

मुख्य बिंदु

बढ़ती खपत: 2023 में भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत 8 प्रतिशत बढ़ी, और यह लगभग सभी ऊर्जा मांग वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार थी।

कोयले का प्रभुत्व: देश की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा लगभग 55-75 प्रतिशत कोयले से पूरा होता है, जो भारत का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन है।

ऊर्जा मिश्रण : 2023 में, कुल ऊर्जा आपूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत, तेल की 25 प्रतिशत, और प्राकृतिक गैस की 5 प्रतिशत थी।

वैश्विक स्थिति : 2023 में चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन उपभोक्ता था।

नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि: स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2025 के मध्य तक, कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक गैर-जीवाश्म स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा सहित) से था।

सरकारी प्रयास : सरकार जैव-ईंधन जैसे इथेनाल, बायोडीजल) के उपयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके और पांच साल में खपत का 50 प्रतिशत जैव-ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत की ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में निकट भविष्य में पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाना संभव नहीं होगा।

जागरण रिसर्च

जीवाश्म ईंधन जलाने से वैश्विक जीडीपी का 3.3 प्रतिशत नुकसान

गैस, कोयला और तेल जलाने से दुनिया भर में सड़क हादसों से होने वाली मौतों की तुलना में तीन गुना ज्यादा मौतें होती हैं। 2018 में इसका वैश्विक आर्थिक नुकसान 2.9 लाख करोड़ डालर था, जो वैश्विक जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है। अनुमान है कि 2018 में वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से 45 लाख की मौत हुई, जबकि पीएम 2.5 प्रदूषण की वजह से 1.8 अरब दिनों की काम से छुट्टी, बच्चों में अस्थमा के 40 लाख नए मामले और 20 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले हुआ।

जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण की आर्थिक लागत (जीडीपी का प्रतिशत)

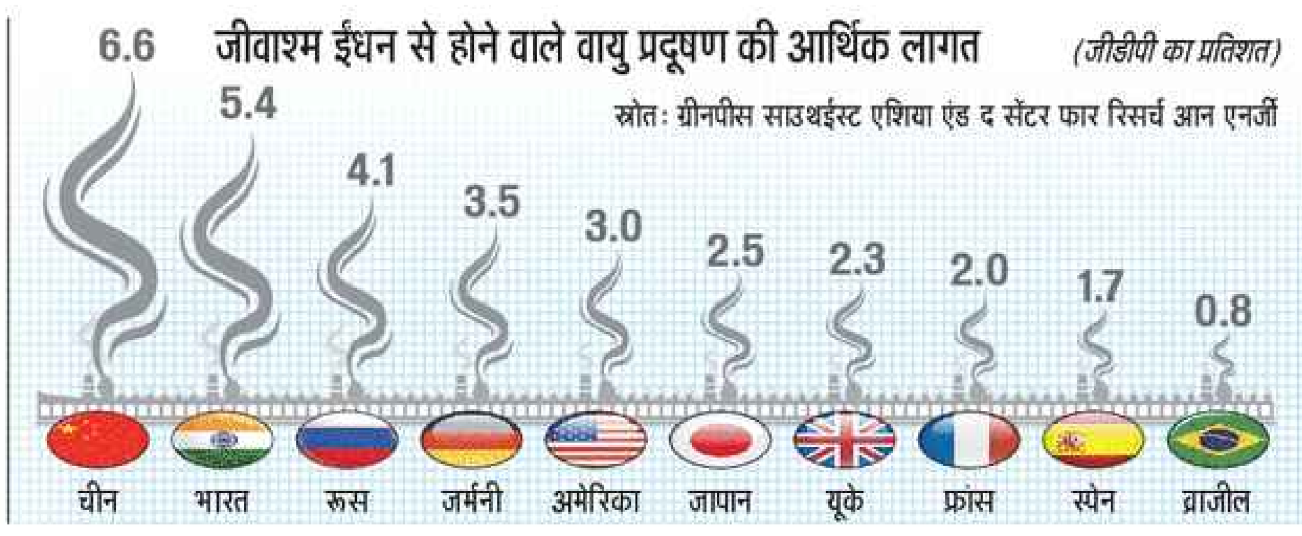

चीन	भारत	रूस	जर्मनी	अमेरिका	जापान	यूके	फ्रांस	स्पेन	ब्राजील
6.6	5.4	4.1	3.5	3.0	2.5	2.3	2.0	1.7	0.8

स्रोत: ग्रीनपीस साउथईस्ट एशिया एंड द सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी

चुनौतियां और भविष्य

भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और विकास के कारण, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता एक बड़ी चुनौती है। हालांकि स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार और उद्योग इलेक्ट्रिक वाहन (इवी) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि जीवाश्म ईंधन की खपत को कम किया जा सके।

17 लाख भारतीयों की मौत हुई 2022 में भारत में जीवाश्म ईंधन से होने वो प्रदूषण की वजह से

प्रदूषित हवा से देशों को नुकसान

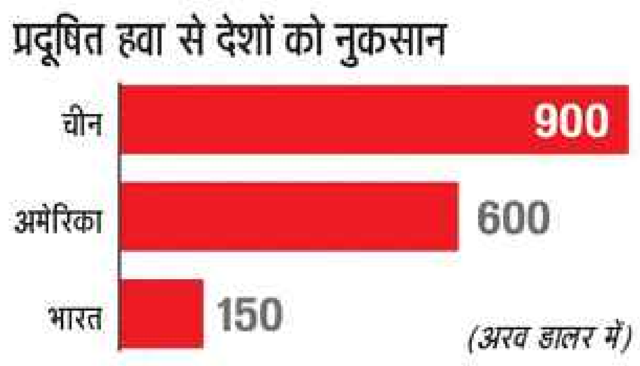

देश	नुकसान (अरब डालर में)
चीन	900
अमेरिका	600
भारत	150

एलपीजी सिलिंडर रीफिल कराने की चुनौती

10 करोड़ परिवारों को नया एलपीजी सिलिंडर मिला था उज्ज्वला योजना के तहत 2023 तक

1/3 आय खर्च करनी होगी बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलिंडर रीफिल कराने पर

50% परिवारों ने एक बार भी रीफिल नहीं कराया है सिलिंडर ऊंची लागत की वजह से

₹1,100 औसत लागत है एलपीजी सिलिंडर रीफिल कराने की भारत में

₹8,800 खर्च आएगा एक परिवार को पूरे वर्ष सिलिंडर रिफल कराने पर

₹27,000 सालाना औसत आय की सीमा तय की गई गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए नीति आयोग

उत्तर भारत में लागू हों निवारक कदम

अनुमिता राय चौधरी
कार्यकारी निदेशक, सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट

वायु प्रदूषण की समस्या से निकटने के लिए हमें पूरे वर्ष समस्या पैदा करने वाले कारणों को खत्म करने पर काम करना होगा। कदम पूरे उत्तर भारत में उठाने होंगे। प्रदूषण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। सिर्फ दिल्ली में कोयला और कचरा जलाने पर रोक से प्रभावी समाधान नहीं मिलेगा।

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को एक क्षेत्र विशेष की समस्या मानकर इससे नहीं निपटा जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की गंभीर स्थिति एक खास भौगोलिक स्थिति के कारण है। यह पूरे इंडो गैंग्नेटिक प्लेन यानी उत्तरी मैदान की समस्या है। ठंड में प्रदूषण की स्थिति इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि हवा का प्राकृतिक वेंटिलेशन रुक जाता है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ यहीं सीमित है। यह पूरे एनसीआर क्षेत्र और आस पास के दूसरे प्रदेशों में भी फैलता है। इसी तरह से दूसरे प्रदेशों का प्रदूषण भी दिल्ली तक आता है। दिल्ली के प्रदूषण में उसका योगदान सिर्फ 30 प्रतिशत है। बाकी प्रदूषण का स्रोत दिल्ली से बाहर है। ऐसे में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले पूरे उत्तर भारत के शहरों के हाटस्पाट यानी ऐसी जगहें जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है, वहां से शुरुआत करनी होगी। इसके बाद शहरों और रीजन के हिसाब से कदम उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली में कोयला, लकड़ी और जैविक कचरा जलाने पर रोक लगाना एक तात्कालिक कदम है लेकिन हमें पूरे उत्तरी मैदान के हिसाब से एक्शन प्लान बना कर उस पर अमल करना होगा। अगर कोयला लकड़ी और जैविक कचरे के जलने से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है तो यही प्रदूषण देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। ऐसे में जब तक हम पूरे रीजन में जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण की समस्या से प्रभावी तरीके से नहीं निपटा जा सकता है। यह सही है कि बिजली उत्पादन के लिए हमें कोयले की जरूरत है लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने पावर प्लांट को धीरे धीरे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर ले जाएं। इसी तरह जैविक कचरा न जलाया जाए। इसके लिए हमें पूरे देश में घरों से निकलने वाले कचरे को एकत्र करके इससे बायोगैस या दूसरी चीजें बनाने का एक मजबूत तंत्र विकसित करना होगा। सिर्फ कुछ शहरों में कचरा प्रबंधन करके काम नहीं चला सकते हैं। अब बात आती है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पूरे वर्ष काम करने की। आम तौर पर जब प्रदूषण की बात आती है सिर्फ दिल्ली की बात होती है और वह भी ठंड के कुछ महीनों की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड के दिनों में प्रदूषण धुंध के रूप में हमें दिखने लगता है जबकि दिल्ली में पूरे वर्ष का एक्यूआइ 126 है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के हिसाब से पूरे वर्ष का एक्यूआइ 40 होना चाहिए। इसका मतलब है कि पूरे वर्ष दिल्ली में प्रदूषण मानक से चार पांच गुना अधिक रहता है। इसका मतलब है कि हमें प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पूरे वर्ष काम करना होगा और प्रदूषण से प्रभावित पूरे रीजन यानी उत्तर भारत में काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है लेकिन जितने बड़े पैमाने पर और जितनी तेजी से काम होना चाहिए, उस तरह से काम नहीं हो रहा है। राज्यों को सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़े पैमाने पर काम करना होगा, जिससे लोग आसानी से आ जा सकें और सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या कम हो। ग्रामीण इलाकों में खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल अब भी हो रहा है। सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। आप सिर्फ शहरों में कदम उठा कर प्रदूषण से नहीं निपट सकते हैं क्योंकि अगर ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण हो रहा है यह शहरों तक जरूर आएगा।

आपकी आवाज

दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण का एक इलाज यह भी है कि यहां ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों खासतौर पर मैट्रो का विस्तार भी है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए प्राथमिक और युद्धस्तर पर का करें और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, आमजन को भी चाहिए कि वो सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, अपने वाहन का प्रयोग जरूरी होने ही करें।
राजेश कुमार चौहान

वायु प्रदूषण आज देश की सबसे गंभीर स्वास्थ्य आपदाओं में से एक बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकारें योजनाएं तो बना रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सुधार नजर नहीं आ रहा है। न तो नियमों का पालन हो रहा है, न ही प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती हो रही है। हर साल हालात बदतर होते जा रहे हैं और आम नागरिक इसकी कीमत चुका रहा है। अब सवाल सिर्फ कदम उठाने का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है। साहिल गर्ग

वायु प्रदूषण का एक कारण पेट्रोल और डीजल वाहन भी हैं। अगर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले तो यह वायु प्रदूषण रोकने के लिए अच्छी पहल होगी। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण भी वाहनों में भी वृद्धि हुई है। अगर बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकारों के साथ आमजन अभी भी गंभीर नहीं हुआ तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हमारे देश के लिए यह अच्छा संकेत है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन शुरू हो चुका है। दीपक पांडे

इंडस्ट्री को बनाया जाए गैस आधारित

डी साहा
पूर्व अतिरिक्त निदेशक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जीवाश्म ईंधन हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने में बड़ा योगदान करता है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इंडस्ट्री और पावर प्लांट को गैस आधारित बनाना होगा। इसके अलावा हमें स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। इससे हमारे ऊर्जा के मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

ऐसे समय में जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके स्रोत पर ही लगाम लगानी होगी। ऐसे में यह देखा जाता है कि प्रदूषण के जिन स्रोतों को बंद करने से आम जन जीवन बाधित न हो, उसी के हिसाब से सरकार कदम उठाती है। अब बात आती है कोयला, लकड़ी या दूसरे बायोमास जलने की तो इसके जलने से हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ती है और प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो जाती है।

ऐसे में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस पर रोक लगाना एक प्रभावी कदम है। हालांकि यह बात सही है कि प्रदूषण को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है क्योंकि हवा बहती है और हवा किसी भौगोलिक या राजनीतिक सीमा में सीमित नहीं रहती है। इसका मतलब है कि अगर दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर काबू पाना है तो कम से कम पूरे एनसीआर में निवारक कदम उठाए जाने चाहिए। ये कदम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं होने चाहिए। दूसरी समस्या खाना बनाने में लकड़ी उपले और दूसरे बायोमास के इस्तेमाल की है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से एक बड़ी आबादी तक खाना बनाने के लिए एलजीपी सिलिंडर तक पहुंच सुनिश्चित हुई लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एलपीजी सिलिंडर की लागत को वहन करना एक चुनौती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी एलपीजी सिलिंडर रीफिल करा सकें, इसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी ग्रामीण इलाकों में प्रदूषण की समस्या को लेकर ज्यादा बात नहीं होती है लेकिन अगर कहीं भी लकड़ी या बायोमास जलता है तो जहरीले तत्व वातावरण को प्रदूषित करते हैं और इसका असर शहरों पर भी पड़ता है। कोयला और दूसरे जीवाश्म ईंधन हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करते हैं। हमारे देश में ज्यादातर पावर प्लांट कोयले से चलते हैं। इनको धीरे धीरे गैस पर चलाना होगा। हालांकि इसे एक साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए हर प्लांट में तकनीकी बदलाव करने होंगे। एक साथ करने से कई तरह की व्यावहारिक दिक्कते आ सकती हैं। ऊर्जा की आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसे में एक प्लान बना कर इंडस्ट्री को गैस आधारित करना होगा। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। इससे हमारे ऊर्जा मिश्रण में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी कम होगी और प्रदूषण में कमी के साथ आयातित जीवाश्म ईंधन की जरूरत भी कम होगी। तीसरी बड़ी समस्या कचरा जलने की है। इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। इसके लिए गांव से लेकर शहर तक प्रभावी कचरा प्रबंधन करना होगा। आज के समय में ऐसी तकनीक उपलब्ध है, जिससे हम कचरे से गैस और बिजली बना सकते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पहल करते हुए गांव में पंचायत स्तर पर कचरे से गैस या बिजली बनाने वाले प्लांट लगाए जा सकते हैं। इससे बनने वाली गैस या बिजली से स्थानीय स्तर पर बिजली की जरूरत पूरी की जा सकती है। यही माडल कस्बों या शहरों में लागू किया जा सकता है। इस तरह से हम प्रदूषण के स्रोत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्ययोजना बना कर उस पर प्रभावी तरीके से अमल करने की। हमारे देश में कार्ययोजना भी है लेकिन इस पर कितना काम हो रहा है और जमीनी स्तर पर किस हद तक बदलाव आया है इसको लेकर जवाबदेही की कमी है। जब तक जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही नहीं तय होगी तक जमीन पर बदलाव नहीं दिखाई देगा।

कश्मीर के लिए खाद्यान्न आपूर्ति की ऐतिहासिक शुरुआत

कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर पंजाब से पहुंची मालगाड़ी से खाद्य पदार्थ लादने के लिए पहुंचे एफसीआई के ट्रक • स्रोत रेलवे

जागरण संवाददाता, जम्मू : अब आपातस्थिति और बिगड़े मौसम के बीच कश्मीर में खाद्यान्न आपूर्ति बाधित नहीं होगी। घाटी में कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां की शुरुआत के साथ रविवार को रेल मार्ग से खाद्यान्न आपूर्ति के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) की पहली खाद्यान्न मालगाड़ी पंजाब से चलकर सुरक्षित और सफलतापूर्वक अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पर पहुंची। यह मालगाड़ी फिरोजपुर मंडल के अजीतवाल गुड्स शेड से रवाना हुई थी। यह पहल रेलवे व भारतीय खाद्य निगम के संयुक्त प्रयास से हुई है।

आर्थिक सेतु बनेगी खाद्यान्न मालगाड़ी - सिंघल : जम्मू रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने इसे रेलवे के लिए गर्व का क्षण बताया। कहा कि एफसीआइ की खाद्यान्न मालगाड़ी पंजाब और कश्मीर के बीच एक आर्थिक सेतु का कार्य करेगी। समय और लागत दोनों की बचत होगी। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर यातायात का दबाव कम होगा, जिससे सड़क परिवहन में भीड़भाड़ घटेगी।

'भूस्खलन में 35 श्रद्धालुओं की मौत थी प्राकृतिक आपदा'

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू: कटड़ा की एक अदालत ने 26 अगस्त को श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में 35 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह घटना प्राकृतिक आपदा के कारण हुई, जिससे आपराधिक लापरवाही साबित नहीं होती है।

याचिका में आरोप लगाया था कि मौसम विभाग व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चेतावनी के बावजूद यात्रा को नहीं रोका गया। इसे लापरवाही मानते हुए बोर्ड के सीईओ और अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की थी। कटड़ा के सब-जज सिद्धांत वैद्य ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि शिकायत सच मान ली जाए, तो भी मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन न करना केवल प्रशासनिक चूक हो सकती है, लेकिन आपराधिक लापरवाही नहीं है। बता दें कि भूस्खलन मामले की जांच में पुलिस ने श्राइन बोर्ड को क्लीन चिट दी है।

गला दबाने के निशान मिटाने संबंधी क्रीम सर्च करने वाले पति को उम्रकैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : महिला की गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने गूगल सर्च हिस्ट्री को अहम साक्ष्य मानते हुए आरोपित पति को उम्रकैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित ने अपने मोबाइल के माध्यम से गूगल सर्च इंजन पर अपराध के सुबूत मिटाने की जानकारी सर्च की थी। गूगल पर सर्च किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के निशान आते हैं या नहीं, यदि आते हैं तो उन्हें मिटाने के लिए कौन सी क्रीम सबसे बेहतर है। पोस्टमार्टम में गला फाड़ा जाता है या नहीं जैसी जानकारियां खोजी गईं।

राकेश गायरी।

प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने सुनवाई में गूगल सर्चिंग को महत्त्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। प्रकरण में दोषी ठहराए गए 23 वर्षीय राकेश ने 14 दिसंबर 2024 को गला दबाकर पत्नी बुलबुल की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि वह शराब पीकर देर रात घर आने का विरोध करती थी। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, इसके बावजूद पुलिस द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य, राकेश के मोबाइल में की गई सर्चिंग व यह तथ्य कि अंतिम बार बुलबुल को राकेश के साथ जीवित देखा गया, न्यायालय में प्रमाणित हुआ। इसके आधार पर न्यायालय ने उम्र कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

पत्नी को खुद ही डाक्टर के पास ले गया था : राकेश का विवाह तीन साल पूर्व हुआ था। परिवार में माता-पिता और एक दो साल का बेटा है। गला दबाकर हत्या करने के बाद राकेश पत्नी को खुद ही डाक्टर के पास ले गया था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया था कि पत्नी लंबे समय से बीमार थी और खुद से ही गला दबा लिया।

यात्री विमानों को मालवाहक में बदलने के क्षेत्र में उतरेगा अडाणी समूह

मुंबई, प्रेट्र: घरेलू विमानन बाजार में तेजी से बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अडाणी समूह अब इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल (एमआरओ) और यात्री विमानों को मालवाहक विमानों में बदलने (पैसेंजर-टू-फ्रेटर या पी2एफ) के क्षेत्र में प्रवेश की योजना बना रहा है।

हवाई अड्डों के संचालन के अलावा, अडाणी समूह पहले से ही एमआरओ और पायलट प्रशिक्षण के कारोबार में मौजूद है। अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) के निदेशक जीत अडाणी ने बताया कि एयर वर्क्स और इंडामर टेक्निक्स जैसी एमआरओ कंपनियों को एक मंच पर लाकर एक बड़ी एमआरओ इकाई बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

देश में 30 हजार पायलटों की होगी जरूरत : भारतीय विमानन कंपनियां आने वाले समय में करीब 1,700 नए विमान शामिल करने वाली हैं। इसके साथ ही देश को 30,000 अतिरिक्त पायलटों की आवश्यकता होगी।

छग में मृत घोषित युवक पहुंचा थाने, बोला- साहब, मैं जिंदा हूं

- दो माह पहले पुलिस ने युवक की हत्या की गढ़ी थी कहानी
- तीन आरोपितों को किया था गिरफ्तार, अब जांच पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दो माह पहले हत्या के बाद मृत घोषित किया गया युवक सीमित खाखा जिंदा निकल आया। शनिवार रात युवक स्वयं कोतवाली थाने पहुंचा और बोला- 'साहब, मेरी हत्या नहीं हुई, मैं जिंदा हूं।' उसकी मौजूदगी से न सिर्फ स्वजन, बल्कि पुलिस भी हैरान रह गई। इस प्रकरण में हत्या के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपितों और पूरी जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब नए सिरे से जांच करने की बात कर रही है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सिटोंगा की है।

रोजगार की तलाश में गया था झारखंड : सीमित ने बताया कि वह रोजगार की तलाश में झारखंड गया था और साथियों से बिछुड़ने के बाद गिरिडीह जिले के सराईपाली गांव में खेतों में काम कर रहा था। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, जिससे वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सका। अब क्रिसमस मनाने के लिए वह घर लौटा है।

सीमित खाखा, पुलिस ने जिसकी हत्या का दावा किया था • नईदुनिया

पुलिस ने विवाद के दौरान हत्या होने का किया था दावा: पुलिस ने दो नवंबर को सीमित की हत्या का राजफाश करते हुए कहा था कि वह चार साथियों संग झारखंड में काम कर रहा था। विवाद के दौरान उसकी हत्या की गई थी। आरोपितों ने शव को जलाने का प्रयास किया था। एसडीओपी चंद्रशेखर परमा ने बताया कि पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की थी।

पोलमपोल भायो

जाम-नगर जयपुर हुयो, होग्या लोग अधीर।
नियम कायदा सड़क का, भूल्या वाहन-वीर।।

लापरवाही : कहीं अपने स्तर पर बीमा तो कहीं सरकार के निर्देशों का इंतजार

दुर्घटना बीमा पर मनमानी, विश्वविद्यालयों में नियम-शुल्क तय नहीं, सरकार का नहीं ध्यान

पत्रिका एक्सक्लूसिव

उच्च शिक्षा लेने वाले लाखों छात्रों के दुर्घटना बीमा पर न सरकार गंभीर न विवि में समान नियम

विजय शर्मा
patrika.com

जयपुर. राज्य में उच्च शिक्षा लेने वाले लाखों युवाओं के दुर्घटना बीमा को लेकर विश्वविद्यालय मनमर्जी से नियम बना रहे हैं। बीमा के लिए सरकार स्तर पर न नियम तय है न ही शुल्क। जाहिर है सरकार विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है। आलम यह है कि कहीं पर विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर ही बीमा योजना लागू है, जहां शुल्क भी अलग-अलग लिए जा रहे हैं। जहां बीमा योजना लागू नहीं है, वहां विवि सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान पत्रिका ने प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालयों में पड़ताल की तो यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। राज्य के आठ वित्त पोषित विश्वविद्यालय ऐसे हैं, जहां पर दुर्घटना बीमा की कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है।

बीते पांच साल में विवि में छात्रों की मौत का आंकड़ा

- राजकीय महाविद्यालयों में 10 विद्यार्थियों की मौत हुई
- कोटा विवि का एक छात्र शामिल
- राजस्थान विश्वविद्यालय के नौ छात्रों की मौत
- इनमें से 15 छात्रों की सड़क हादसों में मौत हुई
- एक छात्र की पानी में डूबने और एक की ट्रेन दुर्घटना में मौत

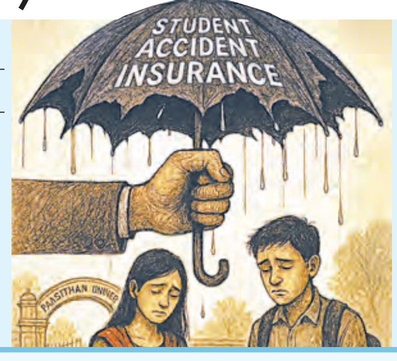

सरकार क्या करे पहल...

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को समान योजना लागू करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। इसके तहत छात्रों के लिए बीमा योजना का शुल्क भी एक समान होना चाहिए। छात्रों से प्रवेश के दौरान ही बीमा का शुल्क लिया जाए। इधर, निजी विश्वविद्यालयों में भी दुर्घटना बीमा को लेकर गंभीरता नहीं है। यहां सड़क सुरक्षा को लेकर छात्रों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन बीमा नहीं किया जा रहा।

किस विवि में बीमा योजना की क्या स्थिति

मोहनलाल सुखाड़िया विवि: महाविद्यालयों के छात्रों की बीमा नहीं हो रहा है।

कोटा विश्वविद्यालय : साल 2021 से एक लाख रुपए दुर्घटना बीमा कराया जाता था। इसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया गया। छात्रों से अतिरिक्त कोई बीमा राशि नहीं ली गई।

महाराजा सूरजमल बृज विवि: बीमा नहीं कराया जाता।

डॉ भीमराव अम्बेडकर विधि विवि: छात्रों का बीमा करवाया जाता है। लेकिन कोई सहायता राशि नहीं दी जाती है।

राजस्थान विश्वविद्यालय: छात्रों से बीमा के 100 रु. लिए जाते हैं।

2021-22	13.57
2022-23	25
2023-24	25.58
24-25	17.07

(बीमा राशि लाखों में)

गोविंद गुरु जनजातीय विवि: विवि स्तर पर बीमा नहीं किया जाता।

वर्धमान महावीर विवि: दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित होने के कारण बीमा की सुविधा नहीं है।

एमबीएम यूनिवर्सिटी: छात्रों का बीमा कराया जाता है, दो लाख बीमा कवर राशि है।

महर्षि दयानंद सरस्वती विवि अजमेर: छात्रों को दो लाख का बीमा कवर दिया जाता है, इसमें 60 रुपए लिए जाते हैं।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता विवि: 100 रुपए बीमा के लिए जाते हैं।

जयनारायण व्यास विवि जोधपुर: छात्रों से 15 रुपए लिए जाते हैं। 1.70 लाख का बीमा किया जाता है।

राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विवि अलवर: बीमा नहीं किया जाता है।

महाराजा गंगा सिंह विवि बीकानेर: छात्रों से 10 रुपए लिए जाते हैं।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर: छात्रों की बीमा प्रक्रियाधीन है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विवि सीकर: बीमा नहीं कराया जाता है।

सभी विवि के लिए एक समान योजना लागू होनी चाहिए

सरकार ने उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए दुर्घटना बीमा की कोई स्पष्ट नीति जारी नहीं कर रखी। इससे किसी दुर्घटना के बाद छात्र के परिजनों को आर्थिक मदद नहीं मिल पाती। जहां पर बीमा योजना लागू है वहां विवि मनमर्जी से शुल्क रखते हैं। सभी विवि के लिए एक समान योजना लागू होनी चाहिए। इसका मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है।

यूनुस खान, विधायक

पत्रिका की-नोट: 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन कार्यक्रम में बोले वक्ता

शब्द जब साहस दें, तभी मीडिया बनता है लोकतंत्र की आत्मा

कोटा. रविवार को 'पत्रिका की-नोट' के तहत 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागी।

patrika राजस्थान पत्रिका | पत्रिका KEYNOTE 2025

कोटा@पत्रिका. *कोटा की धरती पर रविवार को विचारों का एक ऐसा संगम हुआ, जहां समाज की चुनौतियों को दर्पण दिखाया गया। 'पत्रिका की-नोट' कार्यक्रम में रूबरू हुए विशेषज्ञों ने बताया कि मीडिया के शब्द कैसे किसी महिला को संघर्ष का हौसला दे सकते हैं और कैसे किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित कर सकते हैं। डिजिटल युग में 'क्रिएटर' और 'टूल्स' की भीड़ के बीच पाठकों के अटूट भरोसे की जरूरत पर भी मंथन हुआ।*

मीडिया लोकतंत्र की आत्मा: रहाटकर

विजया रहाटकर

पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को कोटा में 'पत्रिका की-नोट' के तहत 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि मीडिया समाज की आंख, कान और आवाज है। मीडिया महिला उत्पीड़न के मामले में पीड़िता की पहचान गुप्त रखकर महिलाओं की मदद करता है। मीडिया लोकतंत्र की आत्मा है। महिलाओं की सफलताओं की जानकारी देकर मीडिया महिलाओं में हौसला भरती है। उनको आगे और आत्मनिर्भरता से बढ़ने में मदद करती है। मीडिया के शब्द किसी महिला को शिकायत दर्ज करने का साहस दे सकते हैं। मीडिया के शब्द समाज सोच बदलने में दिशा दे सकते हैं। सभी मिलकर काम करें तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। महिला आयोग मीडिया को सूचना का माध्यम ही नहीं समाधान का साझेदार मानती है। जब मीडिया बताता है कि कोई महिला सरपंच शानदार काम कर रही है।

टूल्स-क्रिएटर के युग में तथ्यों की पहचान जरूरी

प्रो. निमित रंजन चौधरी

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित रंजन चौधरी ने कहा कि टूल्स और कंटेंट क्रिएटर के इस दौर में तथ्यों की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सूचना तंत्र के बदलते स्वरूप पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज मीडिया में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज भी पाठक तथ्यों की पुष्टि के लिए अखबारों पर भरोसा करते हैं। तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन उसे हावी नहीं होने देना चाहिए। आज लोग टूल्स और क्रिएटर दोनों की भूमिका में हैं। टूल्स के माध्यम से जब कोई व्यक्ति किसी डेटा को सर्च करता है तो वह जानकारी कितनी तथ्यपरक है, यह स्पष्ट नहीं होता। वहीं, कई बार क्रिएटर अपनी व्यक्तिगत राय को तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, जिस पर लगातार टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय तेजी से बदल रहा है। ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए मीडिया को सजग, सतर्क और जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी।

कृषि में आत्मनिर्भर होना आवश्यक: पाटीदार

पद्मश्री हुकुम चंद पाटीदार

पद्मश्री हुकुम चंद पाटीदार ने कहा कि समय-समय पर कृषि और किसानों की स्थिति पर गंभीर मंथन की आवश्यकता है। उन्होंने पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के लेख 'रुपया किलो बिकता कैंसर' का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी देश उसी दिशा में सोचने को मजबूर है। देश आजादी की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है और 'विकसित भारत' की परिकल्पना की जा रही है। रक्षा, आर्किटेक्चर सहित कई क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आज भी लगभग 70 करोड़ किसान कृषि पर निर्भर हैं। किसान एक-एक दाना चुनकर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन किसान और उसकी कृषि आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत का किसान और उसकी कृषि आत्मनिर्भर है। दुनिया की बड़ी-बड़ी बीज कंपनियों ने किसानों को अपने अधीन कर रखा है। हाइब्रीड बीज किसानों के सामने परोसे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। किसानों को गहने बेचकर बीज खरीदना पड़ रहा है।

देर रात हुई उर्स की पहली महफिल

रजब के चांद का दीदार, गरीब नवाज का 814वां उर्स शुरू

अजमेर @ पत्रिका. इस्लामिक माह रजब का चांद रविवार को नजर आने के साथ ही सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स की विधिवत शुरुआत हो गई। महफिल खाने में उर्स की पहली महफिल में सूफियाना कलाम पेश किए गए। देर रात मजार शरीफ पर गुस्ल की रस्म अदा की गई। रजब माह की पहली तिथि सोमवार को होगी।

चांद देखने के लिए शहर क़ाज़ी तौसीफ अहमद सिद्दीक़ी की सदारत में बैठक हुई। बड़े पीर की पहाड़ी से तोप दागकर और दरगाह परिसर में शादियाने व नगाड़े बजाकर चांद दिखाई देने की घोषणा की गई।

आज का राशिफल सोमवार, 22 दिसंबर, 2025

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

मेष: **क्षमता से अधिक परिश्रम करने का दबाव बन सकता है।** नई तकनीकी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा हो सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ बिताया गया समय लाभकारी रहेगा।

वृषभ: **परिस्थितियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा।** भाग्य का समर्थन मिलने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नए संपर्क बनाने का सही समय है। अधिकारों का कोमलता से प्रयोग करें।

मिथुन: **स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।** आध्यात्मिक यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त रहने की संभावना रहेगी। बचत खर्च होने से मानसिक दबाव महसूस करेंगे। परिस्थितियों का आकलन करें।

कर्क: **भावनात्मक संबंधों में साथी की ओर से थोड़ी शुष्कता अनुभव करेंगे।** परिस्थितियां व्यवस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं देंगी। यात्रा टालना अच्छा रहेगा।

सिंह: **विरोधियों को संभालने के लिए मशक्कत करनी होगी।** नई संधियां भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी। परिश्रम का पूरा लाभ तुरंत मिलना मुश्किल रहेगा।

कन्या: **सभी का सहयोग मिलने से कार्य सरलता से बनते चले जाएंगे।** पूर्व किए गए आर्थिक आकलन सही सिद्ध हो सकते हैं। लाभ की स्थितियां बनेंगी। जीवन में आरोप लगने की संभावना है।

तुला: **मित्रों का व्यवहार थोड़ा स्वार्थपूर्ण हो सकता है।** आपको नीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय के फैलाव के लिए योजना बनेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक: **परंपराओं की अवहेलना करके आलोचनाओं का शिकार हो सकते हैं।** कार्यों में गतिशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक संबंधों में परस्पर सहयोग करना पड़ सकता है।

धनु: **किसी खास कार्य के पूर्ण होने से निश्चिंतता अनुभव करेंगे।** बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। यात्रा प्रवास में बहुमूल्य वस्तुओं का ध्यान रखना होगा।

मकर: **दोपहर बाद व्यवस्थाओं पर पकड़ मजबूत होगी।** रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। प्रयास करने होंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा।

कुंभ: **कार्यस्थल पर आपको लेकर नकारात्मकता का वातावरण रह सकता है।** सूझबूझ से परिस्थितियों को संभालना होगा। जीवन शैली में बदलाव लाने के प्रयास होंगे। धन खर्च हो सकता है।

मीन: **अति आत्मविश्वास में बड़े फैसले लेने से बचना होगा।** परिवार के साथ राय मशविरा करके आगे बढ़ना आगे आने वाली समस्याओं से बचाएगा। लोगों को अपना प्रतिभा दिखाने के मौका।

ग्रह-नक्षत्र

शुभ वि. सं:	2082	हिजरी संवत :	1447	ऋतु:	शिशिर ऋतु
संवत्सर का नाम:	सिद्धार्थ	मु.मास:	रज्जब 01	मास:	पौष
शाके संवत:	1947	अयन:	उत्तरायण	पक्ष:	शुक्ल

आज का दिन

सोमवार, 22 दिसंबर, 2025

सूर्योदयकालीन लग्न व ग्रह स्थिति

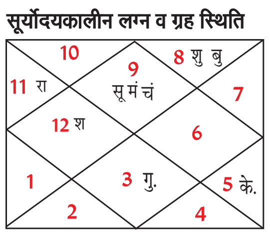

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से 8.33 तक, शुभ का 9.51 से 11.08 तक रहेगा, चर का चौघड़िया 1.42 से 3.00 तक तथा लाभ व अमृत के चौघड़िए 3.00 से सूर्यास्त तक रहेंगे।
तिथि: द्वितीया तिथि दिन 10.52 तक रहेगी, तदुपरांत तृतीया तिथि होगी।
दिशाशूल: आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा।
राहु काल वेला: (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक।

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अंतरात्रि 5.32 तक रहेगा, तदुपरांत श्रवण नक्षत्र होगा।

योग: ध्रुव योग दिन 4.40 तक रहेगा, तदुपरांत व्याघात योग रहेगा।

करण: कौलव करण दिन 10.52 तक रहेगा, तदुपरांत तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग: सर्वार्थसिद्धि योग अंतरात्रि 5.32 सूर्योदय तक, रवियोग अंतरात्रि 5.32 से प्रारंभ।

व्रत/दिवस विशेष: राष्ट्रीय गणित दिवस, गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन जयंती, राष्ट्रीय पौष मास प्रारंभ, उर्स मेला शुरु अजमेर (राज.)।

चंद्रमा: दिन 10.07 तक धनु राशि में होगा, तदुपरांत मकर राशि में प्रवेश होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे: आज दिन 10.07 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि धनु होगी, तदुपरांत मकर राशि होगी। अंतरात्रि 5.32 तक जन्म लेने वाले बच्चों का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा, तदुपरांत श्रवण नक्षत्र होगा। इन बच्चों का ताम्र पाद होगा। इनके प्रथम नामाक्षर भे, भो, ज, जि, खी पर रखे जा सकते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं, परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं।

निजी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे प्रश्न पत्र

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बीकानेर. राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षा आगामी 7 मार्च से शुरू होगी। इसमें कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी शामिल होंगे। जिन विषयों की परीक्षा समय सारिणी में शामिल नहीं हैं, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी स्कूलों के प्रश्न पत्र संबंधित यूसीईईओ एवं पीईईओ के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के लिफाफे खुले पाए गए, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीईईओ और यूसीईईओ की होगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यथासंभव उन्हें पुलिस थानों में रखने की व्यवस्था की जाएगी। यदि प्रश्न पत्र किसी कारण से पीईईओ या यूसीईईओ कार्यालय अथवा विद्यालय में रखे जाते हैं, तो वहां 24 घंटे कार्मिकों की ड्यूटी और रात्रिकालीन पहरा अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र कहां रखे जाएंगे, इसका अंतिम निर्णय जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।

भारत माला हाईवे पर हादसा, यातायात बाधित

ट्रक और ट्रेलर टकराए, लगी आग, चालक जला

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जोधपुर/ओसियां. ओसियां थानान्तर्गत गगाड़ी क्षेत्र में रतननगर व चण्डालिया के बीच भारत माला हाईवे पर रविवार देर रात मूंगफली से भरे ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया और उसमें आग लग गई। फिर मूंगफली से भरा ट्रक भी जल गया। एक चालक जिंदा जल गया और उसके साथी के भी जिंदा जलने की आशंका है। ग्रामीणों व दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास देर रात तक जारी था। टाइल्स बनाने में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी से भरा एक ट्रेलर पंजाब से गुजरात जा रहा था। रात दस बजे ट्रेलर आगे चल रहे मूंगफली से भरे ट्रक से जा टकराया। ट्रेलर में आग लग गई।

यातायात डाईवर्ट: आग ने कुछ ही देर में ट्रेलर और फिर ट्रक का पिछला हिस्सा चपेट में ले लिया था। आग इतनी भीषण थी कि लपटें की दूर तक नजर आने लगी। इससे वहां खौफ व्याप्त हो गया। भारतमाला पर यातायात बाधित हो गया। वाहनों को दूसरे मार्ग पर डाईवर्ट किया गया।

खेलों से स्वास्थ्य मजबूत करने पर जोर

डेजर्ट वॉरियर बीएसएफ मैराथन, धावकों ने दिया फिटनेस का संदेश

जैसलमेर. डेजर्ट वॉरियर बीएसएफ मैराथन में शामिल धावक।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जैसलमेर. सीमा सुरक्षा बल की ओर से सीमाओं की सुरक्षा के साथ जनसामान्य में स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को डेजर्ट वॉरियर-बीएसएफ मैराथन का आयोजन किया गया।

बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर दक्षिण और पीक डायनामिक स्पोर्ट्स के सहयोग से पूनमसिंह स्टेडियम में प्रातः 6:30 बजे से 11 बजे तक यह आयोजन हुआ। मैराथन का आयोजन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन की तीन श्रेणियों में किया गया। प्रतियोगिता में कुल 2854 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 2201 बीएसएफ व अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान, 393 नागरिक धावक और 260 बच्चे शामिल रहे। आयोजन में महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। 72 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक की सहभागिता ने यह साबित किया कि फिटनेस के साथ उम्र केवल एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। इसके साथ ही विदेशी धावकों की मौजूदगी ने स्वर्णनगरी जैसलमेर में आयोजित इस मैराथन को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दिलाई।

माउंट आबू-आबूरोड मार्ग पर हादसा

बस दीवार से टकरा कर पलटी, 17 घायल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

आबूरोड/माउंट आबू. पर्यटन स्थल माउंट आबू में आबूरोड-माउंट आबू मार्ग पर वीर बावसी मंदिर के पास रविवार दोपहर करीब 3 बजे 60 पर्यटकों से भरी निजी बस पलट गई। गनीमत रही कि बस सुरक्षा दीवार से टकराकर सड़क पर ही पलटी, अन्यथा गहरी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में 17 यात्री घायल हो गए, जिन्हें आबूरोड के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद से आए पर्यटक माउंट आबू भ्रमण के बाद बस से वापस लौट रहे थे। आरना गांव के पास अचानक बस अनियंत्रित हो गई। सूचना पर माउंट आबू डीएसपी गोमाराम, थानाधिकारी दलपतसिंह राठौड़, आबूरोड सदर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे पर्यटकों को बाहर निकाला।

माउंट आबू, अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी बस।

ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब मांगा

जोधपुर @ पत्रिका. राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामला जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील स्थित ओढ़ाणिया ग्राम पंचायत से जुड़ा है। न्यायाधीश डा पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने कहा कि ओढ़ाणिया ग्राम पंचायत में पिछले कई वर्षों से सरपंच, ग्राम सेवक और अन्य कार्मिकों ने आपसी मिलीभगत से लाखों रुपए का गबन किया। आरोप है कि स्कूल की दीवार निर्माण और रंग-रोगन के नाम पर राशि निकाली गई, जबकि आरटीआई में संबंधित विद्यालय ने ऐसे किसी कार्य से इनकार किया। सरकार ने जांच के लिए समिति तो गठित की, लेकिन रिकॉर्ड मांगने पर सरपंच और ग्राम सेवक एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे।

14 वर्षीय बेटी का गला रेतकर हत्या

खमनोर. (राजसमंद) @ पत्रिका. नेड़च गांव में एक पिता ने रविवार दोपहर 14 साल की बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। नेड़च गांव में मेघवाल बस्ती निवासी जशोदा (14) की उसके पिता नारायणलाल मेघवाल ने गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस फरार आरोपी पिता की तलाश कर रही है।

मिट्टी में दबा मिला युवक का शव

चूरू @ पत्रिका. रतननगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 स्थित सिंगापुर हब के पास रविवार को एक युवक का शव मिट्टी में दबा मिला है। शव मिलने की सूचना पर जहां इलाके में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया हत्या कर शव को दबाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

नवाचार | 30 दिसम्बर को आएगा यूडीन का मोबाइल ऐप, नया पोर्टल भी किया लॉन्च

सीए अब अपने मोबाइल से कर सकेंगे ऑडिट, दस्तावेज वेरीफाइड

गजेंद्र सिंह दहिया
patrika.com

जोधपुर. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) के लिए कामकाज को और अधिक डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आइसीएआइ) ने बड़ा कदम उठाया है।

आइसीएआइ ने शनिवार को नया और उन्नत यूडीन वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जबकि 30 दिसंबर को यूडीन का मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद सीए अपने मोबाइल फोन से ही ऑडिट रिपोर्ट सहित अन्य प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों का यूडीन जनरेट, डाउनलोड, रद्द और वेरीफाइ कर सकेंगे। यूडीन (यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर) आइसीएआइ की ओर से जारी 18 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जिसे हर सीए को अपने द्वारा जारी रिपोर्ट, सर्टिफिकेट या ऑडिट दस्तावेज पर अंकित करना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य फर्जी प्रमाणपत्रों और गलत दस्तावेजों पर रोक लगाकर पेशे की विश्वसनीयता बनाए रखना है। यूडीन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और अब देश में यूडीन की कुल संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है।

अधिक संख्या में यूडीन हो सकेगा

नए वेब पोर्टल को आइसीएआइ डिजी-सीए प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। पहले की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस, सुरक्षित और सुगम यूडीन मैनेजमेंट, रेगुलेटर्स व प्राधिकरणों के लिए बल्क यूडीन वेरिफिकेशन की सुविधा रहेगी।

यूडीन मोबाइल एप से क्या बदलेगा

यूडीन मोबाइल एप सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके जरिए सीए कहीं भी, कभी भी से जुड़ी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। एप से यूडीन जनरेट करने, देखने, डाउनलोड करने और रिवोक करने की सुविधा मिलेगी।

गत ऑडिटर का विवरण अनिवार्य

आइसीएआइ ने अनुपालन को और मजबूत करने के लिए यूडीन पोर्टल पर एक अहम बदलाव भी लागू किया है। अब जीएसटी और टैक्स ऑडिट से संबंधित यूडीन बनाते समय पिछले वर्ष के ऑडिटर का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। सदस्यों को यह बताना होगा कि पिछले वर्ष ऑडिट किसने किया था, संबंधित ऑडिटर का एमआरएन या एफआरएन क्या है, उनसे संवाद किया गया या नहीं और पिछली ऑडिट फीस बकाया है या नहीं।

पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम

इससे ऑडिट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। पेशेवर शिष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और अनुपालन का स्तर मजबूत होगा। नया यूडीन पोर्टल उपयोग में आसान है और इससे आवश्यक जानकारियां सही तरीके से दर्ज हो सकेंगी।

धवल कोठारी, सदस्य, आइसीएआइ जोधपुर चेप्टर

चिंताजनक • सुप्रीम कोर्ट के बाद सीएक्यूएम व सरकारी विशेषज्ञों ने भी उठाए सवाल

'ग्रैप' लागू है...फिर भी दमघोंटू हवा कहां से आ रही

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंचने और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा 'ग्रैप' के चारों चरण लागू किए जाने के बावजूद प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकारी निकायों के बीच आपसी समन्वय और जवाबदेही के अभाव में ग्रैप के नियमों का धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। दस माह पूर्व सत्ता में आई भाजपा सरकार पिछली सरकारों को कोसकर अपनी विफलताएं छिपाने का प्रयास कर रही है। केंद्र, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस जैसे निकायों की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। सीएक्यूएम की पुष्टि के अनुसार, प्रतिबंध के बावजूद खुले में कूड़ा और जैव-द्रव्यमान (बायोमास) जलाने की घटनाएं निरंतर जारी हैं। अवैध रूप से संचालित उद्योग, अनियंत्रित निर्माण कार्य और सड़कों की खुदाई से उड़ती धूल प्रदूषण को और घातक बना रही है।

विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशासनिक 'नाकारापन' को घेरा

रोहिणी के निवासियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को सरकारी निकायों की लापरवाही पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, "मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कें खोदकर बिना तारकोल और मिट्टी ढके छोड़ दी गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही पर भारी धूल उड़ रही है। सड़कों की मरम्मत न होना, यांत्रिक सफाई का अभाव और धूल-दमन उपायों की कमी ने समस्या को विकराल बना दिया है।" उन्होंने एमसीडी, डीडीए और डीपीसीसी को तत्काल 'जियो-टैग्ड रिपोर्टिंग' और 'साप्ताहिक संयुक्त निरीक्षण' के माध्यम से कठोर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है।

जगदीश ममगांई का सरकार पर निशाना

वरिष्ठ भाजपा नेता और एकीकृत निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ममगांई भी दिल्ली सरकार की विफलता गिना चुके हैं। कहा, एमसीडी व सरकार कूड़ा जलाने पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही है।

परिवहन के बजट को 60% बढ़ायाः सीएम

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, परिवहन विभाग पर वर्तमान बजट में 60 % अधिक राशि का प्रावधान किया है। वर्तमान बजट में परिवहन विभाग के लिए 9,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

शिकंजा • 35-40 हजार रुपए में बेचता था मोबाइल, करोल बाग में कर्मियों के साथ चल रहा था गिरोह

चीन से पार्ट्स इम्पोर्ट कर नकली प्रीमियम मोबाइल असली बताकर बेच रहा था युवक

असेंबल किए हुए 512 प्रीमियम मोबाइल फोन, 124 मदरबोर्ड संग गिरोह का मास्टरमाइंड हकीम अरेस्ट

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

अगर आप करोल बाग से सैमसंग के प्रीमियम मोबाइल खरीद रहे है और सोच रहे है कि वह असली है तो सावधान हो जाए...यह खबर आपके लिए खास है। यहां आठवीं पास युवक अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर चीन से सैमसंग मोबाइल के पार्ट्स इम्पोर्ट कराकर उन्हें असेंबल करने के बाद 35-40 हजार रुपये में बेचता था। सेंट्रल जिले के स्पेशल स्टाफ ने करोल बाग में इस गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हकीम, मेहताब अहमद अंसारी, रवि आहूजा और राहुल के रूप में हुई है। आरोपी हकीम गिरोह का मास्टरमाइंड है।

दुकान में करता था मोबाइल पार्टस को असेंबलः वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी एक दुकान के अंदर मोबाइल असेंबल करते थे और बाद में उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। पुलिस ने इनके पास से आधे-अधूरे असेंबल किए हुए 512 प्रीमियम मोबाइल फोन, 124 मदरबोर्ड, 138 बैट्री, 459 नकली आईएमईआई लेबल और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपी नकली मोबाइल को असली बताकर 35–40 हजार रुपये प्रति यूनिट बेचते थे। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अभी तक कितने लोगों को ऐसे मोबाइल बेच चुके हैं।

चोरी के इस्तेमाल किए मोबाइल फोन मामले पर हुई छापेमारी

डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि आरोपियों को एसीपी ऑपरेशन सुलेखा (आईपीएस) के नेतृत्व में इंस्पेक्टर रोहित कुमार, एसआई मनोज सोलंकी, रोहित, एएसआई प्रमोद मीना, हेड कांस्टेबल मुनेश शर्मा, धीरज, विकास, मनीष और कांस्टेबल,. लोकेंद्र, . सुरज पाल और मनीष की टीम ने पकड़ा है। गत 13 दिसंबर को स्पेशल स्टाफ को एक खास गुप्त सूचना मिली कि करोल बाग के बीडनपुरा में स्थित एक दुकान में चोरी के इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन खरीदे जा रहे हैं।

वह पुराने मदरबोर्ड और चीन से आयातित मोबाइल पार्ट्स का इस्तेमाल करके नए दिखने वाले प्रीमियम सैमसंग मोबाइल फोन अवैध रूप से असेंबल कर रहे है।

नकली आईएमईआई नंबर चिपकाए जा रहे थे

डीसीपी निधिन वाल्सन ने कहा, इन फोन पर नकली आईएमईआई नंबर चिपकाए जा रहे थे और उन्हें बाजार में नए ब्रांडेड प्रीमियम मोबाइल के रूप में बेचा जा रहा था। सूचना मिलते ही टीम ने उस दुकान के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इसके बाद टीम ने देर रात को दुकान पर छापा मार। टीम को दुकान के अंदर चार लोग मोबाइल असेंबल करते हुए मिले। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हकीम, मेहताब अहमद अंसारी, रवि आहूजा और राहुल के रूप में हुई। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर आगे की छानबीन कर रही है। आरोपियों ने बताया कि हकीम, जो सिर्फ 8वीं पास है और उसके पास कोई टेक्निकल डिग्री या औपचारिक योग्यता नहीं है, इस गिरोह का मास्टरमाइंड था।

नया सैमसंग मोबाइल बनाता था

दुकान का मालिक होने के नाते, वह चीन से सैमसंग मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स जैसे मदरबोर्ड, स्पीकर, कैमरे, बैक ग्लास, बॉडी फ्रेम और नकली आईएमईआई स्टिकर इम्पोर्ट करता था। बाद में अपने कर्मचारियों की मदद से वह सैमसंग अल्ट्रा, फोल्ड और फ्लिप मॉडल असेंबल करता था, चूंकि बाजार में इनकी बहुत डिमांड थी। ये नकली मोबाइल ग्राहकों को असली नए सैमसंग हैंडसेट बताकर धोखे से 35,000 से 40,000 रुपये प्रति यूनिट में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाता था।

किशनगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े दो बदमाश, जांच जारी

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

साउथ-वेस्ट जिले की किशनगढ़ थाना पुलिस ने एक चोर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है पकड़े गए आरोपियों की पहचान फूलचंद (33) और राहुल पटेल (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक चोरी का मोबाइल बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इलाके में मोबाइल चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए एसएचओ अजय कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम ने आरोपी को देखा था।

रोडरेज में युवक पर ई रिक्शा चालक ने चाकू से किया हमला

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

नॉर्थ वेस्ट जिले के अशोक विहार थाना इलाके में रोडरेज में ई रिक्शा चालक ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल की पहचान अरविंद के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में ई रिक्शा चालक को पकड़ लिया है। खबर लिखे जाने तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक इस मामले में पीड़ित ने बयान नहीं दिए है, इसलिए अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 1.30 बजे अशोक विहार थाना पुलिस को चाकू लगने के संबंध में पीसीआर कॉल मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक खून से लथपथ हालात में मिला। पुलिस उसे लेकर अस्पताल गई, जहां उसका उपचार किया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को पकड़ लिया है। जांच में पुलिस को पता चला कि रोडरेज में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।

प्रेम जाल में फंसाकर 16 वर्षीय किशोरी को साथ लेकर गया युवक, गिरफ्तार

पुलिस ने किशोरी को किया बरामद, आरोपी पर यौन उत्पीड़न का लगा आरोप

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 24 वर्षीय विकास को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे अपने लेकर चला गया। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को उसके परिजनों को सौप दिया है। बेटी के मिलने के बाद परिजन काफी खुश है और वह पुलिस धन्यवाद कर रहे है। वहीं किशोरी ने युवक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि गत 19 दिसंबर की रात किशोरी अचानक अपने घर से लापता हो गई। सुबह जब परिजनों ने उसे कमरे में नहीं पाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 दिसंबर को परिजनों ने भलस्वा डेयरी थाने में उसके अपहरण की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और किशोरी की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि किशोरी उसके घर पर पानी सप्लाई करने वाले युवक विकास के साथ चली गई है। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से विकास का पता लगाया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से किशोरी को भी बरामद कर लिया।

गैस रिसाव के कारण घर में लगी आग, 50 मिनट में पाया काबू

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

साउथ ईस्ट जिले के जैतपुर एक्सटेंशन इलाके में गैस रिसाव होने के कारण रविवार सुबह एक मकान में आग लग गई। आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे के वक्त मौके पर अफरातफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

दमकल विभाग के मुताबिक दमकल विभाग को सुबह करीब 9:00 बजे आग लगने की सूचना मिली। आग जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-एक, झील गार्डन के पास जी-ब्लॉक स्थित मकान नंबर 192 में आग लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की तीन गाड़ियां पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने 50 मिनट में आग पर काबू पाया। जांच में पुलिस को पता कि सुबह उठाने के दौरान जैसे ही वह उठे और चाय बनाने के लिए गए।

डीजेबी के ट्रक की चपेट में आने से चालक की मौत, केस

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी, चल रही छापेमारी

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के ट्रक की चपेट में आने से एक रैपिडो चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जुबेर अली (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।

हादसे के बाद चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपी को तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 3.30 बजे गीता कॉलोनी थाना पुलिस को सड़क हादसे के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।

मौके पर पहुंची पुलिस को युवक खून से लथपथ मिला। पुलिस उसे लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बाद मे जुबेर अली के रूप में हुई। वह बागपत का रहने वाला था। परिवार में पिता अजमा अली, मां व चार भाई हैं। वह रैपिडो में काम करता था। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के वक्त वह कहां जा रहा था। हादसे के बाद से चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

कीर्ति नगरः चोरों ने लाखों के गहने व कैश लेकर हुए फरार

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

वेस्ट जिले के कीर्ति नगर थाना इलाके में बदमाशों ने एक घर से लाखों के गहने व कैश हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त पीड़िता अपने परिजनों के साथ मायके गई थी। मौके मिलते ही बदमाशों ने 10 लाख रुपये के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने पीड़िता पूजा की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों ने चोरी की बाइक पर आकर वारदात को अंजाम दिया था। बाइक राजौरी गार्डन इलाके से चोरी की गई थी।

पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक 16 दिसंबर को कीर्ति नगर थाना पुलिस को रमेश नगर इलाके के मकान नंबर 3/99, ग्राउंड फ्लोर में चोरी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़िता पूजा छाबड़ा मिली। उसने बताया कि वह गत 14 दिसंबर को अपने परिवार के साथ मायके गई हुई थी। 16 दिसंबर की सुबह जब वह घर लौटी तो देखा कि दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ।

बीयर की बोतल पर छपे बार कोड से मिला आरोपियों का सुराग, अरेस्ट

रील बना रहे युवक से माचिस मांगने पर बोतल से किया था हमला

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

सेंट्रल जिले के देश बंधु गुप्त रोड थाना इलाके में रील बना रहे एक युवक से माचिस मांगने को लेकर हुए िववाद में तीन लोगों ने उस पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। युवक के लहूलुहान होने के बाद वह फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत हत्या की कोशिश पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हम्माद उर्फ रिजवान (22), कामरान उर्फ सारिम (24) और फरजान (24) के रूप में हुई है। पुलिस को इनके पास से टूटी हुई बोतल बरामद की है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

15 दिसंबर को हुई थी घटनाः डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि गत 15 दिसंबर को देश बंधु गुप्त रोड थाना पुलिस को हत्या की कोशिश की एक घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ अजमल खान पार्क, करोल बाग में सोशल मीडिया रील्स बना रहा था। इसी दौरान शराब पी रहे तीन अनजान लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। एक आरोपी ने बीयर की बोतल तोड़कर नुकीले टूटे कांच से शिकायतकर्ता के सिर पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई।

बोतल के बार कोड से पुलिस ने खरीद वाले दुकान की पहचान की

टीम को मौके पर वारदात में इस्तेमाल की गई बीयर की बोतल का एक टूटा हुआ टुकड़ा बरामद किया। बोतल के टुकड़े पर एक बारकोड था, जो जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ। इसके बाद टीम ने उस दुकान का पता लगाया, जहां से शराब की बोतल खरीदी गई थी। इसके बाद टीम ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपियों की पहचान की। इसके बाद टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता से माचिस मांगी, लेकिन शिकायतकर्ता ने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने शिकायतकर्ता की जेबें चेक कीं। इसको लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी हम्माद पर 22 मामले दर्ज हैं।

मॉडल टाउन की घटना

चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर आरोपी फरार, केस दर्ज

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

नॉर्थ वेस्ट जिले के मॉडल टाउन इलाके में पुराने विवाद को सुलझाने के लिए बुलाकर एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल युवक की पहचान मोहित के रूप में हुई है। घायल को हालत गंभीर होने पर लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात मॉडल टाउन थाना पुलिस को गुड़मंडी में एक युवक को चाकू मारे जाने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल मोहित को दीप चंद अस्पताल ले जाया गया है। वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि राजपुरा गुड़मंडी निवासी मोहित के सीने के दाहिनी ओर चाकू का घाव है। घायल को लोक नायक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने पीड़ित को पुराना मामला सुलझाने के लिए बुलाया था। जब पीड़ित आरोपी के बुलाए जाने पर मौके पर आया तो उनके बीच फिर से विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान आरोपी ने अपनी कमर से चाकू से निकालकर युवक पर पीड़ित पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे वह जख्मी हो गया।

भास्कर खास साइबर टिपलाइन रिपोर्ट्स को देखने की नामित इकाई एनसीएमईसी सेल सक्रिय

दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई की पहल पर वर्ष 2025 में बाल अश्लीलता से जुड़े 60 मामले दर्ज, बच्चों से जुड़े कंटेंट पर लग रही रोक

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल सुरक्षा विशेष इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) की पहल पर वर्ष 2025 में बाल अश्लीलता और नाबालिगों के खिलाफ साइबर यौन अपराधों से जुड़े कुल 60 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में इसी विशेष इकाई से मिले इनपुट के आधार पर ऐसे 136 मामले दर्ज किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में से बड़ी संख्या साइबर टिप-ऑफ के आधार पर सामने आई, जो 'चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्यूज मटीरियल' (सीएसईएएम) से संबंधित थे। सीएसईएएम का मतलब बच्चों से जुड़े अवैध कंटेंट के ऑनलाइन प्रसार से है।

नवंबर व दिसंबर में 45 केस हुए दर्जः अधिकारियों के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री साझा करने वाले अपराधियों से जुड़े साइबर टिपलाइन इनपुट्स के आधार पर और एसपीयूडब्ल्यूएसी के समन्वय से नवंबर और दिसंबर में दिल्ली के विभिन्न जिलों में 45 एफआईआर दर्ज की गईं। दिसंबर में दोबारा अपराध करने वालों से जुड़े अतिरिक्त साइबर टिपलाइन इनपुट्स भी मिले, जिनमें गूगल सप्लीमेंटल फाइल्स के रूप में प्राप्त मामले शामिल थे। बीते दो महीनों में साइबर टिपलाइन पर समन्वित कार्रवाई से कुल 52 एफआईआर दर्ज हुईं। अधिकारियों ने बताया कि सभी मामलों में आगे की जांच जारी है।

परामर्श (काउंसलिंग) देने का भी कार्य करती है एसपीयूडब्ल्यूएसीः बाल शोषण से जुड़े मामलों के अलावा परामर्श (काउंसलिंग) भी एसपीयूडब्ल्यूएसी का एक प्रमुख कार्य रहा। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2015 से 19 दिसंबर 2025 तक एसपीयूडब्ल्यूएसी को इस तरह की कुल 3,578 शिकायतों में से 976 मामलों में, जब परामर्श पर्याप्त नहीं रहा और आपराधिक कार्रवाई जरूरी हुई, एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि 42 मामले घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2025 के बीच एसपीयूडब्ल्यूएसी ने 186 परामर्श में से 34 मामलों का समाधान परामर्श के बाद सुलह से हुआ, जबकि छह मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। इस दौरान वर्ष 2024 के सभी लंबित 36 मामले निपटाए गए।

यह है एनसीएमईसी सेल

एसपीयूडब्ल्यूएसी की एनसीएमईसी सेल दिल्ली में ऐसी साइबर टिपलाइन रिपोर्ट्स को देखने की नामित इकाई है। ये रिपोर्ट्स अमेरिका स्थित संस्था 'नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन' (एनसीएमईसी) से प्राप्त होती हैं, जिन्हें 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' के माध्यम से भेजा जाता है। यह केंद्र देशभर में साइबर अपराध से जुड़े इनपुट्स के समन्वय के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। सभी साइबर टिपलाइन इनपुट्स राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए भेजे जाते हैं। इन्हें मिलने के बाद एसपीयूडब्ल्यूएसी की एनसीएमईसी सेल प्रारंभिक जांच करती है, जिसमें सूचना की प्रामाणिकता और गंभीरता का आकलन किया जाता है। इसके बाद संबंधित पुलिस जिलों से जुड़े कार्रवाई योग्य इनपुट तैयार कर जिला इकाइयों को भेजे जाते हैं।

बस में विदेशी महिला के पर्स से चोरी किए 1600 अमेरिकी डॉलर, किए जब्त

पुलिस ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार किया, बस में छूटे पर्स से की चोरी

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

नॉर्थ जिले के कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने एक विदेशी महिला के पर्स से 1600 अमेरिकी डॉलर चोरी होने की गुत्थी को चंद घंटों में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनीष (26) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से लूटे गए 1600 अमेरिकी डॉलर बरामद किए है।

पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि गत 15 दिसंबर को पुलिस चौकी कश्मीरी गेट बस अड्डा को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. अली अकबर शाह ने एक शिकायत दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर को उनकी मेहमान फरिश्ते सयान जली (एक ईरानी नागरिक) अपने साथी यात्रियों के साथ भारत घूमने आई थी और शिकायतकर्ता के घर पर रुकी हुई थीं। बाद में वह उत्तराखंड चली गईं। 15 दिसंबर को वह एक फ्लिक्स बस से दिल्ली वापस आईं। दोपहर करीब 01:45 बजे जैसे ही आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस से उतरीं तो वह अपना पर्स बस में भूल गईं है।

बस ऑपरेटर ने उन्हें फोन कर बताया कि बस मे उनका पर्स छूट गया है। पर्स मिलने पर उन्होंने उसकी जांच की तो उसमें से 1600 अमेरिकी डॉलर चोरी हो चुके थे।

पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। आरोपी को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर प्रशांत यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। पूछताछ के दौरान बस के कंडक्टर और ड्राइवर से पूछताछ की गई। उन्होंने पुलिस को बताया कि पर्स हेल्पर मनीष ने उन्हें सौंपा था। मनीष पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ के दौरान वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके घर से 1600 अमेरिकी डॉलर बरामद किए।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

वैयक्तिक आकांक्षा नव्हे नाइलाज

''**जगण्या'चा जुगार**' हा अग्रलेख (२० डिसेंबर) वाचला. आज स्थलांतर ही केवळ वैयक्तिक आकांक्षा राहिलेली नाही, तर देशातील रोजगार व्यवस्थेच्या अपयशाचा तो थेट परिणाम आहे. अनेक भारतीय तरुण स्थिर, सुरक्षित आणि अर्थपूर्ण काम उपलब्ध नसल्यामुळे देश सोडतात. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विलंब, परीक्षा रद्द होणे किंवा निकाल रखडणे यामुळे प्रतीक्षा अनेक वर्षे वाढते. उद्योगांमध्ये टिकून राहणे कठीण झाले आहे. स्थानिक कामांच्या संधी कमी असणे हे आणखी एक मोठे कारण आहे. अनेक जण एजंटच्या आश्वासनांवर विसंबून कंबोडिया, म्यानमार किंवा रशियात जातात, जिथे त्यांना मानवी तस्करी, फसवणूक किंवा युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे स्थलांतर हा फक्त जागतिक संधींचा शोध राहिलेला नाही. देशातील सुरक्षित उपजीविकेच्या अभावातून सुटका करून घेण्याचा तो मार्ग ठरत आहे. भारतात ग्रामीण उद्योग, कृषिपूरक व्यवसाय आणि लघु उद्योग यांना सातत्यपूर्ण पाठबळ न मिळणे, तसेच मोठ्या प्रकल्पांचा सामान्य तरुणांना त्यांच्या रोजच्या आयुष्यात काहीही लाभ न होणे, हीदेखील प्रमुख कारणे आहेत. बेरोजगारी आणि असुरक्षित रोजगारामुळे 'इथे राहून काही साध्य होणार नाही' ही भावना बळावते आणि तरुण देश सोडण्याचा धोकादायक मार्ग स्वीकारतात. हे विदारक आहे.

■ **देवयानी गाडे,** खोपोली (रायगड)

संयुक्त राष्ट्रांचा पुढाकार हवा

''**जगण्या'चा जुगार**' हा अग्रलेख वाचला. अनियंत्रित लोकसंख्यावाढ हे स्थलांतराच्या समस्येचे मूळ कारण आहे. या बाबतीत सक्तीचे कायदे करता येत नाहीत असा निष्कर्ष काढता येईल. मग पर्याय म्हणून प्रत्येक धडधाकट व्यक्तीच्या हाताला काम मिळेल अशी व्यवस्था तरी केली पाहिजे. कौशल्य विकास संस्थात्मक झाला पाहिजे. कुवत व कल अजमावून मागेल त्याला काम दिले पाहिजे. तंत्रज्ञानप्रधान युगात रोजगार उपलब्ध होण्याकरता भांडवलप्रधान व्यवस्था आणावी लागते. मग सतत भांडवल गुंतवणूक होत राहील अशी व्यवस्था करावी लागते.

परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून प्रथम स्थानिकांना रोजगार द्यावा लागतो. आवश्यक ते कौशल्य स्थानिकांकडे पुरेशा प्रमाणात नसल्यास इतर देशांतील लोकांचे स्थलांतर होते. तेथेही 'आम्ही आणि इतर' असा संघर्ष होतो. काम मिळण्यासाठी घराबाहेर पडलेले स्थलांतर यात होरपळतात. काही वेळा त्यांना मूळ देशात परत जावे लागते. दुसरे स्थलांतर युद्धामुळे होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निरपराध नागरिकांना युरोप आणि अमेरिकेत आसरा घ्यावा लागला. तेथेही जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. प्रत्येक देशाचे स्थलांतरितांना आश्रय देण्याचे कायदे वेगळे. बहुतेक देशांत स्थलांतर बेकायदा आहे, पण जसे परदेशांतील भांडवल चालते, तसे परदेशांतून आलेल्यांच्या श्रमांनाही कायदेशीर मान्यता असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून स्थलांतरित परवड थांबेल. हा पेच सोडवण्याच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्र संघाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

■ **श्रीकृष्ण फडणीस,** दादर (मुंबई)

संधी निर्माण करणे हाच पर्याय

''**जगण्या'चा जुगार**' हे संपादकीय वाचले. देशातील विविध शैक्षणिक, सामाजिक पार्श्वभूमीतून आलेले तरुण रोजगाराच्या शोधात परदेशांत जात आहेत. यातील अनेकांना केवळ पर्याय नाही म्हणून परदेशात जावे लागते. उच्चशिक्षितांना आपल्या देशासाठी योगदान न देता अन्यत्र जावे लागल्याची खंत वाटते. तर अशिक्षित, अर्धशिक्षितांना परदेशात गेल्यानंतर फसवणूक झाल्याच्या भावनेचा सामना करावा लागतो. त्यातही परदेशात एखादे संकट आले, युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली, तर परक्या देशात अडकून पडण्याची वेळ येते. डार्विनचा 'सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट' सिद्धांत हे स्थलांतरितांचे क्रूर वास्तव आहे. अशी फसवणूक होऊ नये यासाठी प्रशासनाने जनजागृती मोहीम राबवावी. तसेच अनधिकृत कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करून तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध होतील, याकडे लक्ष द्यावे.

■ **राघवेंद्र मण्णूर,** डोंबिवली

हा देशाच्या भविष्याशी खेळ

'**राज्यात गेल्या** पाच वर्षांपासून दीड लाख विद्यार्थी शिष्यवृत्तीविना' ही बातमी (लोकसत्ता- २१ डिसेंबर) वाचली. सरकारची कीव आली. शिक्षण हे भावी पिढीसाठी आणि देशाच्या भवितव्यासाठीही अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना समान संधीही मिळणे गरजेचे आहे. असे असताना शिष्यवृत्ती वेळेवर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल तर विद्यार्थ्यांच्या वाटेत अनंत अडथळे येतात. यातून काही विद्यार्थी शिक्षणही सोडून देतात. त्यामुळे हा विषय गंभीर आहे. या प्रश्नाकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे.

■ **नामदेव राव,** नवीन पनवेल

राज्यात सहकार-संस्कृती लयाला

''**सहकार-संस्कृती'साठी** चळवळ हवी' हा रविवार विशेषमधील लेख (२१ डिसेंबर) वाचला. सहकार-संस्कृतीमुळे महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले, सहकारी बँकांचा विकास झाला आणि सामान्य माणसाला दिलासा मिळाला, पण आज साखर कारखाने हे राजकीय वर्चस्व दाखविण्याचे माध्यम ठरत आहे. सहकारी बँका सतत बुडीत जात असल्याने जनता साशंक झाली आहे. अशातच रिझर्व्ह बँकेचेसुद्धा सहकारी बँकांबाबतचे धोरण फारसे सकारात्मक नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये तसाही सहकार कमीच दिसतो. हे सर्व पाहता सहकार-संस्कृती पुन्हा एकदा सर्वांना शिकविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या फायद्यासाठी करण्याच्या वृत्तीला पायबंद घातला तरच खराखुरा सहकार दिसून येईल.

■ **माया भाटकर,** पुणे

अभ्यासक्रमासाठी पात्रता निकष काय?

'**नाशिकमध्ये पूजाविधी** पौरोहित्य प्रशिक्षण' असे शीर्षक असलेले वृत्त (लोकसत्ता- १९ डिसेंबर) वाचले. आयटीआयसारख्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांत हा उपक्रम राबविला जाणार असल्याचे वाचून हसू आले. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची ही संकल्पना असून त्याअंतर्गत ही २१ दिवसीय कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. या कार्यशाळेला विज्ञानाचा आधार आहे का? तसे नसेल, तर शिक्षणसंस्थांत धार्मिक उपक्रम का राबविला जात आहे? यात प्रवेशाची पात्रता काय, प्रशिक्षण देणाऱ्यांच्या पात्रतेचे निकष कोणते, हेदेखील समजले असते तर बरे झाले असते.

■ **व्ही. टी. जाधव**

शोषण आहे, तोवर कम्युनिस्ट पक्ष आहे

'**भारतीय कम्युनिस्ट** पक्षाची शंभर वर्षे' हा डॉ. तेजोमयी भालेराव यांचा लेख (२१ डिसेंबर) वाचला. शंभर वर्षांत कम्युनिस्ट पक्षाचे अनेक तुकडे झाले. कार्यक्षेत्र आणि व्याप्ती मर्यादित राहिली, मात्र तो आजही टिकून आहे. धर्म हा ज्या देशाचा आत्मा व पाया आहे त्या देशात कम्युनिस्ट पक्षाने ही वाटचाल कशी केली, हा राजकीय विश्लेषकांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरू शकतो. या पक्षाने पददलित, श्रमिकांवरची निष्ठा ढळू दिली नाही. स्वार्थापोटी तत्त्वांशी तडजोड केली नाही. जगाच्या इतिहासाचे अवलोकन केले तर ही बाब स्पष्ट होते की, आधुनिक काळातही मार्क्सवाद ही एकमेव विचारसरणी आहे जी गोरगरिबांच्या, दुर्बलांच्या बाजूने लढते आहे. मात्र आज कम्युनिस्टांना लोकशाहीविरोधक ठरवण्याचे षड्यंत्र सत्ताधारी रचताना दिसतात. त्यांना इतर पक्षही साथ देतात.

संघराज्य शासन पद्धती मजबूत करण्यात कम्युनिस्ट पक्षाने पुढाकार घेतला होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी कॉम्रेड डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने लढा दिला. पुढे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड आणि क्रांतिवीर नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जमीनमुक्तीचा लढा देण्यात आला. आज या पक्षासमोर नवी आव्हाने उभी आहेत. जगात अनेक देशांत कम्युनिस्ट पक्ष आजही सत्तेत आहेत आणि इतर देशांमध्ये विविध स्वरूपात कार्यरत आहे. जगात अन्याय, शोषण आहे तोपर्यंत डावा विचार राहील. भारतात सामाजिक विषमता खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळे सैद्धांतिकदृष्ट्या तरी भारत ही नेहमीच डाव्यांसाठी सुपीक भूमी ठरली, मात्र मूळ स्वदेशी समाजवादी परंपरा भारतीय कम्युनिस्टांनी अधिक चांगल्या पद्धतीने आत्मसात करून घेतली पाहिजे. आजच्या विकृत व्यवस्थेतील क्रौर्य, नैतिक आणि आर्थिक शोषण ही अरिष्टे संपवण्यासाठी भांडवलशाहीचे उच्चाटन करण्याशिवाय पर्याय नाही. हे कम्युनिस्टांचे तत्त्वज्ञान आजच्या काळातही प्रासंगिक ठरते. जगात अनेक पक्ष येतील आणि जातील, मात्र भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्याची विचारसरणी कायम राहील.

■ **डॉ. बी. बी. घुगे,** बीड

पाश्चात्त्य आधुनिकतेची संध्याकाळ...

प्रबोधनपर्व म्हणजे मध्ययुगीन अंधकाराचा नाश करून समग्र मानवतेसाठी नव्या युगाचं क्षितिज दाखवणारी प्रकाशमय ऐतिहासिक प्रक्रिया. फ्रेंच राज्यक्रांतीमुळे ते क्षितिज दिसलंसुद्धा. पण पुन्हा एकोणिसाव्या शतकाला गडद सावल्यांनी घेरलं...

तत्त्व-विवेक

शरद बाविस्कर
जेएनयुतील अध्यापक
sharadcrosshuma@gmail.com

Bliss was it in that dawn to be alive.
- William Wordsworth

फ्रेंच राज्यक्रांतीचा उद्रेक १७८९ मध्ये झाला. जुन्या धर्माधिष्ठित राजवटीचा (L' Ancien régime) शेवट घडवून जगभरातील राजेशाहींना धडकी भरवणाऱ्या या घटनेमुळे फक्त फ्रान्समध्येच नव्हे तर संपूर्ण जगात उत्साहाचं आणि आशावादाचं वातावरण निर्माण झालं. कारण फ्रेंच राज्यक्रांती म्हणजे एका राजानं दुसऱ्या राजाची केलेली उचलबांगडी किंवा निव्वळ एक सत्तापालट नसून जगाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी घटना होती. एरवी तटस्थ किंवा खिन्न मानसिकतेत जगणाऱ्या तत्त्वज्ञांमध्येही या युगप्रवर्तक घटनेमुळे उत्सुकतेची आणि उल्हासाची भावना निर्माण झाली होती! पॅरिसपासून शेकडो मैल दूर कनिसबर्गमधील इमॅन्युएल कांटसारख्या जर्मन तत्त्वज्ञाला या घटनेत इतिहासानं टाकलेलं पुढचं पाऊल दिसलं. कांटच्या कठोर शिस्तबद्धतेविषयी अनेक आख्यायिका प्रसिद्ध आहेत. कांटने मोजून दोनदाच त्याचा सायंकाळचा फेरफटका चुकवला होता असं म्हटलं जातं. पहिल्यांदा रूसोचं पुस्तक वाचण्यात गर्क झाल्यामुळे आणि दुसऱ्यांदा फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या बातमीमुळे! खरं तर, कांट फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या उदारमतवादी टप्प्याचा समर्थक होता. पण फ्रेंच राज्यक्रांतीनं रोबेस्पिएरच्या नेतृत्वाखाली रक्तरंजित वळण घेतलं तेव्हा फ्रेंच राज्यक्रांती कांटच्या 'मर्यादित' ज्ञानक्षमतेपलीकडे जाणारी राजकीय घटना ठरली.

इंग्लंडमध्येसुद्धा थॉमस पेन आणि प्रसिद्ध कवी विल्यम वर्ड्सवर्थसारखे विचारवंत, कवी फ्रेंच राज्यक्रांतीनं भारावून गेले होते. वर्ड्सवर्थनं तर फ्रेंच राज्यक्रांतीचा उल्लेख नव्या युगाची पहाट म्हणून केला आहे. तो म्हणतो, 'त्या पहाटेचा साक्षीदार असणं परमसुख होतं!' स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव या मूल्यत्रयीचा जगभर प्रसार करण्याचा विडा उचलणाऱ्या नेपोलियनबद्दल प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञ हेगेलला तर Weltseele zu Pferde अर्थात जागतिक इतिहासाचा आत्मा अश्वारूढ होऊन आगेकूच करीत आहे असं वाटलं. हेगेलच्या नजरेत प्रबोधनपर्वाच्या मुक्तिदायी विचारांनी प्रेरित नेपोलियनच्या लष्करी मोहिमा म्हणजे साक्षात मानवी स्वातंत्र्याचं आणि स्वभानाचं ऐतिहासिक प्रकटीकरण.

१४ जुलै १७८९ रोजी बास्तीईच्या पाडावानंतर फ्रेंच राज्यक्रांतीची सुरुवात झाली आणि अवघ्या दीड महिन्यात राष्ट्रीय घटनासभेत 'वैश्विक मानवी आणि नागरिकांच्या हक्कांची घोषणा' करण्यात आली. ही ऐतिहासिक घोषणा म्हणजे प्रबोधनपर्वाच्या तत्त्वज्ञानात्मक गाभ्याचं राजकीय प्रकटीकरण होय. या घोषणेच्या मानवतावादी तर्कांतर्गत गुलामगिरीच्या प्रथेचं निर्मूलन करणं क्रमप्राप्त होतं. त्यामुळे रोबेस्पियरच्या नेतृत्वाखाली १७९४ मध्ये अधिकृतपणे गुलामगिरीच्या प्रथेचं निर्मूलन करून फ्रेंच वसाहतींमध्ये राबणाऱ्या लाखो गुलामांना मुक्त करण्यात आलं. पण फ्रेंच राज्यक्रांतीनं घेतलेली ही तात्त्विक झेप आणि तत्कालीन वास्तव यांत मोठी दरी होती. अठराव्या शतकात आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचनेचं केंद्र उमराव वर्गापासून व्यापारी बुर्ज्वा वर्गाकडे सरकलं होतं खरं; पण राजकीय सत्ता मात्र उमराव वर्गाच्या हातातच होती. त्यामुळे फ्रेंच राज्यक्रांतीकडे बुर्ज्वा वर्गानं स्वतःच्या आर्थिक सत्तेला अनुरूप उमराव वर्गाकडून राजकीय सत्ता काबीज करण्याची घटना म्हणून पाहता येतं. त्याअर्थी, फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान झालेला प्रबोधन विचारांचा जागर म्हणजे सर्वार्थानं पिचलेल्या कष्टकरी वर्गाला बुर्ज्वा वर्गानं दाखवलेलं मुक्तीचं गाजर ठरतं.

फ्रेंच राज्यक्रांतीचा संकोच एका ठरावीक स्पष्टीकरणात करणं अशक्य असलं तरी एक गोष्ट मात्र नक्की की, रोबेस्पिएरच्या पतनानंतर बुर्ज्वा वर्ग फ्रेंच राज्यक्रांतीला हवं तसं वळण देण्यात यशस्वी झाला. विशेषकरून, नेपोलियनच्या उदयानंतर बुर्ज्वा वर्गानं प्रबोधनपर्वाचा मानवतावादी प्रकल्प स्वतःपुरता सीमित करून श्रमिक वर्गाला तसंच ताटकळत ठेवलं. एवढंच नव्हे तर १८०२ मध्ये फ्रेंच वसाहतवाद्यांच्या भांडवलवादी तर्कासमोर शरण जाऊन नेपोलियननं अध्यादेश काढून गुलामगिरीची प्रथा परत प्रस्थापित केली. मात्र नेपोलियनच्या या कृतीत त्याचाच एके काळचा विश्वासू लष्करी अधिकारी लुई दलग्रेसला प्रबोधनपर्वाच्या उदात्त तत्त्वज्ञानाचा घात दिसला. त्यामुळे फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या मूल्यांशी प्रतारणा करणाऱ्या नेपोलियनच्या विरोधात दलग्रेसनं बंड पुकारून कॅरिबियनमधील कृष्णवर्णीयांना संघटित करून गुआडालुप बेटावर निकराचा लढा सुरू ठेवला. दलग्रेसचं बंड चिरडून टाकण्यासाठी नेपोलियननं रिशपॉन्स या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली लष्करी कारवाई सुरू केली. शेवटी लुई दलग्रेससह शेकडो कृष्णवर्णीयांना सेंट चार्ल्सच्या किल्ल्यात घेरण्यात आलं. मात्र लुई दलग्रेसनं शरणागती पत्करण्याऐवजी किल्ल्यातल्या दारूगोळ्याला पेटवून Live free or die! च्या घोषणा देत शेकडो समर्थकांसह आत्मदाह केला. लुई दलग्रेसची वैचारिक जडणघडण प्रबोधनपर्वाच्या विचारांमध्ये झाली होती. त्यानं त्याच्या शेवटच्या उद्गारात प्रबोधन-प्रकल्पानं दाखवलेलं मानवमुक्तीचं भव्य स्वप्न आणि वस्तुस्थिती यांमधली दरी अधोरेखित केली आहे. खरं तर, ही घटना आधुनिकतेच्या गर्भपाताचं ठळक उदाहरण समजलं जातं!

याआधी आपण पाहिलं की, तत्त्वज्ञानाचं लोकाभिमुखीकरण हे प्रबोधनपर्वाचं महत्त्वाचं योगदान समजलं जातं. कारण प्रबोधनपर्वात मानवमुक्तीच्या विचारांची चर्चा आणि चिकित्सा करून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याची ऐतिहासिक मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यामुळे प्रबोधनपर्व आधुनिकतेचा परमोच्च बिंदू ठरतो. एका बाजूला स्वातंत्र्य, समता, बंधुतासारख्या आधुनिकतेच्या मूल्यांविषयी जनतेच्या जाणिवेत वाढ झाली; पण दुसऱ्या बाजूला मात्र भौतिक वास्तव ठामपणे विषमतावादीच राहिलं.

त्यापुढल्या शतकात...

एकोणिसाव्या शतकात तर पाश्चात्त्य भांडवलवादी, वसाहतवादी, साम्राज्यवादी सत्तारूढ वर्गानं प्रबोधन प्रकल्पाचं (Project of Enlightenment) अपहरण केलं आणि आधुनिक मूल्यव्यवस्थेचा वापर नव्यानं उदयाला येणाऱ्या विषमतावादी व्यवस्थेचा नैतिक बुरखा म्हणून करण्यात आला. ही आधुनिक विषमता धर्माधिष्ठित नसली तरी तिला भेदताना माणसांमधील मानवतेचा चुराडा कसा होतो याचं चित्रण बाल्झाक, एमिल झोला, चार्ल्स डिकन्स यांच्यासारख्यांच्या साहित्यात दिसतं.

सोबतच एकोणिसाव्या शतकात कार्ल मार्क्स, सिग्मंड फ्रॉईड, फ्रेडरिक नित्शे, चार्ल्स डार्विन, फर्डिनांड द सोस्यूर यांच्यासारख्यांनी प्रबोधन-प्रकल्पाच्या मुळाशी असलेल्या एकजिनसी कार्टेशियन 'स्व'च्या सार्वभौमत्वाच्या आणि स्वामित्वाच्या भावनेला जोरदार तडाखे दिले. प्रबोधनाचं तत्त्वज्ञान एकजिनसी विवेकशील व्यक्तीच्या विचारशीलतेला अग्रक्रम देतं. पण एकोणिसाव्या शतकातल्या या विचारवंतांनी दाखवून दिलं की, व्यक्तींच्या वर्तनाला नेणिवेतल्या विविध गोष्टी प्रभावित करत असतात. उदाहरणार्थ, कार्ल मार्क्सच्या नजरेत व्यक्तींच्या जीवनाला मुळात आर्थिक संरचना आणि हितसंबंध प्रभावित करत असतात. त्यामुळे त्यांची सार्वभौम विवेकशीलता भ्रांतमय ठरते. डार्विनच्या दृष्टीनं 'मानव' ही संकल्पना सतत प्रश्नांकित केली पाहिजे; कारण आपल्यातला पशू (animal) मरत कधीही नसल्यानं आपलं जनावर (beast) होऊ शकतं. डार्विनचे विचार प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक एमिल झोलाच्या La bête humaine अर्थात The Human Beast या दीर्घ साहित्यकृतीत प्रतिबिंबित होतात.

सिग्मंड फ्रॉईडसुद्धा प्रबोधन-प्रकल्पाच्या कार्टेशियन कर्ता आणि ज्ञाताच्या मुळावर प्रहार करतो. मनुष्याच्या जाणिवेच्या पातळ आवरणापलीकडे नैसर्गिक प्राण्याचं दमन झालेलं असल्याने मनुष्याची दृश्य प्रतिमा त्याच्या वास्तव अस्तित्वाविषयी फार कळू देत नसते. सोस्यूरची भाषाविषयक मांडणीसुद्धा सार्वभौम कार्टेशियन ज्ञाता आणि वक्त्याच्या स्वातंत्र्याविषयी मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते. त्याच्या मांडणीनुसार - भाषा म्हणजे दोन स्वतंत्र विवेकशील व्यक्तींमधल्या संवादाचं पोकळ साधन नसून भरीव वास्तव आहे. सामाजिक व्यवस्था म्हणून भाषा तुमचं पूर्वनिर्धारित स्थान निश्चित आणि मर्यादित करू पाहते.

'फ्रॅन्कफर्ट स्कूल'ची टीका

खरं तर, प्रबोधनपर्वात आकाराला आलेल्या मूल्यांची चौफेर चिकित्सक चर्चा होऊन टोकाचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. उदा.- विसाव्या शतकातल्या फ्रॅन्कफर्ट स्कूलच्या अडोर्नो आणि होर्कायमर यांसारख्या विचारवंतांनी तर Dialectics of Enlightenment या ग्रंथात प्रबोधनपर्वाच्या मध्यवर्ती दाव्यालाच छेद देऊन प्रबोधनपर्वाच्या तत्त्वज्ञानानं मानवतेचा उत्कर्ष साधण्याऐवजी साम्राज्यवाद, वसाहतवाद, भांडवलवाद, बकाल शहरीकरण, महायुद्ध, ज्यूंचं शिरकाणसारख्या अनिष्ट गोष्टी शक्य करून मानवतेला विनाशवादी खाईत लोटलं असा युक्तिवाद केला आहे. दुसऱ्या बाजूला मात्र हेसुद्धा विसरता येणार नाही की हिटलर सत्तारूढ होताच त्याचा प्रचारमंत्री जोसेफ गोबेल्स १९३३ मध्ये रेडिओवरल्या प्रक्षोभक भाषणात जाहीर करतो की, '१७८९ हे वर्ष इतिहासातून पुसून टाकलं जाईल!' कारण फ्रेंच राज्यक्रांतीचे मानवी हक्क, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव ही तत्त्वे नाझी राजवटीत अप्रस्तुत ठरतात!

थोडक्यात, आधुनिकतेच्या केंद्रभागी असलेल्या कार्टेशियन 'स्व'च्या सार्वभौमत्वाच्या आणि स्वामित्वाच्या भावनेला झालेल्या जखमांमुळे एकोणिसाव्या शतकात आधुनिकता पूर्णपणे संकटग्रस्त झाली. मात्र याच काळात, प्रबोधन तत्त्वज्ञानाच्या पाश्चात्त्यकेंद्री दृष्टिकोनाला बाद करून इतर परंपरांमधील प्रबोधन तत्त्वज्ञानांचं उत्खनन करण्यात आलं. कारण प्रबोधन-प्रकल्पातल्याच विचारांप्रमाणे मानवमुक्तीचं तत्त्वज्ञान कुण्या एका स्थळकाळाची मक्तेदारी असू शकत नाही. तशी मक्तेदारी मानणं हे विषमतावादीच. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाश्चात्त्य साम्राज्यवादी, वसाहतवादी, भांडवलवादी शक्तींनी प्रबोधन तत्त्वज्ञानाचा विपर्यास केला म्हणून प्रबोधन-प्रकल्पातील लोकशाहीचे विचार पूर्णपणे बाद करता येत नाही. कारण तसं करणं म्हणजे throwing the baby out with the bathwater ठरेल.

या लेखात उपस्थित केलेल्या प्रबोधनोत्तर पैलूंची सविस्तर आणि सखोल चर्चा करण्यासाठी आणखी एक लेखमाला आवश्यक आहे. तूर्तास पुढल्या- २९ डिसेंबरच्या लेखापर्यंत थांबू.

कुतूहल

इथेनॉलचे उद्योगविश्व!

इंधनाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. खनिज तेलाचे व कोळशाचे साठे ५०-६० वर्षांत संपुष्टात येतील. सध्या इंधन म्हणून वापरात असलेल्या खनिज तेलांना भविष्यात पर्याय निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

माणसाला मद्यार्क निर्माण करण्याचे तंत्र अनादीकालापासून अवगत आहे. मद्यार्कात इथेनॉल हा मुख्य घटक असतो. शर्करामय पदार्थ, स्टार्चयुक्त धान्ये, कंदमुळे, फळेही इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरतात. त्यात किण्वनासाठी यीस्ट वापरतात. शर्करेचे इथेनॉल आणि कार्बन डायऑक्साइडमध्ये रूपांतर होते. ग्लुकोजच्या एका रेणूपासून इथेनॉलचे दोन रेणू व कार्बन डायऑक्साइडचे दोन रेणू तयार होतात. त्यानंतर ऊर्ध्वपातन प्रक्रियेद्वारे इथेनॉलची मात्रा वाढवली जाते. विविध कर्बोदकांपासून मद्यार्क निर्मितीचे उद्योग अर्थकारणाला चालना देत आहेत. हेन्री फोर्डने २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला आपली गाडी इथेनॉलवर चालवण्याचा प्रयत्न केला होता.

अमेरिका हा सर्वांत मोठा इथेनॉल उत्पादक आहे. त्यांनी २०२१ आणि २०२२ मध्ये १५ अब्ज गॅलनपेक्षा जास्त इथेनॉलचे उत्पादन केले आहे. अमेरिका आणि ब्राझील एकत्रितपणे जगातील ८० टक्के इथेनॉलचे उत्पादन करतात. अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते, तर ब्राझीलमध्ये उसाचा वापर केला जातो. पुण्यातील प्राज उद्योगविश्वाचे 'इथेनॉल मॅन' डॉ. प्रमोद चौधरी यांनी जैवऊर्जेचे महत्त्व जाणून ७५ देशांमध्ये उद्योग विस्तारलेला आहे. भारतात 'बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड' हा इथेनॉल तयार करणारा सर्वात मोठा उद्योग आहे. त्याची ऊस गाळप क्षमता एक लाख ३६ हजार टन प्रति दिन इतकी असून इथेनॉल तयार करण्याची क्षमता ८०० लिटर प्रति दिन इतकी आहे.

प्रश्न असा आहे की, इथेनॉल पेट्रोलची जागा घेऊ शकते का? इथेनॉल हे पेट्रोलऐवजी वापरता येणारे पर्यायी इंधन आहे. पण दोन्हींची ऊर्जा देण्याची क्षमता समान नसते. पेट्रोलसाठी कोणते पर्यायी इंधन किती प्रमाणात वापरल्यास ते पेट्रोलच्या एका गॅलनइतकी ऊर्जा देऊ शकते; याची तुलना करण्यासाठी 'गॅसोलीन गॅलन समतुल्यता' (जीजीई) हे एकक वापरतात. त्यानुसार इथेनॉलची जीजीई किंमत पेट्रोलपेक्षा १.५ पट आहे. याचा अर्थ इथेनॉल स्वस्त असले तरी पेट्रोलइतकी ऊर्जा मिळवण्यासाठी इथेनॉल जास्त प्रमाणात लागते. यामुळे प्रत्यक्ष वापरात ते महाग पडते.

इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रण म्हणून वापरण्याची भारताची क्षमता २०२५ साली १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढल्यामुळे भविष्यकालीन शाश्वत ऊर्जेच्या क्षेत्रात इथेनॉल महत्त्वाचे ठरू शकते.

-डॉ. जयश्री कृष्णा सैनिस
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

भारतात मौखिक परंपरेतून, अनुभवांतून आलेले पिढीजात ज्ञान मुबलक. त्यामुळेच कदाचित, त्याचे मोल ओळखण्यात आणि ते मान्य करण्यात आपण अनेकदा कमी पडतो. केरळचे वनस्पती शास्त्रज्ञ पद्मश्री डॉ. पाल्पू पुष्पांगदन यांनी मात्र ही त्रुटी दूर केली. आदिवासींकडून मिळालेल्या पारंपरिक ज्ञानाचा आधार घेत त्यांनी औषधनिर्मितीशास्त्रात योगदान तर दिलेच, मात्र त्याच्या श्रेयात त्या आदिवासींना वाटेकरी करून घेण्यास ते विसरले नाहीत. डॉ. पुष्पांगदन यांची औषधनिर्माणशास्त्रातील कामगिरी उल्लेखनीय होतीच, पण ते वेगळे ठरले या सामाजिक न्यायाच्या जाणिवेमुळे.

डॉ. पुष्पांगदन हे त्यांनी विकसित केलेल्या 'जीवनी' या रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणाऱ्या औषधामुळे ओळखले जातात. या औषधाच्या निर्मितीचा प्रवास विशेष आहे. औषधी गुणधर्म असलेल्या वनस्पतींच्या शोधासाठी ते केरळमधील अनेक जंगले, डोंगर पालथे घालत. या शोधप्रवासात त्यांची भेट तिथल्या कानी जमातीतील आदिवासींशी झाली. तिरुवनंतपुरम परिसरातील अगस्त्य टेकडीवर १९८७ साली ट्रेकिंग करताना त्यांना थकवा जाणवू लागला. सोबतच्या कानी आदिवासी व्यक्तीने त्यांना एका रानफळाचा रस दिला. तो पिऊन त्यांना ताजेतवाने वाटू लागले. ते फळ 'आरोग्यपाच' (Trichopus zeylanicus) या नावाने ओळखले जाते. आदिवासी त्याचा वापर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी करत.

डॉ. पाल्पू पुष्पांगदन

कानींना त्यांच्या जंगलात दडलेल्या वैभवाची जाण होती. त्यांचे हे परंपरागत ज्ञान जगासाठी उपलब्ध व्हावे यासाठी डॉ. पुष्पांगदन यांनी प्रयत्न सुरू केले, मात्र आदिवासी माहिती देण्यास तयार नसत. हे वैभव जगापुढे आले तर जैवविविधता ओरबाडून नष्ट केली जाईल, अशी भीती त्यांना होती. डॉ. पुष्पांगदन यांनी त्यांना- तुमच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही- याची शाश्वती दिली. त्या फळावर सात वर्षे संशोधन करून त्या आधारे 'जीवनी' हे टॉनिक त्यांनी तयार केले. १९९६ साली कोइंबतूरस्थित एका कंपनीने हे औषध व्यावसायिक स्वरूपात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले. त्यातून होणारा लाभ कंपनी आणि आदिवासींत समान विभागला जाईल असा करार झाला. या पैशांचा योग्य विनियोग व्हावा म्हणून केरळ 'कानी समुदाय क्षेम ट्रस्ट' स्थापन करण्यात आला. आता हा ट्रस्ट शिक्षण आरोग्य व सामाजिक विकासासाठी काम करतो.

सामाजिक श्रेयाचे हे मॉडेल 'पुष्पांगदन मॉडेल' म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारले गेले. 'कन्व्हेन्शन ऑफ बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी' (१९९३) या संयुक्त राष्ट्रांच्या करारातही त्याचा समावेश करण्यात आला. या कार्याची दखल घेत संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना 'इक्वेटर इनिशिएटिव्ह पुरस्कारा'ने गौरविले. 'राष्ट्रीय वनस्पतीशास्त्र संशोधन संस्था' (केरळ) आणि 'ट्रॉपिकल बोटॅनिकल गार्डन अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट' (लखनऊ)च्या संचालकपदाची धुरा त्यांनी सांभाळली. लखनऊमध्ये त्यांच्या प्रयत्नांतून 'प्लांट कॉन्सर्वेशन बँक' सुरू झाली. त्यांच्या संशोधनातून पुढे आलेली अनेक औषधे आज विविध देशांत उपलब्ध आहेत. डॉ. पाल्पू पुष्पांगदन यांचे नुकतेच निधन झाले. संशोधनातील प्रगतीचे इमले सामाजिक न्यायाच्या पायावर बांधले जावेत यासाठी त्यांनी घालून दिलेला पायंडा यापुढे पाळत राहणे हीच त्यांना योग्य आदरांजली ठरेल.

तर्कतीर्थ विचार

सव्यसाची समीक्षक तर्कतीर्थ

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी सैल हातांनी प्रस्तावना लिहिल्या; मात्र, समीक्षा लिहिल्या त्या हात आखडता घेत. असे का करावे त्यांनी. त्याचा विचार करता लक्षात येते की, प्रस्तावना लेखन नाही म्हटले तरी प्रशस्ती लेखन असते. पुस्तक समीक्षा वा परीक्षण मात्र जबाबदारी असते आणि जोखीमही. अत्यंत निवडक व्यक्तींच्या निवडक ग्रंथांची समीक्षा करीत तर्कतीर्थांनी त्या त्या लेखकांना एका अर्थाने प्रतिष्ठा मिळवून दिली. या समीक्षा लिहितानाही मराठी समीक्षक सामान्यतः ज्या ग्रंथांना हात लावणार नाहीत, असेच ग्रंथ तर्कतीर्थांनी समीक्षार्थ निवडले. जे निवडले ते स्वतःची आवड या निकषावर, शिवाय भावल्याशिवाय तर्कतीर्थांनी समीक्षा लेखन केले नाही. समीक्षक सव्यसाची असला पाहिजे, अशी तर्कतीर्थांची बहुधा धारणा असावी. लक्ष्यवेधकाला फक्त मत्स्यभेदाचा ध्यास हवा, शिवाय उभय हातांनी लीलया मत्स्यभेद करता यायला हवा- अर्जुनाप्रमाणे!

ह. कृ. मोहिनी, चिं. ग. काशीकर, भा. पं. बहिरट, डॉ. वा. वि. मिराशी, डॉ. के. ल. दप्तरी, डॉ. ग. श्री. खैर, डॉ. रा. चिं. ढेरे, डॉ. मु. श्री. कानडे ही सारी मंडळी एकाच धारेचे लेखन करणारी. सनातन धर्म, सांस्कृतिक इतिहास, भक्ती मार्ग, वेदोपनिषद, सदाचार, मनुस्मृती, ऋग्वेद, लज्जगौरी, महामाया हे मराठी साहित्याचे रूढ विषय नव्हेत. असलेच तर ही लेखनाची अनवट वाट म्हणायची. त्यांचे ग्रंथही तसे मराठी सर्वसामान्य वाचकांसाठी अनघड, अनभिज्ञ वाटावेत असे. 'संशोधन मुक्तावली', 'अमृतानुभवकौमुदी', 'संतवाणीचा अमृतकलश', 'नाट्यविचार', 'औपनिषदिक जीवनसौख्य', 'उपनिषदर्थव्याख्या' म्हणजे शीर्षक समजून घेण्यापासून श्रीगणेशा! 'चणे खावे लोखंडाचे' अशा शिवधनुषी हिकमतीने तर्कतीर्थांनी या समीक्षा लिहिल्या, म्हणजे अपवाद विषयांना साहित्याच्या वाचन प्रवाहात रूढ करण्याचा हा प्रयत्न नि खटाटोप! तर्कतीर्थांची लेखकीय मूळ बैठक तार्किक, तात्त्विक लेखनाचीच, त्यास शोभेल अशाच या समीक्षा. निवडकांची निवड नेहमी अभिजाततेच्या सीमांना स्पर्शणारी असते. या समीक्षा लेखनाने ही उपपत्ती मोहर ठेवून जाते.

वरील प्रकारच्या ग्रंथांच्या समीक्षा तर्कतीर्थांनी आत्मस्वर (इनर व्हॉइस) म्हणून लिहिल्या; पण रसिक मन घेऊन जन्मलेले तर्कतीर्थ हे मानवेंद्रनाथ रॉय, प्रा. मे. पुं. रेगे, डॉ. पां. वा. काणे यांच्यात जसे रमायचे, तितकेच ते कुमार गंधर्व, पु. ल. देशपांडे यांच्यामध्येही! समीक्षेतही हे चित्र दिसते. वरील मांदियाळीशिवाय पसंदिदा लेखन (राइटर्स चॉइस) म्हणून तर्कतीर्थांनी डॉ. इरावती कर्वे यांच्या 'युगान्त', गोविंद तळवलकरांच्या 'सत्तांतर १९४७', यशवंतराव चव्हाण यांच्या 'कृष्णाकाठ' ग्रंथांची केलेली समीक्षा रियाजापलीकडचे गाणे म्हणता येईल. ही मराठी साहित्य क्षितिजावरची तशी स्थितप्रज्ञ मंडळी! काही त्यांना 'शिष्ट' म्हणूनही संबोधत. असे सांगितले गेले आहे की, 'नवभारत', 'आकाशवाणी'वर आपल्या ग्रंथाची तर्कतीर्थांनी समीक्षा केल्याचे नुसते ऐकूनही या स्थितप्रज्ञ मंडळींच्याही गालावर खळी पडली होती म्हणे!

तर्कतीर्थ टीकाकार नव्हते, होते समीक्षक! सम्+इक्ष या व्युत्पत्तीनुसार ते साहित्य कृतींकडे, त्यातील गुणदोषांकडे समशील वृत्तीने पाहात, 'सुखदुःखे समे कृत्वा, लाभालाभौ जया-'जयौ''च्या कृष्णकृत उपदेशानुसार या सव्यसाची समीक्षकांनी साहित्याकडे पाहिले म्हणून त्यांच्या समीक्षा वाचनीय, विचारणीय अशा दखलपात्र मानल्या गेल्या. 'तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी समग्र वाङ्मय'चे खंड १७ नि १८ क्रमशः 'तीर्कतीर्थ स्मृतिगौरव' व 'तर्कतीर्थ साहित्यसमीक्षा संग्रह' होत. सुमारे शतकभराच्या कालखंडात शे-दीडशे विद्वानांनी यात लेखन केलेले दिसते; पण 'समीक्षक तर्कतीर्थ' अशा अंगाचा लेख शोधूनही सापडत नाही.

''तर्कतीर्थांचे लेखन 'एन्सायक्लोपीडिस्ट राइटिंग' सदरात मोडते. यात व्यापक विद्वत्ता, चिंतन गांभीर्य, उत्कटता, ऋजुता, नेटका युक्तिवाद, तर्क, तत्त्व साऱ्यांचा कसा मधुर मिलाप असतो,'' असे प्रा. मे. पुं. रेगे यांनी तर्कतीर्थांच्या वैचारिक वाटचालीचे वर्णन करताना म्हटले होते. ते तर्कतीर्थांच्या समीक्षेसही तंतोतंत लागू पडते, तर्कतीर्थांची मराठी कळायला मराठी-इंग्रजी शब्दकोशाचा आधार घ्यावा लागतो, असे भाई माधवराव बागल 'हिंदुधर्माची समीक्षा' हा ग्रंथ वाचून त्याचा तर्कतीर्थांना अभिप्राय देत एकदा म्हणाले होते. यात तर्कतीर्थ लेखन पद्धतीचे मार्मिक भाष्य दडलेले आढळते.

- डॉ. सुनीलकुमार लवटे
drsklawate@gmail.com

बेहाल बांगलाचा बोध!

बांगलादेशातील दोन्ही उद्रेकांमध्ये भारताविरुद्धचा राग हा प्रमुख धागा असल्याने आपण त्याकडे पुन्हा दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरेल...

लोकशाही केवळ असून चालत नाही. ती जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या नियामक यंत्रणा ताठ कण्याने उभ्या असाव्या लागतात. त्या तशा नसतील, तर काय होते याचे आपला दुसरा शेजारी बांगलादेश हे उत्तम उदाहरण. त्या देशातील अंतर्गत उद्रेकाचा एक आवेग संपून दुसरा सुरू झाला आहे. पहिल्याने तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा घोट घेतला. दुसरा आवेग या देशास आणखी अस्थिर करेल. येत्या फेब्रुवारीत त्या देशात सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत. त्या देशातील दोन प्रमुख राजकीय पात्रांच्या अनुपस्थितीत होऊ घातलेली ही कित्येक वर्षांतील पहिलीच निवडणूक. शेख हसीना या भारतात आणि त्यांच्या प्रमुख राजकीय विरोधक बेगम खालिदा झिया या अत्यवस्थ. या दोघींशिवाय तेथे इतर राजकीय नेता नाही. त्या अनुक्रमे अवामी लीग आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) या दोन मोठ्या पक्षांच्या नेत्या.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात हसीनांविरोधात विद्यार्थी आंदोलन सुरू झाले, त्यास सार्वत्रिक निवडणुकीची पार्श्वभूमी होती. त्या वेळी सत्तारूढ अवामी लीगने बीएनपीला निवडणूक लढू दिली नाही. त्यातून उठलेला राजकीय वणवा अखेर सत्ताधीशांनाच भस्मसात करून शमला. आता बांगलादेशचे हंगामी प्रभारी मोहम्मद युनुस हे हसीनांच्या चुकीची पुनरावृत्ती करत आहेत. त्यांनी या वेळी अवामी लीगवर बंदी घातली. त्या देशात राजकीय पक्ष फार नाहीत. ईन मीन दोन-तीनच. त्यात लोकसंख्या अवाढव्य. त्यातही पुन्हा नोकरदारांपेक्षा राजकीय कार्यकर्त्यांचे तांडेच जास्त. साहजिकच एखाद्या पक्षावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली की विरोधी जनक्षोभाचा स्फोट होतो. बीएनपीची मुस्कटदाबी झाली, त्यातून हसीनांचा राजकीय बळी गेला. आता अवामी लीगची मुस्कटदाबी झाल्यास, त्यातून आणखी किती बळी जातील, हे कोणीच सांगू शकत नाही. पण दोन्ही उद्रेकांमध्ये भारताविरुद्धचा राग हा प्रमुख धागा असल्याने आपण त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे अविचारी आणि धोकादायक ठरेल.

शरीफ ओस्मान हादी या तरुण राजकीय नेत्याच्या हत्येवरून बांगलादेशात ताजा आगडोंब उसळला. यातून उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया व्यापक आणि भयानक आहेत. ढाका आणि इतर अनेक भागांत मोर्चे निघाले. दोन वृत्तपत्रांची कार्यालये जाळण्यात आली. भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांवर हल्ले झाले. आणखी एके ठिकाणी एका हिंदू व्यक्तीस त्याने कथित प्रेषितनिंदा केल्याच्या आरोपावरून ठेचून मारले गेले आणि त्याचा मृतदेह झाडाला टांगून त्याचे जाहीर दहन करण्यात आले. प्रभारी शासक मोहम्मद युनुस अर्थतज्ज्ञ म्हणून योग्य असतीलही, पण राजकीय जबाबदारी त्यांना अजिबात पेलवलेली नाही. हसीनांच्या पलायनावेळी त्या देशात जवळपास निर्नायकी अवस्था निर्माण झाली म्हणून युनुस यांची सर्वानुमते हंगामी सरकारचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यांची प्रशासनावर पकड नाही हे एव्हाना सिद्ध झालेलेच आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आब राखू, अल्पसंख्याकांचे रक्षण करू, राजदूतावास, वाणिज्य कचेऱ्या आणि इतर परदेशी आस्थापनांचे रक्षण करू अशी हमी त्यांनी

> **तेथील जिहादी तत्त्वांना विद्यमान परिस्थितीत अंकुर फुटू लागले आहेत. याचा फायदा घेण्यास पाकिस्तान आणि चीन तर तयार आहेतच.**

अनेकदा दिली. एक तर ते स्वतः या आश्वासनांविषयी गंभीर नाहीत किंवा त्यांना बांगलादेशातील युवा राजकीय कार्यकर्ते मोजत नाहीत, हेच ताज्या घडामोडींनी पुन्हा सिद्ध केले. तेथील काही भारतीय व्हिसा केंद्रे बंद करावी लागली. मंदिरांवरील हल्ले कमी झाले असले, तरी थांबलेले नाहीत. गेल्या महिन्यात तेथील एका न्यायाधिकरणाने शेख हसीना यांना विविध गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंड आणि जन्मठेप अशी जबर दुहेरी शिक्षा ठोठावली. हसीना आमच्या लेखी न्यायसिद्ध गुन्हेगार असल्यामुळे, त्यांना आमच्याकडे सोपवावे ही बांगलादेशची मागणी आपण मान्य केलेली नाही. त्या न्यायाधिकरणाची निर्मिती मुळात हसीना यांचीच. शिवाय भारत आणि बांगलादेश यांच्यात गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाविषयी रीतसर करारही अस्तित्वात आहे. पण त्यांतील काही तरतुदींचा सोयीस्कर अर्थ लावून आपण हसीनांना बांगलादेश सरकारकडे सोपवणे टाळतो. ही बाब भारताला राजनैतिकदृष्ट्या अडचणीची ठरेलच. पण बांगलादेशातील जनतेतही आपल्याविषयी संताप आणि संशय वाढवणारी ठरेल. कधी तरी बांगलादेशात हसीनांचे समर्थक पुन्हा सत्तेवर येतील, मग हसीनांना पुन्हा बांगलादेशात पाठवता येईल आणि सारे काही सुरळीत होईल असे आपल्या राज्यकर्त्यांस वाटत असावे. ते वाटणे किती पोकळ आहे, हे अलीकडेच संसदेच्या परराष्ट्रविषयक समितीने दाखवून दिले. विद्यमान सरकारचे लाडके विरोधी पक्षीय शशी थरूर या समितीचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या मुत्सद्दी व्यवहार आकलनाविषयी शंका नाही. बांगलादेशाचा पेच १९७१ नंतर प्रथमच इतका गहन झाल्याचा इशारा थरूर यांची समिती देते. केंद्र सरकारची बांगलादेशविषयी धोरणात्मक पावले ही व्यक्तिकेंद्री असून, ती सरकारकेंद्री नाहीत हे या समितीचे निरीक्षण तर विशेष दखलपात्र. व्यक्तिकेंद्री धोरणामुळेच शेख हसीनांविषयी प्रमाणाबाहेर माया दाखवण्याची चूक आपण केली आणि त्यांच्याविरोधात विशेषतः करोनोत्तर बांगलादेशात फोफावलेल्या असंतोषाची नोंद घेऊ शकलो नाही. हसीनांचे प्रत्यार्पण न करता आपण त्यांना आश्रय दिला हे पाऊल व्यावहारिक आणि राजनैतिक दारिद्र्यसूचक कसे ठरते, याविषयी 'लोकसत्ता'ने 'हसीनांना हाकलाच' (१९ नोव्हेंबर) या संपादकीयातून मतप्रदर्शन केले होते. पण केवळ इतकाच मुद्दा नाही.

शरीफ ओस्मान हादी याचा मारेकरी फैसल करीम मसूद हा फरारी असून, त्यास भारताने आश्रय दिल्याचा आरोप आहे. त्यात तथ्य नाही असे गृहीत धरले, तरी याबाबत भारत सरकारकडून त्वरित आणि निःसंदिग्ध खुलासा हवा. कारण ऐकीव असत्य किंवा अर्धसत्य हे सत्य मानले जाण्यासाठी पोषक परिस्थिती तेथे आहे. हादी हा निवडणूक लढवणार होता आणि राजकीय पोकळी भरून काढण्यास तो उत्सुक होता. शेख हसीनांविरोधात गतवर्षी एका टप्प्यावर विद्यार्थी आंदोलन तीव्र झाले, त्या आंदोलनाचे नेतृत्व हादीकडे होते. तेथील कित्येक तरुणांच्या नजरेत तर तो बांगलादेशाचा भावी शासक आणि भाग्यविधाता होता. त्याचे गुण-दुर्गुण कोणते याविषयी व्यापक आणि निष्पक्ष मूल्यांकन झालेले नाही. तेव्हा त्यात पडण्याची गरज नाही. पण शेख हसीनांविरोधात वातावरण तापलेले असताना त्यांच्या एका युवकप्रिय विरोधकाची हत्या होणे ही बाब भारताची डोकेदुखी वाढवणारे ठरते हे तरी आपण कबूल केले पाहिजे.

कारण भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना मुख्य भूप्रदेशाशी जोडणाऱ्या 'चिकन नेक' मार्गिकेवर आघात करून त्या राज्यांना विलग करण्याची भाषा करणारे नेते तेथील मुख्य राजकीय प्रवाहात दिसू लागले आहेत. पाकिस्तानइतकी नाही, तरी बांगलादेशात जिहादी तत्त्वांची पाळेमुळे काही प्रमाणात रुजलेली होती. त्यांना विद्यमान परिस्थितीत अंकुर फुटू लागले आहेत. या पोषक स्थितीचा फायदा घेण्यास पाकिस्तान आणि चीन तर तयार आहेतच. भारतावर पश्चिमेकडून (पाकिस्तानातून) नव्हे, तर पूर्वेकडून (बांगलादेशातून) आक्रमण करून पश्चिमेकडे जिंकत सरकायचे, अशी दर्पोक्ती अलीकडेच पाकिस्तानचे तोंडाळ लष्करप्रमुख सैयद असिम मुनीर यांनी केली. इतिहासाविषयी आकलनशून्यच असे बोलू शकतात. पण बांगलादेशातील अस्थैर्य आटोक्यात आणण्यासाठी भारताचेही प्रयत्न हवेत. पाकिस्तानी चष्म्यातूनच दक्षिण आशियातील घडामोडींकडे पाहण्याची सवय असलेल्यांना बांगलादेशातील स्थिती हाताबाहेर जाणे म्हणजे काय याची कल्पना नाही. फाळणी झाली, तेव्हा ४५ टक्के भूभाग पाकिस्तानकडे आला आणि ५५ टक्के भूभाग बांगलादेशकडे. सबब, दक्षिण आशियातील इतका मोठा देश भारतविरोधी झाला आहे. इतकी वर्षे तो आपला घनिष्ठ मित्र होता या इतिहासात रमण्याची वेळ सरली. या बेहाल बांगलाचा बोध अनेकार्थांनी घ्यायला हवा.

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar
@expressindia.com

दिल्लीकर जिवंत तरी कसे?

> **प्रदूषित हवेमुळे दिल्लीकर हळूहळू मरू घातले आहेत, पण विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरल्यानंतरही संसदेत यावर चर्चा होऊ दिली गेली नाही. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना तर एक्यूआय हा तापमापक वाटतो. विविध देशांच्या दूतावासांनी आपल्या दिल्लीतल्या नागरिकांसाठी धोक्याचा इशारा दिला आहे. दोन दशकांत 'विकसित' होऊ पाहणाऱ्या देशासाठी हे अतिशय लाजिरवाणेच!**

तोंड काळे करायचे असेल तर दिल्लीत या, असे गमतीनेही म्हणायची सोय राहिलेली नाही. कारण, आत्ता दिल्लीत आलात तर खरोखरच तोंड काळे होईल! धुके आणि धूर यांचे मिश्रण म्हणजे धुरके. या धुरक्याचा अतिप्रचंड थर निर्माण झाला आहे. या थरातून गेलात की, तुम्हाला काहीही दिसणार नाही. तुमच्या नाका-तोंडात मात्र धूर, धूळ जात राहील. तुमचा चेहरा काळा होईल. तुम्ही थुंकलात तर तुमच्या तोंडातून काळी थुंकी बाहेर पडेल. 'प्रदूषणयुक्त अतिघातक' हे वर्गीकरणदेखील कमी पडेल इतकी दूषित हवा तुमच्या छातीत दर सेकंदाला जाते. तुम्हाला फुप्फुसाचे आजार कुठल्याही क्षणी होतील, याची भीती मनात बाळगून आणि जीव मुठीत धरून तुम्ही दिल्लीत वावरता. तुम्हाला न्यूमोनिया झाला तर अवस्था आणखी वाईट. हे वाचून कोणालाही वाटेल की, दिल्लीकर जिवंत कसे?

दिल्लीकर हळूहळू मरू घातले आहेत. प्रदूषित हवेमुळे माणूस लगेच मरत नाही. विषारी वायू तुम्ही दररोज दरसेकंदाला नाकाने शरीरात घेत जाता, फुप्फुसे कालांतराने कमकुवत होत जातात. दिल्लीतील वायूप्रदूषणामुळे फुप्फुसाचे आजार होऊन लोक मरतात, पण तशी कोणतीही आकडेवारी केंद्र सरकारकडे नसल्याचे अजब लेखी उत्तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने संसदेमध्ये याच हिवाळी अधिवेशनात दिले. करोनाच्या काळात प्राणवायूच्या पुरवठ्याअभावी करोनाचा एकही रुग्ण दगावलेला नाही, असा अजब दावा त्या वेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केला होता. तसाच हा भन्नाट दावा आहे. फक्त दिल्लीतच नव्हे, उत्तरेच्या संपूर्ण पट्ट्यात हवेची गुणवत्ता इतकी वाईट आहे की, निकृष्टतेचे बहुधा नवे निर्देशांक तयार करावे लागतील! दरवर्षी दिल्ली-एनसीआर आणि उत्तरेकडील राज्यांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होतो. मात्र तो राजकीय मुद्दा ठरत नाही. या वर्षी हवेच्या प्रदूषणाने दिल्लीकरांच्या संयमाची परिसीमा ओलांडली. आताही हा मुद्दा राजकीय झाला नाही तर २०४७च्या कथित 'विकसित भारता'च्या उद्दिष्टालाही अर्थ उरणार नाही, हे निश्चित.

खरे तर या वेळी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहांत दिल्लीतील प्रदूषणावर चर्चा करण्याची संधी चालून आली होती. 'रामजी' वगैरे विधेयके संमत झाल्यानंतरही विरोधकांनी सभागृहांमध्ये गोंधळ घातला. हा गोंधळ बघून लोकसभाध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करून टाकले. असे करण्याची खरोखरच आवश्यकता नव्हती. विरोधकांनी गदारोळ केला हे जरी खरे असले तरी, अर्धा-एक तास अगदी दोन तास सभागृह तहकूब करून वायूप्रदूषणावर चर्चा करता आली असती. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पहिल्या सत्रातच चर्चेला उत्तर दिले होते. गुरुवारच्या दुपारच्या सत्रातील संपूर्ण वेळ मोकळा होता, पण लोकसभाध्यक्षांनी विरोधकांच्या गोंधळावर खापर फोडून ही चर्चा टाळली. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये प्रदूषणावर चर्चा करण्याचा निर्णय झाला होता. विरोधी सदस्यांनी या विषयावर बोलण्यासाठी तयारी केली होती. आणि तरीही या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. शुक्रवारचा दिवससुद्धा हातात होता. दुपारच्या सत्रामध्ये खासगी विधेयकांवर चर्चा होते. शिवाय, अधिवेशनाचा तो शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे दुपारच्या सत्रात चर्चा झाली नसती, पण पहिल्या सत्रात ही चर्चा सुरू केली असती तर खासदार बोलले असते. जे बोलले ते निघून गेले असते. तशीही ही अल्पकालीन चर्चा होती. अशा चर्चा दोन-दोन दिवस चालत नाहीत. दिल्लीतील प्रदूषणावर विरोधकांनी नव्हे केंद्र सरकारने चर्चा होऊ दिली नाही हे वास्तव आहे.

गेल्या दोन दिवसांत यंदाच्या मोसमातील पहिली शीतलहर दिल्लीत आली आहे. शीतलहरीत प्रदूषणाच्या समस्येची तीव्रता अधिक जाणवू लागते. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाझियाबाद अशा 'एनसीआर'च्या पट्ट्यातील उंच इमारतींमधील रहिवाशांनी धुरक्यामुळे अदृश्य झालेल्या परिसराचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर अपलोड करण्यास सुरुवात केली आहे. व्हिडीओतील दृश्ये भयावह आहेत. धुक्यात वाट हरवणे रोमांचकारी असू शकते, धुरक्यात वाट हरवणे हे मात्र मृत्यूच्या दारात उभे करणारे असते. त्याचा अनुभव यंदाच्या मोसमात दोन आठवडे दिल्लीकर घेत आहेत.

याच काळात दिल्लीत लक्षवेधी आंतरराष्ट्रीय घटना होऊन गेल्या. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन दिल्लीत दोन दिवस राहून गेले. त्यांचे इतर कार्यक्रम बंद खोल्यांमध्ये झाले असतील, पण त्यांचे अधिकृत स्वागत राष्ट्रपती भवनाच्या मोकळ्या जागेतच झाले. प्रदूषित, काळ्या हवेत पुतिन यांनी मानवंदना स्वीकारली होती. नंतर ते यमुनेच्या किनारी राजघाटावर महात्मा गांधींच्या समाधीच्या दर्शनासाठी गेले होते. तिथेही त्यांच्यासाठी हीच हवा वाट पाहात होती. गेल्या आठवड्यात फुटबॉलपटू मेस्सी दिल्ली आला. श्वासही घेणे अशक्य होईल अशी स्थिती असताना त्याला आपण फुटबॉलच्या मैदानावर उतरवले होते. चाहते प्रचंड संख्येने स्टेडियमवर आले. त्यांनी मेस्सीचे स्वागत करण्याऐवजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांच्या नावाने लाखोली वाहिली. 'एक्यूआय'च्या घोषणा देऊन प्रदूषणाची आठवण करून दिली. गुप्ताजींना 'एक्यूआय' हा निर्देशांक आहे हे माहीत नाही, त्या गुणवत्ता निर्देशांकाला 'तापमापक' म्हणत होत्या. हवेचा ताप त्यांनी कसा मोजला हे त्यांनाच माहीत. दिल्लीकर भाजपच्या या नव्या नेतृत्वाकडे बघून हतबुद्ध झाले! वेगवेगळ्या देशांच्या दूतावास- उच्चायुक्त कार्यालयांनी आपल्या नागरिकांसाठी धोक्याच्या इशारा दिला. दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेने अतिघातक स्तर ओलांडला असल्याने आरोग्याच्या दृष्टीने सावध राहण्याचा इशारा विकसित देशांनी दिला. पुढील दोन दशकांमध्ये विकसित होऊ पाहणाऱ्या तमाम भारतीयांसाठी हा इशारा अत्यंत लाजिरवाणी आणि अपमानास्पद आहे.

आता दिल्लीत 'डबल इंजिन' सरकार असले तरी, ते नऊ महिन्यांपूर्वी आलेले आहे. त्यामुळे अल्पकाळात दिल्लीच्या हवेचे शुद्धीकरण करणे शक्य नाही असे म्हणत दिल्ली सरकारच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी हात वर केले आहेत. त्यांनी १५ वर्षे राज्य करणाऱ्या 'आप' सरकारला जबाबदार धरले, पण दिल्लीत राज्य सरकारला दोष देऊन उपयोग होत नाही. दिल्ली राजधानी असल्यामुळे आणि हे पूर्ण राज्य नसल्यामुळे प्रदूषणाची जबाबदारी केंद्र सरकारलाही घ्यावी लागेल. हे सरकार गेली ११ वर्षे केंद्रात आहे. काही वर्षे प्रदूषणाचे खापर पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांवर फोडले जात आहे, पण खुंट जाळले जात नाहीत तेव्हाही दिल्लीचे आकाश निरभ्र नसते, प्रदूषण कमी-अधिक प्रमाणात तेवढेच असते. दिल्लीत १०० 'एक्यूआय' फक्त करोनाकाळातच असेल, इथे तर १००० 'एक्यूआय' हा 'न्यू नॉर्मल' म्हणायची वेळ आली आहे. आता कुठे वाहनांना पीसीयूची सक्ती केली जात आहे. गेल्या तीन दिवसांत एक लाख वाहनांना प्रदूषण नियंत्रणाची पावती दिली गेली. दिल्लीतील प्रदूषण मुख्यत्वे वाहनांमुळे होते. हे शहर बाबूंचे आहे, त्यांना कारमधून फिरल्याशिवाय आत्मिक समाधान मिळत नाही. तो त्यांचा स्टेटस सिम्बल आहे. दिल्ली आणि परिसरातील बांधकामे, कारखाने प्रदूषणात भर घालत आहेत. दिल्लीत येणारी वाहने रोखावी लागतील, येणाऱ्यांवर मोठा कर लावावा लागेल. लंडनसारख्या शहरांमध्ये हाच उपाय लागू केला गेला. शहरातील वाहनांवर प्रदूषण नियंत्रणाचे कठोर निर्बंध लादावे लागतील. मेट्रो रेल्वेतील वाढती असह्य गर्दी बघता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करावी लागेल. हे सर्व उपाय फक्त राज्य सरकारच्या भरवशावर सोडता येणार नाहीत. त्यासाठी केंद्र सरकारला पावले उचलावी लागतील. दिल्ली हे एका शहराचे उदाहरण आहे, हीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात विस्तारणाऱ्या आणि चेहरामोहरा बदलत असलेल्या मुंबई वा इतर महानगरांची आहे. हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये निम्न-मध्यम शहरे महानगरे होत असताना प्रदूषण नियंत्रणाचा विचार फक्त दिल्लीपुरता सीमित करता येणार नाही. लखनऊमध्ये क्रिकेटचा सामना रद्द करावा लागला, त्यातून खरे तर मोठा धडा मिळालेला आहे. म्हणूनच प्रदूषण हा राजकीय मुद्दा झाला पाहिजे. पण, हिवाळी अधिवेशनात राजकारण्यांनी ही संधी गमवावी इतके हे कर्मदरिद्री कसे, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

अन्वयार्थ

ओडिशात आमदार तुपाशी, शिक्षक उपाशी

ओडिशातील भाजप सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारांच्या मासिक वेतन व भत्त्यांमध्ये जवळपास २०० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. या संदर्भातील विधेयक ओडिशा विधानसभेत सहमतीने मंजूर झाले. आता त्यावर टीका होऊ लागल्याने सरकार काढता पाय घेऊ पाहत असले, तरी त्यातून सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांचाही अप्पलपोटेपणा चव्हाट्यावर आला आहे.

आमदारांचे सध्याचे मासिक वेतन व भत्ते एक लाख ११ हजार रुपये एवढे आहेत. नव्या वाढीनुसार आमदारांना आता दरमहा ३ लाख ४५ हजार रुपये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे वेतन दरमहा ९८ हजारांवरून ३ लाख ७४ हजार, मंत्र्यांचे ९७ हजारांवरून ३ लाख ५८ हजार, विधानसभा अध्यक्षांचे ९७ हजार ५०० रुपयांवरून ३ लाख ६८ हजार रुपये एवढे घसघशीत वाढणार आहे. माजी आमदारांच्या निवृत्तिवेतनातही वाढ करण्यात आली. देशात महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या आमदारांना सर्वाधिक वेतन व भत्ते मिळतात. महाराष्ट्रात ही रक्कम दरमहा ३ लाख एक हजार रुपये असल्याची माहिती विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे, तर तेलंगणातील आमदारांना दरमहा साडेतीन लाखांच्या आसपास वेतन व भत्ते मिळतात. खासदारांना दरमहा अडीच ते तीन लाखांच्या आसपास वेतन व भत्ते मिळतात. याशिवाय अधिवेशन काळात तसेच समित्यांच्या बैठकांसाठी मिळणारा दैनंदिन भत्ता वेगळा. त्यामुळे आता देशात सर्वाधिक दरमहा वेतन ओडिशाच्या आमदारांना मिळणार आहे. ही वाढ राज्यात भाजप सरकार सत्तेत आले तेव्हापासून म्हणजे जून २०२४ पासून पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात करण्यात आली आहे. म्हणजेच गेल्या दीड वर्षाची फरकाची काही लाखांची रक्कमही त्यांना मिळणार आहे.

विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्यात आले तेव्हा बिजू जनता दल आणि काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला नाही. अपवाद फक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आमदाराचा. सर्वपक्षीय आमदारांनी या वाढीचे समर्थन केले. अन्य राज्यांच्या तुलनेत मागास असलेल्या ओडिशाची वित्तीय परिस्थिती फारशी चांगली नसताना लोकप्रतिनिधींच्या वेतन, भत्त्यांमध्ये एवढी वाढ करण्याच्या निर्णयाची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. या वाढीबद्दल टीका होऊ लागताच भाजप, बिजू जनता दलाच्या नेत्यांनी वाढ मागे घ्यावी म्हणून मागणी सुरू केली आहे. भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत आमदारांनीच मुख्यमंत्र्यांकडे ही वाढ रद्द करावी, अशी मागणी केली. माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी आपण नव्या वाढीनुसार वेतन व भत्ते स्वीकारणार नाही, असे पत्र पाठविले आहे. याला उशिरा सुचलेले शहाणपणच म्हणावे लागेल. या सर्वांनी विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्यात आले तेव्हा विरोध का केला नाही? विरोध होता तर पटनायक यांनी आपल्या आमदारांना सभागृहात विरोध करण्याचा आदेश देणे अपेक्षित होते. तसे काही झाले नव्हते.

विरोधाभास असा की, हे विधेयक मंजूर झाले त्याच दिवशी राजधानी भुवनेश्वरमध्ये शिक्षक, अंगणवाडी सेविका आदी वेतनवाढीसाठी आंदोलन करत होते. शिक्षक व अन्य घटकांच्या वेतनवाढीसाठी सरकारजवळ पैसे नाहीत, मात्र मंत्री, आमदारांच्या वेतनात २०० टक्के वाढ, तीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजूर करण्यासाठी निधी आहे? या प्रकारातून मुख्यमंत्री मोहन मांझी यांची राजकीय अपरिपक्वताच उघड झाली. सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसताना कोणाच्याही वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती. वाढीचा निर्णय घ्यायचाच होता तर सर्वच घटकांना खूश करणे अपेक्षित होते. पण आमदारांना खूश करण्याच्या नादात मुख्यमंत्र्यांचाच पाय खोलात गेला. कारण आता ओडिशा भाजपने आमदारांची वेतनवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. विधेयकाला अद्याप राज्यपालांची संमती मिळालेली नाही. एवढ्या टीकेनंतर आमदारांच्या वेतनातील वाढ अमलात येणे कठीण दिसते.

खासदार, आमदारांचे वेतन तसेच खासदार व आमदार निधी हा नेहमीच वादग्रस्त विषय ठरतो. खासदार वा आमदार निधी बंद करावा, अशी मागणी केली जाते. कारण त्यातून भ्रष्टाचाराला वाटा फुटतात, असा आरोप होतो. या वेतनवाढ प्रकरणातून आपण लोकांना उत्तरदायी आहोत हेच लोकप्रतिनिधी विसरल्याचे आणि आपले कुटुंब, नातेवाईक यापलीकडे त्यांना काहीही दिसत नसल्याचे स्पष्ट झाले. जनतेच्या रोषामुळे ओडिशामधील सत्ताधारी भाजपला माघार घ्यावी लागली हा जनतेचा व नागरी संघटनांचा विजयच म्हणावा लागेल.

विश्लेषण

संतोष प्रधान
santosh.pradhan
@expressindia.com

आमदारांची अपात्रता अमलात कशी आणली जाते?

> **माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे, पण म्हणून त्यांची विधानसभेची जागा रिक्त झाली, असे म्हणता येईल का? त्यासाठीची प्रक्रिया कोणती?**

शिक्षा ठोठावल्यास खासदार वा आमदार लगेचच अपात्र ठरतात का?

दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास खासदार वा आमदार अपात्र ठरण्याची तरतूद १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात होती, पण शिक्षेच्या विरोधात अपील करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना तीन महिन्यांची मुदत होती. त्यासंदर्भात सर्वसामान्यांना शिक्षा झाल्यास ती लगेचच अमलात येते, मग लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळा न्याय का, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. 'लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार' या गाजलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (४) अन्वये लोकप्रतिनिधींसाठी असलेली ही तरतूद रद्द केली. परिणामी, दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याच्या तारखेपासून खासदार किंवा आमदार अपात्र ठरतो. तशी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (३) मध्ये तरतूद आहे. वरिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास खासदारकी किंवा आमदारकी वाचू शकते. माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने वैध ठरविली. उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली. याचा अर्थ कोकाटे यांना लगेचच शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात जावे लागणार नाही. पण ते दोषी असल्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. परिणामी, कोकाटे हे आमदार म्हणून अपात्र ठरले आहेत. लालूप्रसाद यादव, जयललिता यांच्यासह अनेक खासदार, आमदार या निकालपत्रामुळे अपात्र ठरले आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक का असते?

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळाची शिक्षा झाल्यास खासदार वा आमदार आपोआपच अपात्र ठरतो. फक्त त्याच्या अपात्रतेवर लोकसभा वा विधानसभा अध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब करायचे असते. विधिमंडळ सचिवालयाने माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी रद्द झाल्यासंदर्भातील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यावरच ते प्रतिनिधित्व करीत असलेली विधानसभेची जागा रिक्त म्हणून घोषित करण्यात येईल. राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविताना लोकसभा सचिवालयाने काढलेल्या अधिसूचनेत 'सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याने परिणामस्वरूप केरळमधील वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे राहुल गांधी हे सदस्य म्हणून २३ मार्च २०२३ पासून अपात्र ठरले आहेत' असा उल्लेख होता. दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांना अशाच पद्धतीने अपात्र ठरविण्यात आले होते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने प्रसिद्ध केली होती. कोकाटे विधानसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरल्याची अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाला काढावी लागेल. यावर विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक ठरेल.

अपात्रतेची अधिसूचना काढण्यास विलंब केला जाण्यामागची कारणे काय?

सत्ताधारी पक्षाचा आमदार अपात्र ठरल्यास त्याला न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविता यावी म्हणून अनेकदा आमदार म्हणून अपात्र ठरल्याची अधिसूचना काढण्यास विलंब लावला जातो. उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी भाजपच्या दोन आमदारांना दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा होऊनही त्यांच्या अपात्रतेची अधिसूचना काढण्यास विलंब लावण्यात आला होता. समाजवादी पार्टीच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची अधिसूचना मात्र लगेच जारी करण्यात आली होती. सुरत न्यायायलाने शिक्षा सुनावताच लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब करणारी अधिसूचना काढली होती. तोच प्रकार काँग्रेसचे सुनील केदार यांच्याबाबत घडला होता.

दोषसिद्धीस स्थगिती मिळाल्यास पुढे काय?

दोषसिद्धीस न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास खासदारकी वा आमदारकी पुन्हा मिळू शकते. मोदी आडनावावरून केलेल्या भाष्यावरून सुरत न्यायालयाच्या शिक्षेनंतर राहुल गांधी यांना मार्च २०२३ मध्ये अपात्र ठरविण्यात आले होते, पण ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्यांच्या दोषसिद्धीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यामुळे राहुल गांधी हे खासदार म्हणून परत संसदेत कार्यरत झाले. लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादीचे खासदार मोहमद फैझल यांना हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्याची अधिसचून लोकसभा सचिवालयाने काढली. लोकसभेची ती जागा रिक्त झाल्याने निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीप मतदारसंघात पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. दरम्यानच्या काळात केरळ उच्च न्यायालयाने फैझल यांच्या दोषसिद्धीस स्थगिती दिली. परिणामी, त्या मतदारसंघातील पोटनिवडणूक निवडणूक आयोगाला रद्द करावी लागली होती. कोकाटे यांच्या दोषसिद्धीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्यांची आमदारकी वाचू शकते.

गुंतवणूकदाराची जोखीम अन् पडलेले प्रश्न

मार्ग सुबत्तेचा

तृप्ती राणे

माझ्या कामानिमित्त मला अनेक गुंतवणूकदार भेटत असतात. कधी खूप सधन पण शेअर बाजारातील जोखीम न आवडणारे, तर कधी बेताची परिस्थिती असून व्यवस्थित जोखीम क्षमता असणारे, तर कधी बिघडलेले आर्थिक समीकरण असतानासुद्धा अवाजवी जोखीम घेणारे. काही ठिकाणी परिस्थिती बदलल्यामुळे वाढीव जोखीम घेतली गेलीय तर कधी अति भीतीमुळेसुद्धा जोखीम क्षमता कमी झाली आहे. एक अजून गोष्ट सुद्धा होते, स्वतःच्या पैशांवर लोक जोखीम घेत नाहीत, पण लॉटरी लागली किंवा कोणी दुसऱ्याने पैसे दिलेत म्हणून त्यावर जास्त जोखीम घ्यायला लोक तयार असतात. या सर्वांचा अभ्यास करताना जे प्रश्न मला अजूनही पडतात आणि त्यावर माझं विश्लेषण आजच्या या लेखातून मी मांडणार आहे. तर हे प्रश्न असे आहेत-

- जोखीम म्हणजे नक्की काय ?
- जोखीम घ्यायलाच हवी का ?
- जोखीम कोणी घ्यावी ?
- जोखीम किती घ्यावी ?
- जोखीम टाळता येते का ?
- जोखीम व्यवस्थापन कसं करावं ?

आपण या सर्व प्रश्नांची उत्तरे बघू या. खरं तर या आधीसुद्धा मी या विषयावर लिहिलं आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती बघता मला पुन्हा एकदा हा विषय हाताळावासा वाटला आणि तोसुद्धा थोडा अजून खोलवर. तर चला परत एकदा आपला अभ्यास सुरू करू या.

● जोखीम म्हणजे नक्की काय ?

सर्वसामान्य व्यक्तीला जोखीम म्हटलं की, फक्त नुकसान हा शब्द लक्षात येतो. अनेकदा याच्यामागे भीती, अज्ञान आणि अनास्था ही कारणं असू शकतात. परंतु जोखीम म्हणजे फक्त नुकसान नसून एखाद्या कामातून अपेक्षित यश न मिळता नुकसान होण्याची शक्यता असते. उदाहरण घ्यायचं तर रस्त्यावरून चालताना अपघात होऊ शकतो, म्हणून रस्त्यावरून चालणं ही जोखीम आहे. पण म्हणून आपण रस्त्यावरून चालणं बंद करतो का ? तसंच प्रत्येक आर्थिक व्यवहारात जोखीम ही असतेच, नोकरी करतोय पण नियमित पगार मिळणार का ?, व्यवसाय करतोय तर फायदा होणार का?, गुंतवणूक करतोय ती निवृत्तीमध्ये पुरणार का ? जिथे कुठे काहीतरी कमी होऊ शकतं - आयुर्मान, स्वास्थ्य, मिळकत, परतावे, पुरवठा तिथे तिथे जोखीम असते ! कधी ती दिसते (मृत्यू, आजारपण, नुकसान), कधी ती भासते (कमी होणारी बचत, वाढणारे खर्च) तर कधी ती लक्षातसुद्धा येत नाही (महागाई, निवृत्ती निधीतील पैसे कमी पडणं).

● जोखीम घ्यायलाच हवी का ?

मुळात आपलं आयुष्य आणि जोखीम हे एकत्रच असतात. जन्माला आलं की, आजारपण आणि मृत्यूची जोखीम, पैसे कमावले की, त्यांना सांभाळणं आणि वाढवणं याची जोखीम, मालमत्ता जमा केली की तिची सुरक्षा, देखरेख याची जोखीम. साधारणपणे माणसाला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात जोखीम पत्करावीच लागते. परंतु या सर्वमान्य जोखमीच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण जोखीम घेतो, तेव्हा हा प्रश्न नक्कीच विचारावा की खरंच एखादी वाढीव जोखीम घेण्याची गरज आहे का ? जर आपली नोकरी किंवा व्यवसाय व्यवस्थित कमाई करून देत असेल, तर मग गुंतवणुकीत किती जोखीम घ्यावी ? नियमित पगार ज्यांना मिळतो, त्यांनी आपल्या क्षमतेनुसार आणि ध्येयानुसार जोखीम घ्यावी, परंतु अनियमित मिळकत असणाऱ्यांनी मात्र गुंतवणूक करताना पहिली जोखीम कमी ठेवून आपत्कालीन निधी साठवावा आणि पुढे हळूहळू जोखीम वाढवावी. निवृत्त होऊ पाहणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या पुढील ३-५ वर्षांच्या खर्चाची तरतूद करताना जोखीम घेऊ नये. परंतु गुंतवणूक निधी पुरणार की नाही, हे वेळोवेळी तपासून गरजेनुसार जोखीम घ्यावी. महागाई तर सर्वांनाच सोसावी लागते, तेव्हा पोर्टफोलिओला महागाईपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी वेळीच योग्य ती जोखीम घेऊन बदल करणं आवश्यक आहे.

● जोखीम किती घ्यावी ?

आधी म्हटल्याप्रमाणे, जोखीम ही असतेच. आपल्या मिळकतीनुसार, वयोमानानुसार, आयुष्यातील इतर प्रसंगानुसार जोखीम बदलत असते. आपल्या गरजा नीट कळल्या आणि त्या पुऱ्या करताना कोणती जोखीम कधी वाढू शकते आणि किती असू शकते हे कळलं की पुढे तिचं व्यवस्थापन नीट होऊ शकतं. हे समीकरण प्रत्येकाचं वेगळं असतं आणि आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर वेगळं असतं. आयुष्यात मोठे निर्णय घेताना त्यांचा कोणता आर्थिक परिणाम कोणावर आणि किती होऊ शकतो हे वेळोवेळी पाहावं.

● जोखीम टाळता येते का ?

गुंतवणुकीच्या बाबतीत म्हणायचं तर, प्रत्येक पर्यायाला कोणती ना कोणती जोखीम लागू पडते. शेअर बाजाराची जोखीम, महागाईची जोखीम, चोरांची जोखीम, नैसर्गिक आपत्तीची जोखीम, गुंतवलेले पैसे वेळेवर आणि पूर्णपणे परत न मिळण्याची जोखीम. आपल्या ध्येयानुसार कोणती जोखीम टाळायची हे ठरतं. आता बंगला हवा असेल तर सुरक्षारक्षक तर लागणार. जिथे एका वर्षात पैसे हवे आहेत, तिथे शेअरबाजाराची जोखीम टाळावी. जिथे पैसे वेळेवर हवे आहेत, तिथे अधिक व्याजामागे पण वाढीव जोखीम घेऊन उपयोग नाही, कारण असे पैसे बुडण्याची शक्यता जास्त होते. प्रत्येक वेळी ध्येयानुसार आणि त्याला साजेलशा गुंतवणुकीनुसार कोणती जोखीम घ्यायची आणि कोणती टाळायची हे ठरवावं.

● जोखीम व्यवस्थापन कसं करावं ?

आपण किती वाढीव जोखीम घ्यायची, कोणती टाळायची हे आणि कोणती हस्तांतरित करायची हे समजणं म्हणजे जोखीम व्यवस्थापन. जमेल तितकी काळजी घेऊन नुकसान टाळणं, जमेल तितकी जोखीम स्वतः घेणं आणि हे करून पण जी जोखीम राहते तिला दुसऱ्याला हस्तांतरित करणं. आरोग्यविमा घेतला तरीसुद्धा तब्येत चांगली ठेवणं हे केव्हाही उपयोगी. आयुर्विमा घेतला म्हणून काही आपण जिवाचा धोका पत्करत नाही. जिथे कर्ज, भविष्यातील खर्च आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या असतील तिथे सुरुवातीच्या काळात जोखीम व्यवस्थापन जास्त महत्त्वाचं असतं. पुढे चांगला पोर्टफोलिओ तयार झाला आणि पुरून उरेल असा विश्वास वाटला की जास्त जोखीम घेता येऊ शकते. जोखीम व्यवस्थापनाचे खर्च असतात, तेव्हा ते किती आहेत आणि त्याने नक्की किती नुकसानभरपाई होणार आहे, हे लक्षात घेऊन मग विमा घ्यावा. पोर्टफोलिओचं जोखीम व्यवस्थापन करताना आपण काय घेतलं आहे, त्याचा पोर्टफोलिओवर किती आणि कधी परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार प्रत्येक गुंतवणुकीचं प्रमाण ठरवावं. आपल्या नुकसानीच्या मर्यादा आधीच ठरवून त्या नेटाने पाळाव्यात. सिर सलामत तो पगडी पचास ही म्हण इथे लागू पडते. पैसे बुडाले नाहीत तर ते चांगल्या पद्धतीने वाढवता येतील. पसारा नसला, तर पोर्टफोलिओचं नीट व्यवस्थापन होऊ शकेल.

तेव्हा कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात जोखीम ही असणारच. तिला योग्य वेळी ओळखून, नीट समजून आणि चांगलं व्यवस्थापन करून आपण आपल्या कमावलेल्या पैशांचं, जमवलेल्या मालमत्तेचा आनंद स्वतः तर घेऊ शकतोच पण पुढे इतरांनासुद्धा देऊ शकतो. स्वतःला भीतीतून मुक्त करा, ज्ञान मिळवा, योग्य सल्ला घ्या आणि रास्त खर्चात जमेल तेवढं जोखीम व्यवस्थापन करा.

जोखीम कोणी घ्यावी ?

ज्याला भीती आहे नुकसानीची किंवा पैसे कमी पडण्याची, त्यांनी जोखीम घ्यावी. पैसे कमीच पडणार नसतील किंवा नुकसान झालं तरी चालेल, अशा व्यक्तींनी जोखीम घ्यावी. इतरांनी जोखीम व्यवस्थापन करावं. ज्यांना आजारपणाच्या खर्चाची सोय करायची असेल त्यांनी आरोग्यविमा घ्यावा, ज्याच्यावर आर्थिक जबाबदारी असेल त्याने आयुर्विमा घ्यावा, जिथे पैसे पुरवायचे असतील, त्यांनी गुंतवणूक व्यवस्थापन करावं.

लेखिका सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार
trupti_vrane@yahoo.com

किंतु - परंतु मधील वाटचाल

ससा कासवाची गोष्ट

आशीष ठाकूर

गेल्या लेखात निफ्टी आलेखावर ३० सप्टेंबर २०२५चा नीचांक २४,५८७ आणि ७ नोव्हेंबरचा नीचांक २५,३१८ अशा या दोन नीचांकांचे बिंदू सांधत जी 'कल निर्धारण रेषा' आपण आखली होती. त्या 'कल निर्धारण रेषेची' किंमत २६,०५० येत होती. आताच्या घडीला निफ्टी निर्देशांकावर 'महत्त्वाचा केंद्रबिंदू स्तर' हा २६,०५० हाच आहे. अर्थात तेजी-मंदीची मानसिक धारणा ही २६,०५० च्या स्तरावर बेतलेली आहे. निफ्टी निर्देशांक जेव्हा २६,०५०च्या स्तरावर असतो तेव्हा तेजीची वाट २६,३००... २६,५०० ते २६,८०० पर्यंत भिडणारी भासते. पण जेव्हा निफ्टी निर्देशांक २६,०५०च्या खाली असतो तेव्हा मात्र ही तेजीची वाट धुक्यात हरवल्यासारखी वाटते. या वाक्यचे प्रत्यंतर सरलेल्या सप्ताहात आले. निफ्टी निर्देशांक २६,०५० चा स्तर पार करण्यास वारंवार अपयशी ठरत असल्याने, मनात किंतु उद्भवत होता. परंतु ही घसरण अतिशय मामुली स्वरूपात असल्याने मागील लेखात नमूद केलेल्या निफ्टी निर्देशांकाचे २५,८००चे खालचे लक्ष्य सरलेल्या सप्ताहातील गुरुवारच्या सत्रात २५,७२७ चा नीचांक मारत साध्य केले गेले.

सेन्सेक्सबाबतीत मंदीच्या चक्राचा अभ्यास करता, सेन्सेक्सवर सरासरी २,५०० ते ३,००० अंशांची घसरण होते. या घसरणीचा कालावधी पाच ते दहा कामकाजीन दिवसाचा असतो. जसे की सेन्सेक्सने २१ ऑगस्टला ८२,२३१ वरून गाठलेला २९ ऑगस्टचा ७९,७४१ अंशांचा नीचांक. ही घसरण २,४९० अंशांची होती आणि घसरणीचा कालावधी पाच कामकाज दिवस होता.

दुसरे उदाहरण, १८ सप्टेंबरच्या ८३,१४१च्या उच्चांकावरून, १ ऑक्टोबरला गाठलेला ८०,१५९चा नीचांक. ही घसरण २,९८२अंशांची आणि घसरणीचा कालावधी नऊ दिवस होता.

तिसरं उदाहरण, २३ ऑक्टोबरचा ८५,२९०चा उच्चांक ते ७ नोव्हेंबरचा ८२,६७०चा नीचांक. ही घसरण २,६२० अंशांची आणि घसरणीचा कालावधी १० दिवस होता.

आता वरील गणिती कोष्टकांचा ल.सा.वि.घेता, सेन्सेक्सवर २,५०० ते ३,००० अंशांची घसरण आणि घसरणीचा कालावधी ५ ते १० दिवस येतो. याच्या तुलनेत १ डिसेंबरला ८६,१५९ चा उच्चांक नोंदवत, ३ डिसेंबरला ८४,७६३ पर्यंत घसरण होत, पुन्हा निर्देशांकात सुधारणा झाली. ही घसरण अवघी १,३९६ अंशांची आणि ती दोन दिवसात झाली. ही तुलनात्मक आकडेवारी हे मंदीचे चक्र नसून, सशक्त तेजीची साक्ष देणारी आहे.

या आठवड्यात सेन्सेक्सने ८५,८०० चा स्तर पार करून, हा स्तर सातत्याने पाच दिवस टिकवल्यास सेन्सेक्सचे वरचे लक्ष्य ८६,१७० ते ८६,५०० आणि द्वितीय वरचे लक्ष्य ९०,००० असेल. अन्यथा ८५,८०० चा स्तर पार करण्यास आणि ८४,००० चा स्तर राखण्यासही सेन्सेक्स अपयशी ठरल्यास, सेन्सेक्सचे खालचे लक्ष्य ८२,७०० असेल.

निफ्टी, सेन्सेक्स आणि बँक निफ्टी या तिन्ही निर्देशांकाचा भविष्यकालीन आढावा घेता, निफ्टी निर्देशांकांने २६,०५० हा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू स्तर सातत्याने राखल्यास निफ्टी निर्देशांकाचे प्रथम वरचे लक्ष्य हे २६,३०० ते २६,५०० आणि द्वितीय वरचे लक्ष्य २६,८०० ते २७,००० असेल. ही नाण्याची एक बाजू झाली. निफ्टी निर्देशांक सातत्याने २६,०५०च्या खाली राहिल्यास निफ्टी निर्देशांकाचे प्रथम खालचे लक्ष्य २५,७०० ते २५,५०० आणि द्वितीय खालचे लक्ष्य २५,२०० असेल.

बँक निफ्टी निर्देशांकावर ६०,१०० हा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू स्तर असून हा स्तर या निर्देशांकाने सातत्याने राखल्यास त्याचे प्रथम वरचे लक्ष्य हे ६०,५०० ते ६१,००० आणि द्वितीय वरचे लक्ष्य ६२,००० असेल. ही नाण्याची एक बाजू झाली. बँक निफ्टी निर्देशांक सातत्याने ५८,८००च्या खाली राहिल्यास त्याचे प्रथम खालचे लक्ष्य ५८,१०० असेल.

सेन्सेक्सवर ८४,४०० हा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू स्तर असून हा स्तर त्याने सातत्याने राखल्यास सेन्सेक्सचे प्रथम वरचे लक्ष्य हे ८५,८०० ते ८६,२०० आणि द्वितीय वरचे लक्ष्य ९०,००० ते ९३,००० असेल. ही नाण्याची एक बाजू झाली. सेन्सेक्स सातत्याने ८४,४००च्या खाली राहिल्यास, त्याचे प्रथम खालच लक्ष्य ८२,७००, द्वितीय खालचे लक्ष्य ८१,३०० असेल.

अस्वीकृती : शेअर बाजारातील व्यवहार हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहेत. अंदाज चुकल्यास मुद्दल गमावण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी 'स्टॉप लॉस' आणि इच्छित लक्ष्य या संकल्पनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

बाजार अस्थिरतेत 'एसआयपी' थांबवावी का ?

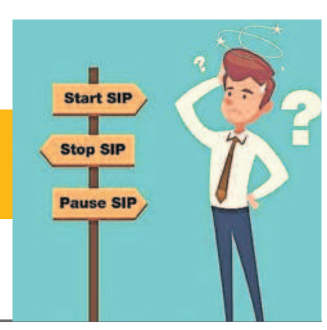

फंड जिज्ञासा

कौस्तुभ जोशी

म्युच्युअल फंडात शिस्तशीर गुंतवणुकीचा मार्ग असलेल्या 'सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन' अर्थात 'एसआयपी'च्या माध्यमातून पैसे गुंतवले तर फायदा होतो असे म्हटले जाते. मी गेल्या दीड वर्षापासून एकरकमी आणि दर महिन्याला पैसे गुंतवतो आहे. पण चांगला परतावा मिळत नाहीये, तर माझी गुंतवणूक चुकते आहे का ? एसआयपी थांबवू का ?

-भूषण

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या बऱ्याच गुंतवणूकदारांना गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या गुंतवणुकीची चिंता वाटते आहे. २०२० या वर्षात करोना संकटामुळे शेअर बाजार दणकून आपटले, त्या वेळी बऱ्याच गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. वर्षभरानंतर जेव्हा शेअर बाजारात तेजी निर्माण झाली, तेव्हा सगळ्यांनाच उत्तम परतावा मिळाला. ज्यांनी दहा वर्षांपासून सलग गुंतवणूक केली आहे, त्यांना तर मधल्या एक-दीड वर्षात आलेल्या पडझडीमुळे स्वस्तात युनिट मिळून 'एसआयपी' तंत्राचा फायदा झाला. त्यामुळे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांचा ओघ वाढला.

म्युच्युअल फंड म्हणजे हमखास पैसे ?

फंडात गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड म्हणजे हमखास पैसे देणारे साधन आहे, असा विचार करून गुंतवणूक करायला लागले. समाजमाध्यमांवरील व्हिडीओ पाहून गुंतवणुकीचे स्वतःच निर्णय घेणाऱ्यांचा यात मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता, असा आमचा अनुभव आहे. मागच्या पाच वर्षांतील फंडांनी दिलेले घसघशीत परतावे पाहून लोकांनी 'हाच तो माझा फंड' असा विचार मनात ठेवून पैसे गुंतवायला सुरुवात केली.

मिडकॅप, स्मॉलकॅपची मोहिनी

जेव्हा शेअर बाजार अस्थिर असतात, त्या वेळी कायमच लार्जकॅप म्युच्युअल फंड आणि इक्विटी हायब्रिड फंड योजना गुंतवणुकीसाठी त्यातल्या त्यात महत्त्वाच्या समजल्या जातात. पण गेल्या तीन वर्षांतला मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप फंडातील गुंतवणुकीचा वाढता आकडा पाहिल्यास लोकांना त्यांची भुरळच पडली आहे, हे स्पष्ट दिसते. अनेक नवख्या गुंतवणूकदारांच्या समजा पाच फंडात गुंतवणुकी सुरू असतील, तर त्यातील चार फंड मिड आणि स्मॉलकॅप प्रकारचे आहेत असेही बऱ्याचदा दिसते.

अस्थिरतेच्या वर्षातील परतावे

मागच्या वर्षीपासून जागतिक भू-अर्थकारणात चमत्कारिक घडामोडी घडू लागल्या. युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्ध थांबेल, अशी एक शक्यता निर्माण झालेली असताना ते थांबले तर नाहीच वर आणखी चिघळू लागले. दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेभरवशाची धोरणे राबवायला सुरुवात केल्यामुळे जागतिक शेअर बाजारावर त्याचा स्पष्ट परिणाम दिसायला लागला. देशांतर्गत भांडवली बाजारात दर महिन्याला काही हजार कोटी रुपयांचा निधी म्युच्युअल फंडामार्फत गुंतवला जात आहे. मात्र देशांतर्गत भांडवली बाजारात तेजीची दारे खुली होण्यासाठी खरी गरज आहे ती परदेशी गुंतवणूकदारांची. गेल्या एक वर्षाचा परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणजेच 'एफआयआय' गुंतवणुकीचा आढावा घेतल्यास, त्यांनी पैसे भारतातून काढून दुसऱ्या ठिकाणी गुंतवले आहेत हे स्पष्ट दिसते.

याचा थेट परिणाम अपरिहार्यपणे मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअरच्या घसरणीवर झाला. त्यामुळे एकेकाळी 'चमकते तारे' असलेले मिड आणि स्मॉलकॅप फंड आता बँकेच्या मुदत ठेवींइतकेही परतावे देत नाहीत, अशी तक्रार गुंतवणूकदारांकडून सुरू झाली.

जोखीम कालावधी आणि गुंतवणूक निर्णय

ज्यांनी लोभी मनोवृत्तीने मागच्या एक दीड वर्षात गुंतवणूक सुरू केली असेल आणि कमी वेळात म्युच्युअल फंडातून जास्त पैसे मिळतील या मानसिकतेने पैसे गुंतवले असतील, त्यांना त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाची किंमत चुकती करावी लागणार आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे ज्या गुंतवणूकदारांनी पाच ते सात वर्षांच्या गुंतवणूक ध्येयासह आपली गुंतवणूक गेल्या दोन वर्षांत सुरू केली असेल त्यांनी आपली गुंतवणूक अजिबात थांबवू नये किंवा विकूसुद्धा नये.

'एसआयपी'मध्ये पडत्या बाजारात किंवा अस्थिर बाजारात गुंतवणूक थांबवणे हा इलाज नसून उपाय जेवढे मिळतील तेवढे युनिट जमा करून पोर्टफोलिओ वाढवणे हा आहे.

रणनीती कशी असावी ?

तुम्ही गेल्या वर्ष दीड वर्षाचा अंदाज घेऊन गुंतवणूक करणार असाल, तर ते शहाणपणाचे लक्षण नाही. म्युच्युअल फंडाच्या संकल्पनेमध्येच असे म्हटले आहे की, फंडातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. म्हणजेच भविष्यकालीन दृष्टिकोनातून आपल्या फंडाचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे हे लक्षात ठेवा.

दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी गुंतवणूक सुरू केली असेल तर त्या रणनीतीमध्ये कुठलाही बदल करायची गरज नाही. मात्र दर दोन वर्षांनी तुम्ही ज्या फंडात गुंतवणूक करत आहात त्या फंडाचा आढावा घ्यायला विसरू नका.

(म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीविषयी तुमच्या अडचणी, प्रश्न थेट आम्हाला ईमेल- arthmanas@expressindia.com द्वारे कळवा)

डिस्क्लेमर: म्युच्युअल फंड योजना आणि त्यातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे, योजनेविषयीचे दस्तऐवज वाचून आणि गुंतवणूक सल्लागाराच्या माध्यमातूनच गुंतवणूक करावी.

विदा क्षेत्रातील बँकांची तंत्र-साथी

माझा पोर्टफोलिओ

अजय वाळिंबे

वर्ष १९९५ मध्ये स्थापन झालेली डायनाकॉन्स सिस्टम्स अँड सोल्यूशन्स लिमिटेड आयटी पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध सेवा पुरवते. कंपनी विदा केंद्र (डेटा सेंटर) आणि क्लाउड, व्यवस्थापित सेवा, डिजिटल कार्यस्थळ, सिस्टम्स इंटिग्रेशन, नेटवर्क आणि सुरक्षा, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि सुरक्षित शहर विभागासंबंधित उपाय आणि सेवा पुरवते. कंपनी डेटा सेंटर आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क-सुरक्षा आणि कार्यक्षेत्र या तीन प्रमुख विभागांमध्ये सेवा पुरवण्यासाठी आघाडीच्या जागतिक तंत्रज्ञान भागीदारांसोबत सहयोग करते. यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट, सिस्को, डेल टेक्नॉलॉजीज, व्हीएमवेअर, एचपीई, लेनोव्हा, ओरॅकल या कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपनीचा बहुतांश महसूल (९९ टक्के) हा सिस्टम इंटिग्रेशनमधून येतो. कंपनीच्या भारतात २५० हून अधिक शाखा आहेत.

मुख्य व्यवसाय आणि सेवा:

● **डेटा सेंटर आणि क्लाउड सोल्यूशन्स:** बॅकअप, डीआर आणि ऑप्टिमायझेशन टूल्ससह एचसीआय, एसडीएस, व्हर्च्युअलायझेशन आणि हायब्रिड/मल्टी-क्लाउड सेटअप वापरून एंटरप्राइझ आयटीचे आधुनिकीकरण करते. प्रमुख बीएफएसआय आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना सेवा देते. सिस्टम इंटिग्रेशन महसुलात प्रमुख योगदानकर्ता.

● **नेटवर्क आणि सुरक्षा पायाभूत सुविधा:**

सुरक्षित, स्केलेबल कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी एसडी-डब्ल्यूएएन, पुढच्या पिढीचे अर्थात नेक्स्ट-जेन फायरवॉल्स, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट, एंडपॉइंट सिक्युरिटी आणि एसआयईएम ऑफर करते. नियंत्रित क्षेत्रांमध्ये मजबूत उपस्थिती; स्टेट बँकेच्या ७,०००-शाखा एसडी-डब्ल्यूएएन ड्राइव्ह प्रकल्प महसूलसारख्या मोठ्या तैनाती.

● **वर्कप्लेस सोल्यूशन्स:**

व्हीडीआय, मायक्रोसॉफ्ट ३६५, डिव्हाइस लाइफसायकल व्यवस्थापन, व्यवस्थापित प्रटिं आणि डीईएक्स टूल्सद्वारे डिजिटल कार्य वातावरण सक्षम करते.

● **व्यवस्थापित सेवा:**

सहकारी बँकांसाठी एनओसी/एसओसी ऑपरेशन्स, आयएमएस, ब्रेक-फिक्स सपोर्ट, कर्मचारी वाढ आणि इतर क्षेत्र-विशिष्ट उपाय प्रदान करते.

कंपनी बीएफएसआय, पीएसयू तसेच इतर प्रमुख क्षेत्रांमधील ग्राहकांना सेवा देते. कंपनीच्या प्रमुख ग्राहकांत रिझर्व्ह बँक, आयसीआयसीआय बँक, आयडीबीआय बँक, मुंबई महानगरपालिका, फेसबुक इंडिया, उबर, महानगर गॅस, म्हाडा, फोक्स वागेन, मर्क, फायझर, सीएट टायर्स, कोफोर्ज लिमिटेड इ. विविध क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. प्रमुख पुरवठादारांमध्ये रेडिंग्टन लिमिटेड आणि इंग्राम मायक्रो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

मजबूत कार्यादेश

कंपनीच्या कार्यादेशामध्ये डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी कॅनरा बँकेकडून २८० कोटी रुपये, कोअर बँकिंग अद्ययावत करण्यासाठी नाबार्डकडून २३३ कोटी रुपये, डिजिटल वर्कप्लेस सोल्यूशन्ससाठी एलआयसीकडून १३८.४४ कोटी रुपये, खासगी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून ११९ कोटी रुपये, सीबीएएससाठी नाबार्डकडून १०८ कोटी रुपये, एसडी-वॅनसाठी स्टेट बँकेकडून ६२.९८ कोटी रुपये, अतिरिक्त नाबार्ड कार्यादेशामध्ये ५१.२८ कोटी रुपये तसेच इतर करारांचा समावेश आहे. सीटीएस स्कॅनरसाठी बँक ऑफ बडोदाकडून १८.८४ कोटी कार्यादेश तर नुकतीच जम्मू अँड कश्मीर बँकेकडून ९८५१ डेस्कटॉप पुरवण्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा कार्यादेश प्राप्त झाला आहे.

डायनाकॉन्सचे दुसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर झाले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे कंपनीने उत्तम कामगिरी करून दाखवली आहे. सप्टेंबर २०२५ अखेर संपलेल्या तिमाहीसाठी कंपनीने ३५२ कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर २३ कोटी रुपयांचा नक्त नफा कमवला आहे. गेल्या वर्षाच्या तिमाहीच्या तुलनेत तो २४ टक्क्यांनी अधिक आहे. कंपनीचे कार्यादेश आणि सेवांचा विस्तार पाहता आगामी काळातदेखील डायनाकॉन्सकडून भरीव कामगिरीची अपेक्षा आहे. सध्या ९०० रुपयांच्या आसपास असलेला हा शेअर २-३ वर्षात चांगला परतावा देऊ शकेल.

शेअरबाजारातील अनिश्चितता पाहता हा शेअर सुचवलेल्या किमतीपेक्षा कमी भावात मिळू शकतो, म्हणून प्रत्येक मंदीत तसेच टप्प्याटप्प्याने शेअर खरेदीचे धोरण ठेवावे.

Stocksandwealth@gmail.com

सूचना : १. प्रस्तुत लेखामध्ये सुचविलेल्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये लेखकाची वा त्याच्या जवळच्यां नातेवाईकांची (उपलब्ध माहितीप्रमाणे) कुठलीही गुंतवणूक नाही किंवा असल्यास ती कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलाच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. तसेच सुचविलेल्या कंपनीशी लेखकाचा कुठलाही संबंध नसून त्याने कंपनीकडून कुठलेही मानधन अथवा भेटवस्तू घेतलेली नाही. २. लेखात सुचविलेल्या कंपनीचे संशोधन हे वाचकांच्या माहितीसाठी असून, प्रत्यक्ष कंपनीच्या शेअरमधील गुंतवणूक वाचकांनी स्वतःच्या जोखमीवर वा सल्लागाराच्या सल्ल्याने करावी. ३. वरील लेख केवळ विश्लेषणात्मक संशोधन असून तो गुंतवणूक सल्ला नाही.

डायनाकॉन्स सिस्टम्स अँड सोल्यूशन्स लिमिटेड (बीएसई कोड -५३२३६५)

शुक्रवारचा बंद भाव : **रु. ९७१/-**

वर्षभरातील उच्चांक/ नीचांक : **रु. १६१५/८२५**

बाजार भांडवल : **रु. १२३६ कोटी**

भरणा झालेले भागभांडवल

१२.७३ कोटी

शेअर होल्डिंग पॅटर्न (%)

प्रवर्तक	६०.९५
परदेशी गुंतवणूकदार	०.२८
बँका/ म्यु. फंड/ सरकार	०.११
इतर/ जनता	३८.६५
डेट इक्विटी गुणोत्तर	०.६४%

वेबसाइट : www.dynacons.com

संक्षिप्त विवरण

- शेअर गट : स्मॉल कॅप
- प्रवर्तक : शिरीष अंजारिया
- व्यवसाय क्षेत्र : माहिती तंत्रज्ञान
- पुस्तकी मूल्य : रु. २१४.१
- दर्शनी मूल्य : रु.१०/-
- गतवर्षीचा लाभांश : —%

शेअर शिफारशीचे निकष

- प्रति समभाग उत्पन्न : ६२ रु.
- पी/ई गुणोत्तर : १५.७
- समग्र पी/ई गुणोत्तर : ३०.५
- इंटरेस्ट कव्हरेज गुणोत्तर : ६.५१
- बीटा : १.९
- गुंतवणूक कालावधी : २४ महिने
- रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉइड : ३९.२%

PREMIUM NEWSPAPER ACCESS💥

RECRUITING NEW MEMBERS AFTER MANY MONTHS

🎈Access to all this In Just 19 Rupees [lifetime Validity]

📚Indian Newspapers:

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

Click below to

Join

📚International Newspapers Channel

📚 Magazine Channel (National & International)